नीलू प्रिंटिंग प्रेस
हर प्रकार की वेब ऑफसेट एवं रंगीन या बहुरंगीन प्रिंटिंग के लिए नोएडा में एक मात्र स्थान
ई 33, सेक्टर 7 नोएडा (यूपी)
फोन नं. : 9811157562

फरीदाबाद हरियाणा का नंबर 1 समाचार पत्र

भेदी नज़र

संस्थापक : स्वाधीनता सेनानी सुखवासी लाल शर्मा (ब्रह्मलीन)

ई- पेपर पढ़ने के लिए लॉगऑन करें- www.bhedinazar.com

दिल्ली, शुक्रवार 18 सितंबर 2026

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश का प्रमुख हिन्दी दैनिक

आवश्यकता है
1- न्यूज एडीटर
2- एकाउन्टेट
3- मार्केटिगं एग्जीक्यूटिव (फार एडवर्टाइजमेंट)
4- चपरासी
सर्म्पक करें- 9811157562
समय: 3:00 से 5:00 PM

वर्ष : 23 अंक : 155 | Email : bhedinazardaily@gmail.com | RNI NO. DEL/HIN/2004/13528 | Postal REG. No. HR (FBD) -260/2023/25 | पृष्ठ : 12 मूल्य : 1 रुपये

संक्षिप्त समाचार

चंद्रशेखरन 5 साल और टाटा संस के चेयरमैन रहेंगे

बोर्ड ने कार्यकाल बढ़ाया, पिछले महीने नोएल टाटा से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 2032 तक बढ़ा दिया गया है। टाटा संस लिमिटेड के बोर्ड ने गुरुवार को नया कार्यकाल देने को मंजूरी दी। कंपनी को शेयर मार्केट में उतारने का भी निर्णय लिया गया है। अभी चंद्रशेखरन का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वे फरवरी 2027 में रिटायर होने वाले थे। चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त 2026 को इस्तीफा दे दिया था। तब नोएल टाटा से मतभेद और ट्रस्ट में खींचतान की वजह बनी थी। एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को अभी सालाना आम बैठक में मंजूरी मिलनी है, जिसमें टाटा ट्रस्ट की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ट्रस्ट के बोर्ड सदस्य नोएल टाटा फैसले के खिलाफ हैं, जबकि वेनु श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया है।

महाराष्ट्र सरकार की सीक्रेट डिप्लोमेसी और 20 दिन बाद खत्म हुआ मनोज जारांगे का अनशन

मुंबई (एजेंसी)। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जारांगे पाटिल ने गुरुवार, 17 सितंबर को अपना 20 दिन का अनशन खत्म कर दिया है। मनोज जारांगे ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि अगर तीन महीने में मराठा आरक्षण पर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे अपना

विरोध प्रदर्शन राजधानी मुंबई तक ले जाएंगे। पेरिस में इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और जारांगे पाटिल के सहयोगियों के बीच बातचीत कराने में मदद की। मनोज जारांगे पाटिल के अनशन को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें उदय सामंत ने पेरिस से ही तालमेल बैठाया। उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से कई बार बात की। सूत्रों के मुताबिक, कुल सात बार बातचीत हुई। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें वे खुद, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और बीजेपी नेता प्रसाद लाड शामिल रहे।

बंगाल एसटीएफ को बड़ी सफलता

शीर्ष माओवादी नेता असीम मंडल गिरफ्तार, पैसे जुटाने के लिए पहुंचा था ससुराल

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। करीब दो करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी नेता असीम मंडल उर्फ आकाश को कोलकाता पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने गुरुवार तड़के पूर्व मेदिनीपुर के पोटाशपुर से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक, संगठन के कमजोर पड़ने और कई बड़े नेताओं के आत्मसमर्पण के बावजूद आकाश ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था।

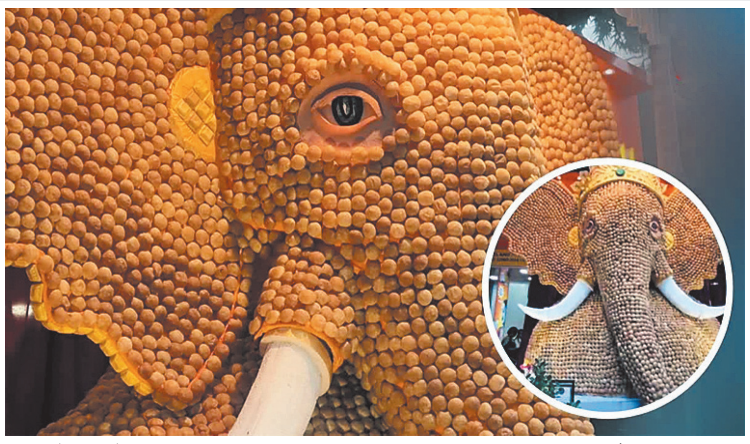

पुणे में 21 हजार पानीपुरी से बनी 13 फीट ऊंची इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, देखते ही कहेंगे वाह!

पुणे (एजेंसी)। इस समय पूरे देश में गणेशोत्सव 2026 की धूम मची है। खासकर पूरे महाराष्ट्र में चारों ओर गणेश उत्सव की प्रतिमा ही प्रतिमा दिखाई दे रही है. लोग अपनी भक्ति का अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रथम पूज्यनीय भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर गणेश भेल की ओर से बनाई गई गणपति की एक अनोखी मूर्ति लोगों का खास ध्यान खींच रही है। बता दें, यहां पानीपुरी से करीब 13 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें 21,000 पानीपुरी का प्रयोग किया गया है। गणेश भेल के मालिक रूपेश और दिनेश गुडमेवार ने अपने कारोबार से जुड़ी चीजों का अनोखे ढंग से इस्तेमाल करके यह मूर्ति बनाई है। भेल और पानी-पूरी का कारोबार करते समय उन्हें यह विचार आया कि क्या वे अपने काम में इस्तेमाल होने वाली चीजों से ही गणपति बप्पा की एक अनोखी मूर्ति बना सकते हैं. इसी सोच से पानी-पूरी से गणपति की मूर्ति बनाने का आइडिया आया।

पुणे के गुडमेवार भाइयों ने इस आइडिया को हकीकत में बदलने से पहले छह महीने तक योजना बनाने और विचार-विमर्श करने में बिताए। उन्होंने पानीपुरी से बनी इतनी बड़ी मूर्ति के लिए जरूरी स्ट्रक्चरल डिजाइन पर स्टडी की। इसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया कि पानीपुरी को कैसे व्यवस्थित किया जाए और मूर्ति का आकार और स्थिरता कैसे बनाए रखी जाए। मूर्ति बनाने का असल काम दो महीने पहले शुरू हुआ था। 13 फीट ऊंची यह गणेश प्रतिमा बांस, कागज और 21,000 पानीपुरी से बनाई गई है। हर पूरी को बहुत बारीकी से इस ढांचे में लगाया गया, जिससे बप्पा की एक शानदार और आकर्षक छवि तैयार हुई। इस मूर्ति को देखने के लिए आम लोगों और गणेश भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसी मूर्तियों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल न होने वाली चीजों से बनी होने के कारण यह मूर्ति सबसे अलग दिखती है।

खास बात यह है कि 13 फीट ऊंची यह शानदार मूर्ति सिर्फ दिखाने के लिए है। पूजा और दर्शन के लिए गणपति बप्पा की एक अलग और छोटी मूर्ति पास ही में स्थापित की गई है। इससे भक्त बप्पा के दर्शन और पूजा कर पाते हैं, जबकि पूरी तरह से पानीपुरी से बनी यह शानदार मूर्ति लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गई है। हालांकि, पानीपुरी से बनी मूर्ति को संभालकर रखना एक बड़ी चुनौती है।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर

बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की किश्त जारी

मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताः अमित शाह, वडनगर से बनारस बाइक रैली रवाना की, देशभर में सेवा-संकल्प अभियान के तहत हुए कार्यक्रम

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना/अहमदाबाद (एजेंसी)। पीएम मोदी का गुरुवार को 76वां जन्मदिन है। इस मौके पर देशभर में सेवा-संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की किश्त जारी की। मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों को लंबे समय तक केंद्र की योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें नुकसान हुआ।

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं। उन्होंने मोदी के जन्मस्थान वडनगर से वाराणसी तक करीब 1300 किमी की बाइक रैली रवाना की।

वाराणसी से भी वडनगर के लिए बाइक रैली शुरू हुई। इसमें करीब 600 बाइकर्स, 10 राज्य और 193 जिले शामिल होंगे। इसका समापन 7 अक्टूबर को होगा।

रेखा गुप्ता ने दान किए शरीर के 14 अंग

नईदिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानवता

और परोपकार की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर अपने शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के महादान का संकल्प लिया है, जो चिकित्सा जगत और जरूरतमंदों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाएगा।

शुभकामनाओं का तांता

इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिल्म सितारों समेत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए के नेताओं उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर नेताओं ने उनके नेतृत्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और देश के विकास में योगदान की तारीफ की। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' भी शुरू कर रही है। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूरे देश में सेवा गतिविधियां और आउटरीच प्रोग्राम होंगे। यह अभियान पीएम मोदी के पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं– बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश में सामाजिक समरसता का मंत्र फूंकते हैं।

खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी– कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर अच्छी सेहत और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दीं।

राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं– रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

सीएम योगी बोले, भगवान विश्वकर्मा राष्ट्र शिल्पी तो पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार

विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा–अर्चना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ओर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो दूसरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी थे तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं

ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदी न पढ़ाई जाए

- **तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए हर जिले में जमीन की पहचान करने के अपने 15 दिसंबर, 2025 के आदेश का पालन करे। साथ ही, कोर्ट ने राज्य और केंद्र से कहा कि वे इन स्कूलों को लेकर अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाएं।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने नवोदय स्कूलों में अपनाई जाने वाली तीन-भाषा नीति का तमिलनाडु द्वारा विरोध किए जाने पर भी सवाल उठाए।

बेंच ने कहा कि राज्य को केंद्र से फंड पाने वाले इन संस्थानों को अपनी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा नहीं मानना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी; ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी न पढ़ाई जाए।

चेन्नई के लोगों को दिल्ली से दूरी नहीं बनानी चाहिए- कोर्ट- बेंच ने सहकारी संघवाद की जरूरत पर जोर देते हुए यह भी कहा कि चेन्नई के लोगों को दिल्ली के लोगों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम कह रहे हैं कि आप अपने राज्य में जो अच्छे काम कर रहे हैं।

मणिपुर के रिलीफ कैंप में 25 मौतें कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश देने को मजबूर न करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के 8 राहत शिविरों में संदिग्ध मौतों और यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से 25 मौतों की रिपोर्ट मांगी। कोर्ट के मुताबिक, 8 जिलों के राहत शिविरों में अब तक 640 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से सिर्फ 20 मामलों में

पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि इन मामलों में आपराधिक केस भी दर्ज किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच मणिपुर में 2023 में जातीय हिंसा से जुड़े यौन हिंसा के मामलों की जांच और कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी–मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है। सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 16 जिलों में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू–कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया। मणिपुर के एडवोकेट जनरल से भी पूछा कि 4 जुलाई को समिति ने जो जानकारी मांगी थी, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई।

भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की तैयारी

भारतीय चिप की दुनियाभर में सप्लाई शुरू; इसकी कमी से फोन-कार महंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने वहां का दौरा किया और प्रतिभागियों से बातचीत भी की।

नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 17 से 19 सितंबर तक होने वाला यह इवेंट इंडस्ट्री की भागीदारी, पॉलिसी की दिशा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, यह कॉन्फ्रेंस सिलिकॉन टू सिस्टम्सः बिल्डिंग द इकोसिस्टम थीम के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम), मेटी बाय और ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी एमईएमआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए कहा कि अगर हम सिर्फ पिछले 15 दिनों पर नजर डालें, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है और कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। सिर्फ 10 दिन पहले मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था। वहां एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए समावेशी फाइनेंस पर चर्चा हुई।

हिमाचल-उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी

बिहार में बाढ़ से 100 से ज्यादा सड़कें बहीं, यूपी-एमपी समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट

नईदिल्ली/भोपाल/पटना/जयपुर/लखनऊ (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में गुरुवार को बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल में गुरुवार सुबह रोहतांग, भरमौर और मनाली के पहाड़ों पर एक से डेढ़ इंच बर्फ गिरी। इन क्षेत्रों में 15 अक्टूबर के आसपास हिमपात होता है, लेकिन इस बार करीब एक महीना पहले बर्फ देखने को मिली है। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चमोली में भी ओलों के साथ हल्की बर्फ गिरी है। देहरादून में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर दोबारा लैंडस्लाइड हुई। बिहार के 15 जिलों में करीब 50 लाख की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। 26 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। राज्य में 700 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें डूबी थीं, जिनमें 100 से ज्यादा पूरी तरह बह गईं, 400 सड़कें 50 प्रतिशत से ज्यादा टूटीं और 200 क्षतिग्रस्त हैं।

हेमकुंड साहिब में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, केदारनाथ धाम में हो रही हल्की बारिश– सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी से रौनक लौट आई है। गुरुवार 17 सितंबर सुबह बारिश के साथ हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हेमकुंड साहिब का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रकृति ने मानो इस पवित्र धाम को अपने ही अंदाज में सजाकर श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी की हो।

DEV MEDICARE CHEMIST
Your Trusted Medical Store
SECTOR 7, FARIDABAD
Allopaathic & Ayurvedic Medicine
BP & sugar Mechines, Thermometers, Oximeters
DISCOUNT ON VARIOUS MEDICINES
Surgical Items, Baby Products, Health Supplements
Wide Range of Cosmetics
ORDER NOW - 9650518651 (Call/Whatsapp)
Hours: 8 AM to 10 PM
100% Genuine Medicines
Experienced Staff

SINCE 2007
TARUN JEWELLERS
TODAY BIS HALLMARK
92% Gold Rate
₹1,36,600/-
Making Charges 8%
100% BUY BACK + EXCHANGE
पिछले 19 वर्षों से हमारी दुकान एक ही स्थान पर है। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है।
Shop No. 25, Sec-7, Huda Mkt, FBD
0129-3668332, 9990032657

'गैंगस्टरां ते वार' अभियान का 240वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 526 स्थानों पर छापेमारी; 265 व्यक्ति काबू

- पुलिस टीमों द्वारा 196 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई
- लोग 'एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946' के माध्यम से गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से कर सकते हैं रिपोर्ट
- 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के 565वें दिन 109 नशा तस्कर काबू

चंडीगढ़। 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के 240वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित और मैप किए गए 526 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए 'गैंगस्टरां ते वार' एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को की गई थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें 'एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स' पंजाब के समन्वय से राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं। 240वें दिन पुलिस टीमों ने 265 व्यक्तियों को तीन हथियारों सहित गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 71,522 हो गई है। इसके अलावा 196 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस अभियान के दौरान नौ भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग 'एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946' के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान 'युद्ध नशों विरुद्ध' को 565वें दिन भी जारी रखा, जिसके तहत आज 109 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 465 ग्राम हेरोइन, 180 किलोग्राम भुक्की, 492 नशीली गोलियां तथा 12,200 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, केवल 565 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 78,018 तक पहुंच गई है। नशा छुड़ाने के अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 19 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए राजी किया है।

मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा : पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना में न्यूरोटिक और तनाव-संबंधी समस्याओं का इलाज शामिल

- मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में देरी हो सकती है घातक, इलाज को प्राथमिकता देना ज़रूरी : डॉ. बलबीर सिंह
- तनाव-संबंधी बीमारियाँ रोज़मर्रा के जीवन, कामकाज और रिश्तों को कर सकती हैं प्रभावित : डॉ. गगनदीप सेखों, एम.डी. मनोचिकित्सा, कंसल्टेंट मनोचिकित्सक, सिविल अस्पताल बरनाला

चंडीगढ़। हम अक्सर तनाव को व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा मान लेते हैं। वह बहुत ज़्यादा चिंता करती है। वह हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। वे मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। पर तनाव एक स्वास्थ्य समस्या का रूप भी ले सकता है। बड़ी चुनौती यह पहचानने की है कि आम चिंता कब स्वास्थ्य समस्या में बदल जाती है। न्यूरोटिक और तनाव-संबंधी समस्या सिर्फ़ रोज़मर्रा के आम तनाव तक सीमित नहीं होती। इनमें चिंता, डर, बेचैनी या शारीरिक लक्षणों के ऐसे गंभीर रूप शामिल होते हैं, जो व्यक्ति के रोज़ाना जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर, गंभीर तनाव प्रति प्रतिक्रिया और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर शामिल हैं। जनरलाइज़्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर को दुनिया भर में पाए जाने वाले आम मानसिक विकारों में से एक माना जाता है। निदान के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले लगभग 5 फ़ीसदी लोग इससे प्रभावित होते हैं। हालाँकि, यह स्थिति की सिर्फ़ एक तस्वीर हो सकती है, क्योंकि सामाजिक बंदिशों और इलाज करवाने में आने वाली रुकावटों के कारण कई लोग इलाज ही नहीं करवा पाते। पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना में मानसिक स्वास्थ्य को 'मेंटल डिसऑर्डर्ज़' श्रेणी अधीन शामिल किया गया है। न्यूरोटिक, तनाव-संबंधी और सोमैटोफार्म समस्याओं के लिए इलाज पैकेज को 'रेगुलर प्रोसीजर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, 'मानसिक स्वास्थ्य के इलाज को किसी पारिवारिक या आर्थिक रुकावट के कारण टाला नहीं जाना चाहिए।' डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के बराबर प्राथमिकता मिलनी चाहिए और आर्थिक रुकावटों के कारण लोग इलाज से वंचित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना अधीन मानसिक स्वास्थ्य के इलाज को शामिल करने का उद्देश्य इलाज को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना और उन्हें समय पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।' डॉ. गगनदीप सेखों, एम.डी. (मनोचिकित्सा), कंसल्टेंट मनोचिकित्सक, सिविल अस्पताल बरनाला ने कहा, 'मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को अक्सर तब तक नज़रअंदाज़ किया जाता है, जब तक ये रोज़ाना के जीवन और आम कामकाज को प्रभावित करना शुरू नहीं कर देतीं। उस समय तक इनसे निपटना अधिक मुश्किल हो जाता है।' उन्होंने कहा कि 18 से 45 साल की उम्र का वर्ग ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उम्र में लोग करियर बनाने, रिश्ते संभालने और आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ निभाने में रुझे होते हैं।

जब दिमाग के लिए आराम मुश्किल हो जाए– तनाव को एक अलार्म सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। ख़तरा होने पर यह अलार्म बजना चाहिए और ख़तरा टलने के बाद शांत हो जाना चाहिए। डॉ. गगनदीप सेखों ने कहा, 'तनाव-संबंधी बीमारियों में यही अलार्म समस्या बन जाता है। व्यक्ति को लगातार चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल, नींद में परेशानी या हर समय बेचैनी महसूस हो सकती है। चिंता शारीरिक लक्षणों का रूप भी ले सकती है, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीना आना, कांपना, जी मिचलाना और मासपेशियों में खिंचाव।' विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर पारिवारिक जीवन, शिक्षा और कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी स्थिति भी है, जिसे अक्सर सही ढंग से समझा नहीं जाताः इसमें शरीर हमारे मन में चल रही परेशानी को शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट करने लगता है। डॉ. गगनदीप सेखों ने बताया, 'सोमैटोफार्म विकारों में शारीरिक लक्षण लगातार बने रह सकते हैं, भले ही जाँच में उनकी गंभीरता का पूरा कारण स्पष्ट न हो। इनमें दर्द, शरीर में भारीपन या पेट फूलना जैसे लक्षण हो सकते हैं।' इसलिए किसी व्यक्ति को यह कहना कि 'यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है' समस्या को समझने का सही तरीका नहीं है। लक्षण असली होते हैं। मन और शरीर के बीच संबंध भी असली होता है। कई बार इसकी शुरुआत किसी एक बड़ी घटना से हो सकती है–जैसे किसी करीबी की मौत, अलग होना, बीमारी, आर्थिक संकट या जीवन में आया कोई बड़ा बदलाव। दूसरी ओर, कई बार यह लंबे समय से बन रहे तनाव का नतीजा हो सकता हैः कई महीनों के काम का दबाव, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, अनिश्चितता और नींद की कमी धीरे-धीरे व्यक्ति की तनाव से निपटने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

भगवंत मान सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम' के तहत 5.10 लाख श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की: तरुनप्रीत सिंह सौंद

- स्कीम के तहत 95 ए.सी. बसों ने 12,485 चक्कर पूरे किए: तरुनप्रीत सिंह सौंद
- श्री खाटू श्याम-सालासर बालाजी धाम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन को इस स्कीम में शामिल किया गया: तरुनप्रीत सिंह सौंद
- 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रद्धालु मुफ्त ए.सी. स्लीपर बस के माध्यम से यात्रा, आवास और भोजन संबंधी सुविधा के लिए पात्र: तरुनप्रीत सिंह सौंद

चंडीगढ़। पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज बताया कि भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम' के तहत 5,10,807 श्रद्धालुओं ने राज्य और राज्य के बाहर के विभिन्न धार्मिक स्थानों के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के इच्छुक बुजुर्ग नागरिकों को यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत उन्हें मुफ्त यात्रा और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत 5,10,807 श्रद्धालुओं ने राज्य के और राज्य के बाहर के विभिन्न धार्मिक स्थानों के दर्शन किए हैं। वर्तमान में, इस स्कीम के अंतर्गत 95 ए.सी. बसें चलाई जा रही हैं और अब तक 12,485 चक्कर पूरे किए गए हैं।' पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने कहा, 'यह स्कीम 9 नवंबर 2025 को शुरू की गई थी और इसके पहले चरण के दौरान, लगभग चार लाख श्रद्धालुओं ने श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी की यात्रा की।' उन्होंने कहा, '12 अगस्त 2026 को इस स्कीम का विस्तार करते हुए इसमें अन्य धार्मिक स्थानों जैसे श्री खाटू श्याम-सालासर बालाजी धाम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन को भी शामिल किया गया।' कैबिनेट मंत्री

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, 'इस स्कीम के तहत, 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग इस तीर्थ यात्रा का लाभ ले सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा योग्य श्रद्धालुओं को ए.सी. स्लीपर बस के माध्यम से यात्रा, आवास और भोजन संबंधी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं।' पर्यटन मंत्री ने कहा, 'यात्रा के दौरान संगतों की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हर बस में सहायक कर्मचारियों और मेडिकल स्टाफ की एक टीम तैनात की गई है, जबकि विभिन्न पड़ावों पर संगतों की सुविधा के लिए विशेष टीमें तैनात हैं।' उन्होंने कहा, 'संगतों के लिए किए गए प्रबंधों में साफ-सुथरे और अच्छे पखाने की सुविधा वाली एयर-कंडीशन्ड रिहायश के साथ-साथ यात्रा के दौरान भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं।' पर्यटन मंत्री ने कहा, 'यात्रा के दौरान संगत बहुत खुश और संतुष्ट होती है और श्रद्धालु अक्सर शबद गाते जाते हैं। मैं अरदास करता हूं कि हर यात्रा सुरक्षित और शुभ हो और सारी संगत धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने के उपरांत खुशी-खुशी अपने घर लौटे।' उन्होंने आगे कहा, 'यात्रा की समाप्ति पर, श्रद्धालुओं को प्रसाद और यादगार के रूप में पीतल का गिलास भी दिया जाएगा।' पर्यटन मंत्री ने कहा, 'यह स्कीम हर किसी के लिए खुली है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म से संबंधित हो। धार्मिक स्थानों के दर्शन करने और माथा टेकने के इच्छुक बुजुर्गों की सहायता करना ही इस पहल का उद्देश्य है।' मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, 'मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर श्रद्धालु को पूरी यात्रा के दौरान उचित सुविधाएं और सहायता मिले। संबंधित टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाजिर रहें और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाए।'

भगवंत मान सरकार द्वारा स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में 11 गैर-सरकारी सदस्य नामित, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी और मजबूती

- स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की मजबूती से पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जवाबदेही, गुणवत्ता और अधिकार-आधारित प्रणाली सुनिश्चित होगी
- मरीजों, देखभाल करने वालों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संस्थाओं को पंजाब की मजबूत की गई मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में मिली प्रतिनिधित्व
- गुणवत्ता, जवाबदेही, मान-सम्मान और उपचार की निरंतरता बनाए रखते हुए काम करे स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी: डॉ. सतिएन शर्मा, वरिष्ठ मनोचिकित्सक
- पंजाब को अपने लोगों और समुदाय की जरूरतों के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य समाधानों की आवश्यकता: डॉ. सतीश के. थापर, वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ

चंडीगढ़। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी (एस.एम.एच.ए.) में 11 गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया है, जिससे राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी। यह पहल पंजाब में मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा और अधिक जवाबदेह मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मजबूत स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 के प्रावधानों को लागू करने की निगरानी की जाएगी और अधिनियम के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, नियमन और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार की प्रमुख पहल 'युद्ध नशों विरुद्ध' के तहत मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति सेवाओं के विस्तार के मद्देनजर यह कदम विशेष महत्व रखता है। उल्लेखनीय है कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन के लिए सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्ता और सेवा मानक निर्धारित करने, संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का पंजीकरण करने तथा मानसिक स्वास्थ्य नीति से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। अथॉरिटी के सरकारी सदस्यों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही 11 गैर-सरकारी नामित सदस्यों में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, नर्सें, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोग, देखभाल करने वाले और गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां केवल प्रशासनिक और चिकित्सकीय विशेषज्ञों तक सीमित न रहें, बल्कि मरीजों, उनके परिवारों और उनके साथ निकटता से काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाए। जिला जज या योग्य न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी कार्य कर रहे हैं। ये बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में दाखिले और उपचार से संबंधित निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा करते हैं। इसके अलावा बोर्डों के माध्यम से शिकायतों और अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामलों का निपटारा, अग्रिम निर्देशों और नामित प्रतिनिधियों की जांच की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण भी किया जाता है। एस.एम.एच.ए. के लिए नामित सदस्यों की सूची में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से निरंतर कार्य कर रहे वे विशेषज्ञ, अनुभवी और प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं, जिन्होंने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नामित सदस्य और वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सतिएन शर्मा ने कहा, 'स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास गुणवत्ता और जवाबदेही को केंद्र में रखकर किया जाए। सरकार ने हमें अधिकार-आधारित एक स्पष्ट ढांचा दिया है और अब अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसे ऐसी सेवाओं में बदला जाए, जिन तक लोगों की वास्तव में पहुंच हो और जिन पर भरोसा करके लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके लिए मरीजों के मान-सम्मान, उपचार की निरंतरता, पुनर्वास तथा परिवारों और देखभाल करने वालों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।' पटियाला से संबंधित वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. शर्मा ने आगे कहा, 'मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अब लोगों तक उनके अपने क्षेत्रों में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। पंजाब जैसे राज्य के लिए जिला और सामुदायिक स्तर पर सेवाओं को मजबूत करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों को केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के उपचार की सुविधा भी मिल सके। अथॉरिटी के पास इस उद्देश्य को साकार करने का महत्वपूर्ण अवसर है।' वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नामित सदस्य डॉ. सतीश के. थापर ने कहा, 'पंजाब के सामने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं और हमें ऐसे समाधानों की आवश्यकता है, जो हमारे लोगों और समुदाय की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हों। मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे हालिया प्रयास और अब स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को मजबूत किया जाना इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। अथॉरिटी राज्य भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक एकरूपता और जवाबदेही लाने में मदद कर सकती है और यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि मरीजों के अधिकारों और मान-सम्मान को प्राथमिकता दी जाए। अभी काफी काम करना बाकी है और यह पंजाब में एक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार है।' अथॉरिटी की नामित सदस्यों के साथ पहली बैठक आगामी सप्ताह में होगी। एस.एम.एच.ए. पंजाब में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक समान प्रणाली तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सेवाएं मरीजों की जरूरतों और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाएं। यह पहल 'युद्ध नशों विरुद्ध' के तहत पंजाब सरकार के व्यापक उद्देश्य को भी मजबूत करती है। इस पहल के माध्यम से नशों की समस्या से निपटने के लिए केवल प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है।

गैंगस्टरां ते वार का 239वां दिन: पंजाब पुलिस ने 570 स्थानों पर छापेमारी कर 303 को किया काबू

- पुलिस टीमों ने 226 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की
- लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में कर सकते हैं रिपोर्ट
- युद्ध नशों विरूद्ध के 564वें दिन 27.2 किलोग्राम हेरोइन समेत 63 नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़। राज्य में चलाए जा रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 239वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 570 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरां ते वार'–पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग–की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। 239वें दिन पुलिस टीमों ने 3 हथियारों सहित 303 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तारियों की कुल संख्या 71,257 हो गई है। इसके अलावा, 226 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 13 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं। इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान 'युद्ध नशों विरूद्ध' को 564वें दिन भी जारी रखते हुए आज 63 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 27.2 किलोग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 81 नशीली गोलियां और 8,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही, केवल 564 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,922 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 8 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है।

पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल 27 नवंबर को

दो मिनट की एयर रेड वार्निंग सायरन के साथ रात 8 बजे शुरू होगी मॉक ड्रिल

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में 27 नवंबर, 2026 को रात 8 बजे सिविल डिफेंस एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज़ करवाई जाएगी। यह मॉक ड्रिल पूरे राज्य में सिविल डिफेंस संबंधी तैयारियों का जायज़ा लेने और इन तैयारियों में मज़बूती लाने के लिए की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मॉक ड्रिल एक एयर रेड वार्निंग सिग्नल के साथ शुरू होगी, जिस दौरान दो मिनट के लिए हाई-लो पिच वाला सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान, संबंधित डिप्टी कमिश्नर-कम-कंट्रोलर, सिविल डिफेंस द्वारा मॉक ड्रिल वाले क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट के दौरान, निर्धारित क्षेत्रों में आम लोगों को सभी गैर-ज़रूरी लाइटें बंद करने के लिए कहा जाएगा, जबकि इस दौरान ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मॉक ड्रिल पूरी होने पर दो मिनट के लिए तेज़ आवाज़ वाला सायरन बजाकर 'ऑल क्लियर' का संकेत दिया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस मॉक ड्रिल के दौरान फायर रिस्पॉन्स ऑपरेशन, खोज और बचाव कार्यों, प्राथमिक चिकित्सा सहायता, घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और यातायात तथा भीड़ नियंत्रण करने संबंधी उपाय अमल में लाए जाएंगे। ये गतिविधियां सिविल डिफेंस प्रणाली संबंधी तैयारियों और रिस्पॉन्स प्रणालियों का मूल्यांकन करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान आम लोगों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की गई है क्योंकि यह एक रूटीन अभ्यास है जो सिविल डिफेंस संबंधी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए किया जा रहा है। मॉक ड्रिल वाले क्षेत्रों के लोगों से शांत रहने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने और ड्रिल के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में कानूनी विवादों में फंसे बच्चों को हुनरमंद बनाने की दिशा में पंजाब सरकार की अहम पहल

- होशियारपुर के ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम के 48 बच्चों ने रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम किए पूरे
- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के 'रंगला पंजाब' के सपने के तहत बच्चों को नई दिशा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पंजीकृत होम्स में रह रहे बच्चों को शिक्षा, कौशल और बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार की इस विशेष पहल के तहत होशियारपुर के स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम में रह रहे 48 बच्चों ने सफलतापूर्वक रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। स्पेशल होम, होशियारपुर के 25 बच्चों ने हेयर ड्रेसर एंड स्टाइलिस्ट (हेयर ड्रेसर एंड स्टाइलिस्ट) और ऑब्जर्वेशन होम के 23 बच्चों ने मल्टी स्किल टेक्नीशियन (मल्टी स्किल तकनीशियन) पाठ्यक्रम पूरा किया। इन सभी बच्चों का 100 प्रतिशत प्रशिक्षण पूरा होने के साथ-साथ उनकी असेसमेंट और प्रमाणन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। यह सफलता उन्हें कौशल के साथ आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशों के अनुसार राज्य के ऑब्जर्वेशन होम्स और स्पेशल होम्स में कुल 187 बच्चों के लिए विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का चयन बच्चों की रुचि, क्षमता और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजाब कौशल विकास मिशन के सहयोग से करवाए जा रहे ये पाठ्यक्रम बच्चों को व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के साथ-साथ समाज में पुनर्वास के लिए तैयार कर रहे हैं। विभाग द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने वाले बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस प्रणाली के तहत रह रहे बच्चों को केवल देखभाल की ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और अवसरों की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से इन बच्चों को अपनी क्षमता पहचानने और जीवन में नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 'रंगला पंजाब' के निर्माण के लिए हर बच्चे को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संक्षिप्त समाचार

हाईकोर्ट का तिहाड़ जेल अधीक्षक पर बड़ा एक्शन, आदेश न मानने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की

नई दिल्ली, एजेंसी। विचाराधीन कैदी को पैरोल पर रिहा होने से रोकने को दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन माना है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन ने कैदी अनवर हुसैन की रिहाई के आदेश को असल में नाकाम कर दिया। अदालत ने यह कार्रवाई पैरोल पर रिहाई के निर्देश देने की मांग वाली हुसैन की याचिका पर की। हुसैन ने जेल प्रशासन द्वारा अपनी पैरोल अर्जी खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

30 जुलाई को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हुसैन को सक्षम अधिकारी द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के साथ चार सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। अदालत के आदेश के बावजूद सक्षम अधिकारी ने पैरोल की शर्तें तय नहीं कीं। इसके कारण हुसैन को रिहा नहीं किया गया और वह जेल में ही रहने को मजबूर रहा। हुसैन पहले ही विचाराधीन कैदी के तौर पर पांच साल और पांच महीने जेल में बिता चुका था। हाई कोर्ट ने इसी स्थिति को अदालती आदेश के पालन को नाकाम करने वाला व्यवहार माना और जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

एम्स दिल्ली में पहले 'मेड इन इंडिया' एंडोस्कोपी सिस्टम से शुरू हुआ इलाज

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में निर्मित पहला एंडोस्कोपी सिस्टम एम्स में स्थापित किया गया है। फुजीफिल्म इंडिया के जोधपुर स्थित निर्माण संयंत्र में तैयार ईपी-6000 एंडोस्कोपी सिस्टम को एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलाजी विभाग में लगाया गया है। एम्स की ओर से बुधवार को दी गई जानकारी में बताया गया है कि यह देश में निर्मित पहला ऐसा एंडोस्कोपी सिस्टम है, जिसे संस्थान में स्थापित किया गया है। एम्स के निदेशक प्रो. निखिल टंडन ने कहा कि भारत में एंडोस्कोप के निर्माण के लिए संयंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एम्स में देश में निर्मित इस सिस्टम की स्थापना से आधुनिक तकनीक के जरिये मरीजों को सेवाएं देने की संस्थान की क्षमता बढ़ेगी। नई प्रणाली में बेहतर इमेजिंग की सुविधा है। इससे डाक्टर पाचन तंत्र के अंदरूनी हिस्सों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकेंगे और किसी असामान्य हिस्से की पहचान करना आसान होगा। इससे बीमारी की जांच और आवश्यकता के अनुसार आगे का उपचार तय करने में मदद मिल सकती है। गैस्ट्रोएंटेरोलाजी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रमोद गर्ग ने बताया कि नई प्रणाली से विभाग की मरीजों को सेवा देने की क्षमता बढ़ेगी।

दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम, डीडीए ने इंदिरा कल्याण विहार में शुरू किया सर्वे

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया अब जमीन पर आगे बढ़ने लगी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इंदिरा कल्याण विहार से झुग्गीवासियों के सर्वे का काम शुरू किया है। ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, साइट-2 स्थित इस जेजे क्लस्टर में डीडीए की इन-सीटू स्लम पुनर्वास शाखा की टीमें घर-घर जाकर निवासियों की संख्या और पुनर्वास के लिए उनकी पात्रता से जुड़े दस्तावेज जुटा रही हैं। सर्वे का मकसद यह पता लगाना है कि क्लस्टर में कितने परिवार रह रहे हैं और इनमें से कौन पुनर्वास योजना के तहत पात्र है। डीडीए ने झुग्गीवासियों से सर्वे के दौरान मौजूद रहने और मांगी गई जानकारी व दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

अधिकारियों के अनुसार, इंदिरा कल्याण विहार के बाद राजधानी के अन्य जेजे क्लस्टरों में भी चरणबद्ध तरीके से सर्वे कराया जाएगा। एक जनवरी 2025 की कटआफ तिथि तय की गई इस सर्वे की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि झुग्गी पुनर्वास के लिए तैयार की गई दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति-2026 में पात्रता के लिए एक जनवरी 2025 की कटआफ तिथि तय की गई है। यानी सर्वे में दस्तावेजों के आधार पर यह भी देखा जाएगा कि संबंधित परिवार तय पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज पर मेटा का बड़ा फैसला, अब सीधे दिल्ली पुलिस को मिलेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम का डेटा

नई दिल्ली, एजेंसी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री मिलने पर मेटा अब इसकी जानकारी सीधे भारत के साइबर अपराध तंत्र को देगी। इससे दिल्ली में ऐसे मामलों की जांच को महत्वपूर्ण डिजिटल सुराग मिलने की उम्मीद है। खासकर द्वारका स्थित दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस इकाई को संदिग्ध अकाउंट, आइपी एड्रेस और अन्य डिजिटल एविडेंस तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

दिल्ली पुलिस के अनुसार महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील साइबर अपराधों समेत जटिल मामलों की जांच करने वाली विशेष इकाई है। इसके पास डिलीट डाटा निकालने और मोबाइल व अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच की सुविधा भी है।

बच्चों के खिलाफ आनलाइन अपराध की गंभीरता का अंदाजा एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। देश में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के

1,238 मामले सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दर्ज हुए।

इनमें 1,099 मामले बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट सामग्री में दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े थे। यानी करीब 89 प्रतिशत मामले इसी श्रेणी के थे। दिल्ली में ऐसे साइबर अपराध के 151 मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 137 मामले सामने आए।

यह आंकड़ा सिर्फ दर्ज मामलों को दर्शाता है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार ग्रूमिंग, साइबर स्टाकिंग, मार्फ्ड इमेज, ब्लैकमेलिंग और आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए बच्चों को डराने या फंसाने जैसी घटनाओं में कई बार शिकायत ही नहीं होती। इसलिए दर्ज मामलों को आनलाइन अपराध की पूरी तस्वीर नहीं माना जा सकता।

15 जिला साइबर थानों का नेटवर्क

दिल्ली में अब सभी 15 जिलों में अलग साइबर थाना अधिसूचित है। इनमें पूर्व, उत्तर-पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, बाहरी, मध्य, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, शाहदरा, रोहिणी, नई दिल्ली, द्वारका और बाहरी उत्तर जिला शामिल हैं।

मिले इनपुट को संबंधित जिले तक भेजकर स्थानीय स्तर पर जांच और कार्रवाई की जा सकती है। एनसीआर में नोएडा और गुरुग्राम में भी साइबर अपराध के लिए अलग पुलिस तंत्र सक्रिय है। बच्चों को निशाना बनाने का तरीका हमेशा सीधे आपत्तिजनक सामग्री भेजने से शुरू नहीं होता। कई मामलों में अपराधी पहले सोशल मीडिया पर बच्चे से दोस्ती करता है, उम्र या पहचान छिपाकर विश्वास हासिल करता है और धीरे-धीरे निजी तस्वीर या वीडियो मांगता है। इसे ग्रूमिंग कहा जाता है। बाद में उसी सामग्री के आधार पर ब्लैकमेल, धमकी या यौन शोषण का प्रयास किया जा सकता है।

अंतिम दिन उड़ीं नियमों की धज्जियां, लग्जरी गाड़ियों से प्रचार

नई दिल्ली, एजेंसी। डूसू चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को छात्र संगठन और प्रत्याशी नार्थ कैंपस में चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद प्रचार में महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा छात्र परिसर में अवैध पार्किंग करते भी दिखाई दिए। इससे चुनावी आचार संहिता के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। डूसू चुनाव में प्रचार के दौरान वाहनों के इस्तेमाल और पार्किंग को लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद आखिरी दिन प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र प्रचार करते नजर आए। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही और अवैध पार्किंग से परेशानी हुई। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आने से प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को झटका, जंतर-मंतर पर 'शरिया बचाओ' प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं; दिल्ली पुलिस अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों और राजग शासित राज्यों में इसे लॉगू करने के रोडमैप के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी आंदोलन को शुरुआत में ही झटका लगा है। राजधानी दिल्ली में हालिया कॉकरोच जनता पार्टी के उग्र विरोध प्रदर्शनों से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए एआइएमपीएलबी को जंतर-मंतर पर धरना देने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से इस मुहिम के औपचारिक

आगाज का फैसला लिया है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मंजूरी न मिलने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी व प्रमुख मुस्लिम प्रतिनिधि आज प्रेस क्लब में एक साझा पत्रकार वार्ता करेंगे। इसमें राष्ट्रव्यापी 'संविधान बचाओ-शरिया बचाओ' अभियान की विस्तृत रूपरेखा रखेंगे। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यूसीसी और वक्फ संशोधन कानून के जरिए उनके धार्मिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानूनों में सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2029 तक सभी राजग शासित राज्यों में यूसीसी लॉगू करने का रोडमैप पेश किए जाने के बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आक्रामक रुख अपनाए हुए है। इसी तरह वक्फ कानून में बदलाव से भी असंतोष है। शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम् के सभी छह छंदों को अनिवार्य किए जाने का भी बोर्ड कड़ा विरोध कर रहा है। इन मुद्दों को लेकर मुस्लिम संगठन विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को एकजुट करने और जनता के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश में है।

200 करोड़ की ठगी में बढ़ेंगी जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें? सुकेश के मकोका केस में बन सकती हैं आरोपी

नई दिल्ली, एजेंसी। 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में जांच की कड़ी अब एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी स्थिति तक पहुंच गई है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका मामले में जैकलीन को आरोपित बनाए जाने की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला टाल दिया है। अब अदालत यह तय करेगी कि जिस संगठित अपराध के खिलाफ मकोका लगाया गया, उसमें जैकलीन को भी आरोपित के तौर पर जोड़ा जा सकता है या नहीं। फिलहाल जैकलीन मकोका मामले में आरोपित नहीं हैं। कानूनी स्थिति इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलग है, जिसमें ईडी ने उन्हें आरोपित बनाया है। यही अंतर इस मामले की अगली कानूनी लड़ाई का अहम बिंदु बन गया है। मामले की शुरुआत सुकेश चंद्रशेखर पर जेल से 200 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप से हुई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में आरोप लगाया गया कि सुकेश ने जेल के अंदर से एक संगठित नेटवर्क संचालित किया और लोगों से रकम वसूलने के लिए अपने सहयोगियों की मदद ली।

दिल्ली बनेगी 'सोलर कैपिटल', फ्री में घर-घर लगाए जाएंगे सोलर पैनल; 6 महीने में 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली को सोलर कैपिटल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा के विस्तार पर जोर बढ़ा दिया है। सरकार ने तीन किलोवाट तक निशुल्क सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। अगले वर्ष मार्च तक करीब 2.30 लाख सोलर पैनल लगाने और अगले छह महीनों में इस पहल पर लगभग 2,700 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को सोलर कैपिटल बनाना है। इसके लिए उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना से संबंधित सोलर वेंडर्स सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इससे जुड़े व्यवसाय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कई उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए आने वाले खर्च का अग्रिम भुगतान करने में परेशानी होती थी। सरकार ने इस बाधा को दूर कर दिया है और पूरी राशि का भुगतान सरकार करेगी। योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा विभाग ने समर्पित पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया है। सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक लगभग 2.30 लाख सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, अगले छह महीनों में इस पहल के तहत लगभग 2,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आशीष सूद ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाना है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति मिलने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने और सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली में खड़ी रहीं 5 हजार बसें, सड़कों पर बेहाल दिखे 40 लाख यात्री, ऑटो-टैक्सी चालकों ने मांगा मनमाना किराया

नई दिल्ली, एजेंसी। डीटीसी बस चालकों की हड़ताल ने आम जन के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के आह्वान पर हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 40 लाख यात्री डीटीसी बसों में यात्रा करते हैं, जो 5000 से अधिक बसों के दिल्ली की सड़कों पर न उतरने से दिनभर बेहाल दिखे। वहीं आटो-टैक्सी चालकों के मनमाने किराये ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी। वेतन बढ़ोत्तरी, मेडिकल सुविधा, सालाना बोनस व ओवर टाइम का भुगतान समेत कई अन्य मांगों को लेकर डीटीसी व परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल प्राइवेट आपरेटर्स की बसों के चालकों ने मंगलवार से हड़ताल शुरू की है। बुधवार को उसका व्यापक असर देखने को मिला।

आंदोलनकारी चालकों के संगठन ने डीटीसी बसों के संचालन के 80 प्रतिशत तक प्रभावित होने का दावा किया है। अधिकतर बसें दिल्ली के सभी 83 डिपो में खड़ी रहीं। डिपो में चालकों ने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। कुछ जगहों पर सड़कों पर निकले बसों को आंदोलनकारी चालकों ने रोका और उनके चेहरे पर कालिख भी पोत दी। हड़ताल का असर पूरे दिन बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां यात्री घंटों बसों का इंतजार में खड़े दिखे। कई यात्रियों को हड़ताल की जानकारी भी नहीं थी। काफी देर तक जब बसें नहीं आईं तो कई यात्रियों ने मेट्रो का रुख किया। आइटीओ, मंडी हाउस, कृषि भवन, करोल बाग, चाणक्यपुरी, दरियागंज, प्रगति मैदान, इंडिया गेट, लक्ष्मी नगर समेत दिल्लीभर के बस स्टैंडों पर यात्री परेशान दिखे। अंबेडकर पार्क में दोपहर में बस का इंतजार करते आशीष ने बताया कि एक घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन कोई बस नहीं आ रही है। इसलिए उन्हें ई-रिक्शा लेकर मेट्रो जाना पड़ा है। आइटीओ पर बस का इंतजार करती माता सुंदरी कालेज की छात्रा मेहजबीन ने बताया कि उसे भोगल तक

जाना है, लेकिन काफी देर से बस नहीं आ रही है। सुबह भी बस न मिलने से उसे कालेज तक आटो से आना पड़ा था। खानपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही दिव्या व खुशी ने बताया कि आधे घंटे से बस नहीं आ रही। आटो लेना चाहा तो उसने 150 की जगह 200 रुपये किराया मांगा। ऐसी स्थिति रही कि लोग अपने घरों में देर रात तक पहुंच पाए। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महामंत्री मनोज शर्मा का कहना है कि डीटीसी बेडे की कुल 6500 से अधिक बसों में से करीब 5000 बसों का परिचालन प्रभावित रहा है।

एसआईआर के बाद दिल्ली में 47.5 लाख नाम हटे, नए वोटर बनने के लिए 15 दिन में आए सिर्फ 62 हजार आवेदन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की रफ्तार अभी धीमी है। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47.5 लाख नाम हटाए जाने के बाद 30 सितंबर तक चलने वाले दावे-आपत्तियों के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 62,583 लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए फार्म छह भरा है। चुनाव कार्यालय को उम्मीद है कि हटाए गए मतदाताओं में से कम से कम 10 प्रतिशत यानी करीब 4.75 लाख लोग इस अवधि में आवेदन करेंगे।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर तक 62,583 फार्म छह जमा हुए हैं। हालांकि, ड्राफ्ट सूची जारी होने से पहले ही दिल्ली में 2.12 लाख फार्म-6 जमा हो चुके थे। यानी दावे-आपत्तियों की शुरुआत के बाद नए आवेदनों की रफ्तार अपेक्षाकृत कम रही है। जिलों के स्तर पर भी आवेदन संख्या में बड़ा अंतर है। पहले 15 दिनों में सबसे ज्यादा 7,834 आवेदन पश्चिमी जिले से आए। इसके बाद उत्तर-पश्चिम में 6,384, पूर्वी दिल्ली में 6,297, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 5,585 और दक्षिण-पश्चिमी जिले में 5,436 आवेदन हुए। नई दिल्ली जिले में सबसे कम 1,203 आवेदन आए। पुराने दिल्ली क्षेत्र में 2,547, मध्य में 2,647, मध्य-उत्तर में 4,188 और बाहरी उत्तर में 4,287 आवेदन मिले। मतदाता सूची में नाम हटने के बाद भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक प्रारूप सूची में शामिल करीब 33 लाख मतदाताओं को भी विभिन्न विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यह संख्या प्रारूप सूची में शामिल करीब 97 लाख मतदाताओं की एक-तिहाई से ज्यादा है। ऐसे में अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या और घट सकती है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली की बड़ी आबादी के लगातार स्थान बदलने को कम आवेदन आने की एक वजह माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में लोग कुछ वर्षों के लिए दिल्ली में रहने के बाद दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।

दिल्ली सरकार बेचेगी कार्बन क्रेडिट, हर साल करोड़ों कमाने का प्लान; पर्यावरण सुधार से होगी बंपर कमाई

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार अब पर्यावरण सुधार के कामों को आय का जरिया बनाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इससे सरकार को करोड़ों की कमाई होगी। सरकार इलेक्ट्रिक बसों, पौधारोपण, कचरा प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा बचत जैसे प्रोजेक्ट से होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी को कार्बन क्रेडिट में बदलकर बाजार में बेच सकेगी। इससे सरकार को इन पर्यावरणीय कामों के बदले अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है। पर्यावरण विभाग ने इसके लिए तीन सलाहकार एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा जारी की है। ये एजेंसियां पहले यह पता लगाएंगी कि दिल्ली सरकार की कौन-कौन सी परियोजनाओं से कितने कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है।

इसके बाद उसका वैज्ञानिक तरीके से हिसाब तैयार किया जाएगा और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उसका सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र परियोजनाओं के लिए कार्बन क्रेडिट जारी होंगे।

इन्हें कार्बन बाजार में खरीदारों को बेचा जा सकेगा। इनकी बिक्री से मिलने वाली रकम दिल्ली सरकार के समेकित कोष या सरकार द्वारा तय खाते में जमा होगी। निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारंभिक आकलन के मुताबिक दिल्ली मध्यम अवधि में हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी हासिल कर सकती है।

हालांकि सरकार ने इसे प्रारंभिक और संकेतात्मक अनुमान बताया है। वास्तविक कार्बन क्रेडिट परियोजना की प्रकृति, उत्सर्जन में वास्तविक कमी और मान्यता प्राप्त मानकों के आधार पर तय होंगे। सरकार का कहना है कि दिल्ली में अभी अलग-अलग परियोजनाओं से होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी का व्यवस्थित हिसाब, उसकी निगरानी और उसे बाजार से जोड़ने की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। जनवरी में दिल्ली कैबिनेट ने कार्बन क्रेडिट से आय अर्जित करने के लिए रूपरेखा को मंजूरी दी थी।

रिश्तेदार होना जरूरी नहीं, समलैंगिक पार्टनर को मिला मेडिकल फैसले लेने का हक; दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का हलफनामा

नई दिल्ली, एजेंसी। किसी वयस्क मरीज के अधिकृत समान-लैंगिक पार्टनर को केवल उसके समान लिंग या गैर-विषमलैंगिक संबंध में होने के आधार पर मेडिकल फैसले लेने से नहीं रोका जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि मरीज ने पार्टनर को अधिकृत किया है तो उसे मेडिकल प्रतिनिधि मानने में चिकित्सकीय या नैतिक आपत्ति नहीं है। हालांकि, यह संबंधित कानून और जरूरी सुरक्षा उपायों के अधीन होगा। केंद्र और एनएमसी ने कहा कि मरीज होश में है और अपनी बात समझने की स्थिति में है तो इलाज के लिए उसकी सूचित और स्वैच्छिक सहमति ही पर्याप्त है। केवल इसलिए किसी रिश्तेदार के हस्ताक्षर या सहमति की मांग नहीं की जा सकती कि वह मरीज का रिश्तेदार है।

हलफनामे में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले से अपने पार्टनर को अधिकृत किया है कि वह उसके बेहोश या निर्णय लेने में असमर्थ होने की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी फैसले ले सके, तो पार्टनर को केवल उसके यौन अभिविन्यास के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को पहले से अपने भरोसेमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने के लिए नामित करने की अनुमति है। यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसका रक्त संबंधी ही हो। ऐसे में मरीज की ओर से पहले से किया गया अधिकृत नामांकन महत्वपूर्ण होगा। यह हलफनामा अरशिया टक्कर की याचिका पर दाखिल किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि अस्पतालों और डाक्टरों को निर्देश दिए जाएं कि वे मरीज के अधिकृत गैर-विषमलैंगिक पार्टनर को मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें।

संपादकीय

महंगाई की दोहरी मार, आम आदमी की जेब पर बढ़ रहा बोझ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खुदरा महंगाई की दर अगस्त में क्रमशः 5.23 फीसद और 4.31 फीसद दर्ज की गई। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा किसानों को उचित उत्पादन और भंडारण सुविधाएं देने की जरूरत है।जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है, जिसकी आय कम होती है और संसाधनों का दायरा भी सीमित होता है। भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यकताओं पर बढ़ता खर्च इन परिवारों के बजट को बिगाड़ देता है। सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी महंगाई के आंकड़ों से साफ है कि आम लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है।खाद्य, ईंधन एवं विनिर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ने से अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 9.92 फीसद, जबकि खुदरा महंगाई 4.82 फीसद पर पहुंच गई है। इससे पिछले माह जुलाई में यह क्रमशः 9.78 फीसद और 4.45 फीसद थी। जनवरी से लागू 2024 आधार वर्ष वाली नई शृंखला के बाद से अगस्त की खुदरा महंगाई का यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक है।यही नहीं, अगले माह से यूपीआइ के जरिए दो हजार रुपए से अधिक की राशि के भुगतान पर भी शुल्क लगेगा। सरकार की ओर से मंगलवार को तय की गई शुल्क दरों में हालांकि आम लोगों के बीच यूपीआइ से लेन-देन को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन अन्य सरकारी एवं निजी सेवाओं के लिए भुगतान पर शुल्क देना होगा। यानी आम आदमी को अब महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खुदरा महंगाई की दर अगस्त में क्रमशः 5.23 फीसद और 4.31 फीसद दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के दाम ज्यादा बढ़े हैं, जहां लोगों की आय सीमित होती है। प्याज की महंगाई दर का जुलाई के 22.54 फीसद की तुलना में अगस्त में उछलकर 48.27 फीसद पर पहुंचना दर्शाता है कि प्याज आम लोगों की रसोई से गायब होने लगा है।यही हाल लहसुन और अदरक का भी है। ऐसे में निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। आय में वृद्धि अगर महंगाई की गति से कम हो, तो घरेलू बजट को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसमें दोराय नहीं कि अगले माह की शुरुआत में जब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी, तब नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला करने में महंगाई का यह बढ़ा हुआ स्तर एक प्रमुख कारक साबित हो सकता है।यह भी महत्त्वपूर्ण है कि महंगाई का असर केवल घरेलू बजट तक सीमित नहीं रहता। जब लोगों की क्रय शक्ति घटती है, तो बाजार में मांग भी प्रभावित होती है। यानी इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।

गांधी के लिए लोकतंत्र केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं था, बल्कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था था। वे लोकतंत्र को अहिंसा, अनुशासन, आत्मसंयम और नागरिक चेतना से जोड़ते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि लोकतंत्र हिंसा और असत्य के सहारे कायम नहीं रह सकता। विंस्टन चर्चिल का प्रसिद्ध कथन भी लोकतंत्र की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता हैकृ लोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणाली है, उन सभी प्रणालियों को छोड़कर जिन्हें आजमाया जा चुका है। यह कथन लोकतंत्र की कमियों को स्वीकार करते हुए भी उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित करता है। लोकतंत्र पूर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसमें आत्म-सुधार की क्षमता है। जनता सरकार को चुन सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है-सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण।

शांति, स्वतंत्रता और समानता का बुनियादी स्तंभ है लोकतंत्र

(ललित गर्ग)

लोकतंत्र की दूसरी बड़ी आवश्यकता है संवाद की संस्कृति। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। सरकार से प्रश्न पूछना राष्ट्र-विरोध नहीं; विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र-विरोध नहीं; मीडिया द्वारा सत्ता से जवाब मांगना व्यवस्था-विरोध नहीं। बल्कि यही लोकतंत्र की जीवंतता के प्रमाण हैं। लोकतंत्र केवल मतपत्र पर लगाई गई मुहर का नाम नहीं है। यह उस विश्वास का नाम है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज, अपनी गरिमा और अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र-निर्माण में सहभागी होने का अवसर मिलता है। एक तरह से शांति, स्वतंत्रता, समानता एवं सह-जीवन का बुनियादी स्तंभ है लोकतंत्र। हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसी लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिवस की स्थापना की थी और 2008 से इसका आयोजन हो रहा है। 2026 में अंतर-संसदीय संघ-आईपीयू ने लोकतंत्र दिवस के लिए मानवाधिकारों को केंद्र में लाएं को प्रमुख विषय बनाया है। इसका संदेश स्पष्ट है कि मानवाधिकार लोकतंत्र के सजावटी तत्व नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी शर्त हैं। मानवाधिकार सुरक्षित नहीं हैं तो चुनाव, संसद और संविधान की मौजूदगी के बावजूद लोकतंत्र अधूरा रहेगा। आज दुनिया के सामने लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या लोकतंत्र केवल संस्थागत ढांचे के रूप में जीवित है या उसके भीतर नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संवाद और मानवीय गरिमा भी सुरक्षित हैं? संयुक्त राष्ट्र भी 2026 में लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित न मानते हुए मानवाधिकार, कानून के शासन और नागरिकों की सार्थक भागीदारी को उसकी अनिवार्य आत्मा मान रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। लेकिन इसकी कमजोरी भी यहीं से शुरू होती है। जब जनता अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जब चुनाव जाति, धर्म, क्षेत्र, धनबल, बाहुबल या झूठे प्रचार के प्रभाव में आने लगते हैं, तब लोकतंत्र का बाहरी ढांचा तो बचा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। आज दुनिया के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर दबाव दिखाई देता है तथा सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कई समाजों में चिंता का कारण बन रही है। लोकतंत्र के नाम पर चुनाव हो जाना पर्याप्त नहीं है। यदि चुनाव के बाद नागरिकों की आवाज को महत्व न मिले, विपक्ष को शत्रु समझा जाए, मीडिया स्वतंत्र न रहे, न्यायपालिका पर दबाव हो और सत्ता जवाबदेही से मुक्त होने लगे, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे बहुमत की निरंकुशता में बदल सकता है। महात्मा गांधी का लोकतंत्र संबंधी चिंतन आज भी इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था- मेरे विचार में लोकतंत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति को वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मिलता है। गांधी के लिए लोकतंत्र केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं था, बल्कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था था। वे लोकतंत्र को अहिंसा, अनुशासन, आत्मसंयम और नागरिक चेतना से जोड़ते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि लोकतंत्र हिंसा और असत्य के सहारे कायम नहीं रह सकता। विंस्टन चर्चिल का प्रसिद्ध कथन भी लोकतंत्र की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता हैकृ लोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणाली है, उन सभी प्रणालियों को छोड़कर जिन्हें आजमाया जा चुका है। यह कथन लोकतंत्र की कमियों को स्वीकार करते हुए भी उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित करता है। लोकतंत्र पूर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसमें आत्म-सुधार की क्षमता है। जनता सरकार को चुन सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है-सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। जहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा, क्रांति या रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ती और मतदाता अपनी इच्छा से सरकार बदल सकता है, वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक हैं। आज लोकतंत्र के सामने एक नई और जटिल चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और डिजिटल तकनीक के रूप में भी सामने आई है। तकनीक लोकतंत्र को अधिक सहभागी और पारदर्शी बना सकती है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, नागरिक शिकायतों के समाधान, नीति-निर्माण में आंकड़ों के उपयोग और जनता की राय को शासन तक पहुंचाने में एआई उपयोगी हो सकता है। लेकिन यही तकनीक गलत सूचना, डीपफेक, लक्षित दुष्प्रचार, हेट स्पीच और जनमत को प्रभावित करने का माध्यम भी बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी एआई की इन संभावनाओं और जोखिमों के बीच संतुलन तथा उसके जिम्मेदार शासन की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए लोकतंत्र का डिजिटल भविष्य केवल तकनीकी क्षमता से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि तकनीक के पीछे मानवीय विवेक कितना मजबूत है। एआई लोकतंत्र का विकल्प नहीं, लोकतांत्रिक विवेक का सहायक होना चाहिए। तकनीक नागरिक को नियंत्रित करने का उपकरण नहीं, नागरिक को सशक्त करने का माध्यम बने- यही लोकतांत्रिक तकनीकी संस्कृति की कसौटी होनी चाहिए। लोकतंत्र की दूसरी बड़ी आवश्यकता है संवाद की संस्कृति। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। सरकार से प्रश्न पूछना राष्ट्र-विरोध नहीं; विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र-विरोध नहीं; मीडिया द्वारा सत्ता से जवाब मांगना व्यवस्था-विरोध नहीं। बल्कि यही लोकतंत्र की जीवंतता के प्रमाण हैं। जब असहमति को दबाया जाता है, तब लोकतंत्र का संवाद समाप्त होता है और उसके स्थान पर भय जन्म लेता है। इसीलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र जरूरी है। जो राजनीतिक संगठन अपने भीतर विचार-विमर्श, पारदर्शिता और नेतृत्व परिवर्तन की स्वस्थ परंपरा नहीं रखते, वे व्यापक समाज में लोकतांत्रिक संस्कार कैसे विकसित कर सकते हैं? लोकतंत्र की शुरुआत संसद से पहले राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के भीतर होनी चाहिए। साथ ही लोकतंत्र को केवल राष्ट्रीय सत्ता तक सीमित रखना भी उचित नहीं। पंचायत, नगर निकाय और स्थानीय संस्थाएं लोकतंत्र की वास्तविक पाठशाला हैं। जिस लोकतंत्र में गांव का नागरिक अपने स्थानीय निर्णयों में सहभागी नहीं है, उसमें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण अधूरा है। गांधी का ग्राम स्वराज इसी व्यापक लोकतांत्रिक दृष्टि का प्रतीक था-सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को भी यह समझना होगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। मतदान करना ही नागरिकता की पूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। सही सूचना प्राप्त करना, संविधान और कानून का सम्मान करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और गलत नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना भी नागरिक धर्म है। अंततः लोकतंत्र कोई तैयार होकर मिल जाने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि निरंतर साधना है। उसे हर पीढ़ी को अपने आचरण, संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मजबूत करना पड़ता है। लोकतंत्र तभी सार्थक है जब सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो, संस्थाएं स्वतंत्र हों, मानवाधिकार सुरक्षित हों, कमजोर को न्याय मिले, असहमति का सम्मान हो और नागरिकों को यह विश्वास हो कि शासन वास्तव में उनके कल्याण के लिए है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विविधता और जनभागीदारी का अद्भुत उदाहरण है।

ब्रिक्स में भारत की शानदार कूटनीतिक सफलता ने ब्रांड मोदी को और मजबूत कर दिया है

(नीरज कुमार दुबे)

भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता।

दिल्ली में हुई ब्रिक्स शिखर बैठक को अगर केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मानकर देखा जाएगा तो उसकी असली राजनीतिक अहमियत समझ में नहीं आएगी। देखा जाये तो यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव, युद्ध, अविश्वास और बदलते शक्ति-संतुलन से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत ने जिस तरह अलग-अलग ध्रुवों के देशों को एक मंच पर बैठाया, संवाद के रास्ते खोले और मतभेदों के बावजूद सहयोग की जमीन तैयार की, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर सामने आई है।

ब्रिक्स की इस बैठक की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि भारत ने उन देशों के बीच भी संवाद की संभावना पैदा की, जिनके बीच गहरे मतभेद हैं। ईरान और खाड़ी के देशों के बीच बातचीत इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। पश्चिम एशिया लंबे समय से टकराव, अविश्वास और संघर्ष का मैदान बना हुआ है। ऐसे समय में दिल्ली का मंच बातचीत के लिए उपलब्ध होना अपने आप में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अलग-अलग पक्षों से संवाद करते हुए अपने लिए स्वतंत्र कूटनीतिक स्थान बना सकता है।

भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता। यही वह बिंदु है जहां मोदी की कूटनीति की ताकत दिखाई देती है। अमेरिका से संबंध भी कायम हैं, रूस के साथ रिश्ते भी बने हुए हैं, चीन से संवाद भी हो रहा है और पश्चिम एशिया के अलग-अलग देशों के साथ भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। यानी भारत किसी एक शक्ति के पीछे चलने के बजाय अपनी शर्तों पर संबंधों का संतुलन साध रहा है।

यही सफलता उस राजनीतिक नैरेटिव को भी कमजोर करती है, जिसमें बार-बार यह सवाल उठाया जाता रहा कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मक्का समझौता कर लिया, दूसरे देशों के साथ अपने समीकरण बना लिए और क्षेत्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ीं तो क्या भारत की विदेश नीति असफल हो गई? विदेश नीति को केवल पड़ोस की तत्काल घटनाओं से मापना वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देना है। असली सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को किस नजर से देख रही हैं और संकट के समय कितने देश भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की बैठक ने इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे दिया है।

यहां प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग की तस्वीरें जिस तरह वैश्विक स्तर पर चर्चा में आई हैं, उनका राजनीतिक संदेश तस्वीर से कहीं बड़ा है। यह तस्वीर बताती है कि भारत का नेतृत्व एक साथ दुनिया की अलग-अलग शक्तियों के साथ संवाद करने की स्थिति में है। पश्चिमी देशों के लिए भी यह संदेश महत्वपूर्ण है कि भारत को नजरअंदाज करके वैश्विक राजनीति की कोई बड़ी रणनीति पूरी नहीं हो सकती।

इसका घरेलू राजनीतिक असर भी कम नहीं होगा। भाजपा लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत वैश्विक छवि को अपनी राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करती रही है। ब्रिक्स की दिल्ली बैठक उस पूंजी को और मजबूत करने का अवसर देती है। विपक्ष यदि यह कहता है कि सरकार की विदेश नीति कमजोर पड़ गई है, तो भाजपा के पास दिल्ली में जुटे वैश्विक नेताओं, भारत की मध्यस्थ भूमिका और अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ संवाद को सामने रखने का मजबूत राजनीतिक आधार तैयार हो गया है।

सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मिली यह कूटनीतिक सफलता केवल एक शिखर सम्मेलन की सफलता बनकर नहीं रहने वाली। इसका सीधा और दीर्घकालिक लाभ भारत की सामरिक स्थिति को मिल सकता है। रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप, ईरान और खाड़ी देशों जैसे अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ एक साथ संवाद कायम रखने की मोदी की क्षमता ने यह संदेश दिया है कि भारत किसी दबाव या धड़े की राजनीति में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ संबंध तय करने की स्थिति में है। इसका असर आने वाले समय में व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक सहयोग और भारत की वैश्विक हैसियत, हर मोर्चे पर दिखाई दे सकता है।

यूपीआई शुल्कः सुविधाओं का विस्तार या उपभोक्ता पर बोझ?

-: ललित गर्गः-

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूपीआई केवल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक, टैक्सी से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक और घरेलू लेन-देन से लेकर व्यावसायिक भुगतान तक-यूपीआई ने पैसे के लेन-देन की आदत, गति और भाषा तीनों बदल दी हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़े शुल्क की व्यवस्था केवल बैंकिंग या फिनटेक कंपनियों का कारोबारी विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता की आदत, छोटे व्यापार की लागत और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा से है। यहां एक तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। सितंबर 2026 में सरकार ने जो नया ढांचा स्पष्ट किया है, उसके अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति यानी पी2पी को यूपीआई भुगतान किसी भी राशि पर निःशुल्क रहेगा। रू.2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर भी एमडीआर नहीं है। रू.2,000 से अधिक के कुछ पी2एम यानी ग्राहक से व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर का प्रावधान किया गया है और रू.75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर प्रति लेन-देन अधिकतम रू. 300 की सीमा रखी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूल किया जाने वाला लेन-देन शुल्क नहीं है, बल्कि व्यापारी-पक्ष का एमडीआर है। फिर भी इस बदलाव को केवल 'शुल्क लगा या नहीं लगा' के प्रश्न तक सीमित करना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और उसकी लागत किसके हिस्से में जाए। यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सरलता और लगभग बिना लागत की अनुभूति रही है। अगस्त 2026 में यूपीआई पर करीब 24.51 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग रू.29.82 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई अब किसी वैकल्पिक भुगतान माध्यम की श्रेणी में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक जीवन के बुनियादी ढांचे में शामिल हो चुका है। यूपीआई के इस विस्तार के पीछे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। लोगों ने डिजिटल भुगतान को केवल सुविधा नहीं, स्वाभाविक व्यवहार मान लिया है। पहले दस रुपये, पचास रुपये या सौ रुपये के लिए जेब से नकद निकालना सामान्य थाय आज वही भुगतान मोबाइल से कुछ सेकंड में हो जाता है। जब कोई सेवा वर्षों तक निःशुल्क उपलब्ध रहती है तो उपभोक्ता उसके पीछे मौजूद तकनीकी, बैंकिंग और साइबर-सुरक्षा लागत को लगभग भूल जाता है। इसलिए बाद में किसी प्रकार का शुल्क या लागत सामने आने पर स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा होती है।

यहीं आधुनिक बाजार व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति दिखाई देती है। अनेक डिजिटल और उपभोक्ता सेवाएं पहले मुफ्त, अत्यंत सस्ती या भारी छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ता को उस सुविधा का अभ्यस्त बनाया जाता है, बाजार में उसका व्यवहार बदलता है और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के बाद लागत की नई संरचना सामने आती है। ओला-उबर जैसी सेवाओं से लेकर ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सदस्यता और विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं तक इस मॉडल के अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर मामले में यही रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है-यदि किसी सेवा की दीर्घकालिक लागत है तो उसकी जानकारी शुरुआत से स्पष्ट क्यों न हो? यूपीआई के मामले में यह प्रश्न और गंभीर है क्योंकि इसके उपयोगकर्ता केवल शहरी मध्यमवर्ग नहीं हैं। छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू उद्यमी, ग्रामीण उपभोक्ता

और पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग भी इसके बड़े हिस्से हैं। सरकार की 2025 की प्रोत्साहन योजना में भी छोटे व्यापारियों के रू.2,000 तक के भीम-यूपीआई भुगतान को शून्य एमडीआर के दायरे में रखते हुए रू.1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और भुगतान ढांचे को मजबूत करना था। इसलिए शुल्क की किसी भी व्यवस्था का पहला सिद्धांत होना चाहिए-छोटे भुगतान और छोटे कारोबार की रक्षा। रू.100, रू.500 या रू.1,000 के भुगतान पर लागत बढ़ाने वाला मॉडल डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत जा सकता है। इसके विपरीत बड़े व्यावसायिक भुगतान से जुड़ी लागत को अलग तरीके से देखा जा सकता है, बशर्ते शुल्क पारदर्शी, सीमित और पूर्व घोषित हो तथा उसका भार अनुचित रूप से ग्राहक पर न डाला जाए। यहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। यूपीआई के व्यापक प्रसार ने कार्ड भुगतान को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में पीछे धकेला है। यदि यूपीआई के कुछ बड़े व्यापारी लेन-देन पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारी वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर देख सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यम फिर कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे भुगतान बाजार में विविधता बढ़ सकती है, लेकिन यदि उपभोक्ता को हर माध्यम में अलग-अलग शुल्क, सुविधा और शर्तों का सामना करना पड़े तो डिजिटल भुगतान की सरलता कमजोर भी हो सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य केवल माध्यम बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ता को बेहतर विकल्प देना होना चाहिए। दूसरी ओर यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने की भी कीमत है। भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे चलाने के लिए बैंकिंग सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियां, ग्राहक सहायता और तकनीकी उन्नयन पर लगातार खर्च होता है। जैसे-जैसे लेन-देन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विश्वसनीयता और क्षमता पर निवेश की आवश्यकता भी बढ़ती है। सरकार की 2025 की योजना में भी तकनीकी विफलताओं को घटाने और सिस्टम अपटाइम सुधारने को प्रोत्साहन से जोड़ा गया था। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यूपीआई की हर सेवा हमेशा मुफ्त रहे या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि उसकी लागत का न्यायपूर्ण और पारदर्शी वितरण कैसे हो। सरकार, बैंक, फिनटेक कंपनियां और भुगतान नेटवर्क यदि इस व्यवस्था से आर्थिक लाभ लेते हैं तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा, विश्वसनीयता और नवाचार पर पर्याप्त निवेश हो। शुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि बेहतर डिजिटल भुगतान व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात उपभोक्ता विश्वास की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है। यदि आज किसी सेवा को 'मुफ्त' बताया जाए और कल अचानक उसकी लागत सामने आए, तो उपभोक्ता में अविश्वास पैदा हो सकता है। इसलिए भविष्य में किसी भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था की शुरुआत करते समय उसकी संभावित लागत, शुल्क संरचना और उसे लागू करने की परिस्थितियां पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि कौन-सी सेवा निःशुल्क है, किस पर लागत है, लागत कौन वहन करेगा और उसका अधिकतम स्तर क्या होगा। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है। ऐसे समय में यूपीआई की सफलता को केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता, सुरक्षा, पहुंच और उपभोक्ता विश्वास से मापना होगा। भारत की विकास-आकांक्षाओं के लिए उत्पादकता, नवाचार और मजबूत डिजिटल आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारत की उत्पादकता और नवाचार क्षमता को दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। यूपीआई शुल्क की बहस इसलिए वास्तव में 'शुल्क बनाम मुफ्त' की बहस नहीं है। यह उस आर्थिक दर्शन की परीक्षा है जिसमें डिजिटल सुविधा आम आदमी तक सस्ती, सरल और सुरक्षित रूप में पहुंचती है। छोटे भुगतान मुफ्त रहें, छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक भार न पड़े, बड़े व्यावसायिक लेन-देन में लागत की तार्किक व्यवस्था हो, शुल्क की जानकारी पहले से सार्वजनिक हो और उससे प्राप्त संसाधन भुगतान प्रणाली की सुरक्षा व क्षमता बढ़ाने में लगें, ऐसा संतुलन ही टिकाऊ रास्ता हो सकता है। भारत को डिजिटल भुगतान का विस्तार रोकना नहीं, बल्कि उसकी अगली पीढ़ी तैयार करनी है। यूपीआई की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने भुगतान को बैंक की शाखा और बटुए की सीमा से निकालकर मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचा दिया। अब अगली चुनौती यह है कि यह सुविधा आर्थिक रूप से टिकाऊ भी रहे और आम उपभोक्ता के लिए सहज भी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत में डिजिटल भुगतान केवल तकनीक नहीं, आर्थिक जीवन की धड़कन है। इसलिए इसकी कीमत तय करते समय बाजार की कमाई से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए- 'उपभोक्ता का विश्वास, छोटे कारोबार की क्षमता और डिजिटल भारत की दीर्घकालिक विश्वसनीयता।'

300 लक्जरी और स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 179 ई रिक्शा चालकों को पढ़ाया नियमों का पाठ

हरिद्वार, एजेंसी। लग्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में विभाग की टीमों ने जिले के विभिन्न मार्गों और प्रमुख स्थानों पर बसों की जांच की. पिछले पांच दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाली 300 बसों का चालान किया गया, 80 बसें सीज की गई. इसके साथ ही तकनीकी मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली पांच बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किए गए. सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी प्रशासन निखिल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर 179 तिपहिया वाहनों का चालान किया. मानकों का उल्लंघन करने पर 21 वाहन सीज कर दिए गए. हाईवे पर एआरटीओ नेहा झा संभाल रही मोर्चाः जिलाधिकारी

मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अलग-अलग टीमों का गठन किया है. एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में चंडीघाट चौक, भूपतवाला और बहादराबाद क्षेत्र में बड़ी बसों की चेकिंग की जा रही है. अलग-अलग टीमें पिछले पांच दिनों से तकनीकी स्थिति और फिटनेस मानकों की जांच कर रही है. इसके अलावा बसों के परमिट, फिटनेस, कर, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, स्वीकृत वाहन संरचना और सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की गई. जांच के दौरान बसों में अनधिकृत परिवर्तन, परमिट शर्तों का उल्लंघन, बसों में अतिरिक्त सीटें लगाना, पर्दे लगाकर चलना और यात्री सूची उपलब्ध नहीं होने जैसी अनियमितताएं मिलीं. कई बसों में सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी, फायर सेफ्टी यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होना, रिफ्लेक्टर में कमी, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल और चालक परिचालक के निर्धारित वर्दी में नहीं होने की भी बात सामने आई. परिवहन विभाग की विभिन्न प्रवर्तन टीमों ने अन्य श्रेणी के वाहनों की भी जांच कीः एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने, वाहनों में अनधिकृत परिवर्तन करने और परमिट और फिटनेस शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पिछले पांच दिनों में करीब 300 बस चालकों का चालान किया गया. 80 बसें सीज की गई है. लक्जरी और स्लीपर बसों समेत सभी यात्री और व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा. ई रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान, 179 वाहनों के चालान एवं 21 वाहन सीजः इसके साथ ही परिवहन विभाग की टीमें छोटे सवारी वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटी है. मंगलवार को तिपहिया वाहनों में में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, कर एवं आवश्यक प्रपत्रों के वाहन संचालित करने सहित विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं. अभियान में इंटरसेप्टर प्रभारी वरुणा सैनी एवं टास्क फोर्स चिड़ियापुर के मुकेश भारती द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई.

इनके अभियान में रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के अतिरिक्त दोपहिया, बस, मालवाहक, मोटर कैब, मैक्सी कैब तथा अन्य श्रेणी के वाहनों की भी जांच की गई. परिवहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 179 वाहनों के चालान किए गए और गंभीर अनियमितता वाले 21 वाहनों को सीज किया गया. इसके अतिरिक्त 65 मामलों में वाहन संबंधी दस्तावेज इम्पाउंड किए गए. चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग, बिना वैध बीमा, परमिट, कर एवं ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन संचालन, परमिट शर्तों का उल्लंघन, वाहन में अनधिकृत परिवर्तन, मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाने और रिफ्लेक्टर एवं सीट बेल्ट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

दुर्गम चट्टान से अलकनंदा नदी में उतरा शख्स, कुछ सेकंड तैरने के बाद हुआ ओझल, तलाश शुरू

कर्णप्रयाग, एजेंसी। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में तैरने के बाद एक व्यक्ति बह गया. व्यक्ति के बहने की सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस का नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है. व्यक्ति के परिजनों का कहना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था. पुलिस को लोगों द्वारा मिली सूचना के मुताबिक, मंगलवार को कर्णप्रयाग नगर में पोखरी विकासखंड निवासी सतीश कुमार खाली, नदी के बीच एक दुर्गम चट्टान पर खड़ा था. कुछ देर बाद वह चट्टान से नदी की ओर उतरा और तैरते हुए आगे बढ़ने लगा. लेकिन अलकनंदा के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया. सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और उसकी तलाश शुरू कर दी. एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें नदी में संभावित स्थानों पर सर्च अभियान चला रही है. पुलिस के मुताबिक, सतीश कुमार खाली अचानक घर से निकल गया था. परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान था. उधर, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि, जिस चट्टान से सतीश नदी में उतरा वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है. स्थानीय लोगों के अनुसार जिस चट्टान पर सतीश दिखाई दिया, वहां न तो सामान्य रास्ते से पहुंचा जा सकता है और न ही आसानी से रस्सी के सहारे वहां पहुंचना संभव है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सतीश नदी को तैरकर उस दुर्गम चट्टान तक पहुंचा होगा. लोगों के मुताबिक, सतीश अच्छा तैराक था. चट्टान पर पहुंचने के बाद वह कुछ समय तक वहां दिखाई देता रहा. इसके बाद उसने अलकनंदा नदी में उतरकर तैरना शुरू किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह काफी दूरी तक नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन धीरे-धीरे नदी का बहाव तेज होता गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया. हालांकि, सतीश उस दुर्गम चट्टान तक आखिर कैसे पहुंचा इसे लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है. हालांकि उसके तैराक होने और चट्टान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नदी तैरकर वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

बारिश के बाद दर्दनाक हादसा, खेलते समय तेज बहाव में बहा सात साल का बच्चा, एक किमी दूर मिला शव

चमोली, एजेंसी। मूसलाधार बारिश के बाद घनसाली के दोणी गांव में अचानक बढ़े पानी के बहाव ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। मंगलवार शाम खेलते समय लापता हुआ सात वर्षीय आरव रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद बुधवार सुबह मृत मिला। मंगलवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद तहसील घनसाली क्षेत्र के ग्राम दोणी में दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के पास खेलते समय सात वर्षीय बच्चा तेज पानी के बहाव में बह गया। आज बुधवार सुबह करीब घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर नदी से बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। बताया गया कि आरव पुत्र अरविंद, उम्र सात वर्ष, निवासी ग्राम दोणी, घनसाली मंगलवार देर शाम गांव के पास गदेरे में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक बढ़े पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से वह बह गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर थाना घनसाली पुलिस और एसडीआरएफ घनसाली की टीम ने तत्काल खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। देर रात तक बच्चे की तलाश की गई। बुधवार सुबह भी अभियान जारी रखा गया। थानाध्यक्ष अजय कुमार जाटव ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर नदी से बालक का शव बरामद कर लिया गया। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार बच्चे के शव को सीएचसी बेलेश्वर ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद ग्राम दोणी में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

नौ किमी पैदल चलकर सकंड गांव पहुंचे डीएफओ-एसडीएम, ग्रामीणों को सड़क की मंजूरी का दिया लिखित आश्वासन

चमोली, एजेंसी। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों के श्रमदान से सड़क कटिंग शुरू करने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच करीब दो घंटे चली बैठक के बाद फिलहाल वन भूमि पर निर्माण रोकने पर सहमति बनी। सड़क सुविधा से वंचित सकंड गांव के ग्रामीणों द्वारा खुद सड़क निर्माण शुरू किए जाने के बाद प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता की। डीएफओ और एसडीएम करीब नौ किमी पैदल चलकर गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की। ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। सड़क स्वीकृति नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क कटिंग का काम शुरू कर दिया था। प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को वन अधिनियम के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि स्वीकृति मिलने तक वन भूमि पर सड़क निर्माण का काम नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यदि तीन माह में सड़क की स्वीकृति नहीं मिली तो वे फिर एकजुट होकर सड़क निर्माण शुरू करेंगे।

एनएच के पास मकानों में दरारें बढ़ने से ग्रामीण चिंतित

गरमपानी, एजेंसी। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगोरी, मनरसा और जेएनवी सुयालबाड़ी क्षेत्र की सड़कों और लोगों के घरों पर दरारें पड़ने से ग्रामीण परेशान हैं। क्षेत्र में 12 से अधिक मकानों के नीचे की जमीन में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। साथ ही बारिश के बीच भू-धंसाव का सिलसिला जारी रहने से मकानों को खतरा बना हुआ है। ग्राम प्रधान नीमा देवी ने बताया कि क्षेत्र के चनी राम, नीरज कुमार, महेश लाल, आनंद राम, महेश राम, ईश्वर सिंह नेगी और प्रकाश सिंह आदि ग्रामीणों के भवनों और दुकानों में दरारें बढ़ने लगी हैं। उन्होंने कहा यदि भू-धंसाव इसी तरह जारी रहा तो केवल भवन ही नहीं, बल्कि ग्राम सभा की भूमि और खेती भी इसकी चपेट में आ सकती है। पूर्व ग्राम प्रधान अर्जुन नेगी ने बताया कोसी नदी से ऊपर की तरफ लगातार भूमि धंस रही हैं। वहीं एनएच के अधिकारी सड़क में आई दरारों को भरने में लगे हुए हैं।

ओजोन दिवसः श्रीनगर गढ़वाल में 26 दिन खराब रही हवा, चिंता बढ़ाने वाले हैं वायु गुणवत्ता के आंकड़े

पौड़ी, एजेंसी। हिमालय की गोद में बसे श्रीनगर की हवा को लेकर सामने आए एक साल के आंकड़े तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रहे हैं। प्रदूषण के महीन कणों के साथ ओजोन का बढ़ा स्तर भी शहर की वायु गुणवत्ता के लिए चिंता का कारण बना है। हिमालयी क्षेत्र की हवा को साफ-सुथरी मानने की धारणा के बीच श्रीनगर की वायु गुणवत्ता के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि की हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के एक साल के अध्ययन में पीएम-2.5 और पीएम-10(वायु में मौजूद बहुत छोटे और ठोस कण व तरल बूंदें) प्रमुख प्रदूषक पाए गए। वहीं 26 दिनों में ओजोन का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक रहा। 15 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2026 तक के 339 वैध दिनों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर मंगलवार को भौतिकी विभाग, चौरास परिसर में पांचवां ग्रीनहाउस गैस एवं वायु गुणवत्ता सूचना बुलेटिन जारी किया गया। अध्ययन के अनुसार पीएम-2.5 की औसत सांद्रता 73.30 माइक्रोग्राम और पीएम-10 की 100.48 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। पीएम-2.5 की मात्रा 169 दिन और पीएम-10 की मात्रा 146 दिन निर्धारित 24 घंटे की सीमा से अधिक रही। सबसे चौंकाने वाली स्थिति 19 दिसंबर 2025 को सामने आई, जब ओजोन का आठ घंटे का औसत 634.13 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। इसी दिन प्रति घंटे ओजोन की सांद्रता 880 माइक्रोग्राम से अधिक दर्ज की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में घाटी में प्रदूषकों के फंसने, स्थानीय स्तर पर बायोमास जलाने और मौसमीय

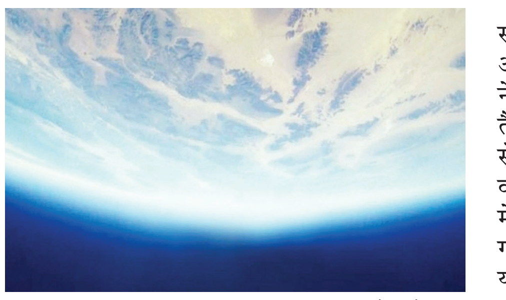

परिस्थितियों से इस घटना का संबंध हो सकता है। भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. त्रिलोक चंद्र उपाध्याय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ समाज तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने डॉ. गौतम और उनकी शोध टीम अमनदीप विश्वकर्मा, अंकित कुमार और सरस्वती रावतको जनहितकारी वैज्ञानिक पहल के लिए बधाई दी। हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के अन्वेषक डॉ. आलोक सागर गौतम ने कहा कि अध्ययन में मौसम के अनुसार प्रदूषण के स्तर में बदलाव भी सामने आया। सर्दियों में तापमान प्रतिलोमन के कारण पीएम बढ़ा, जबकि गर्मियों में अधिक तापमान और सौर विकिरण से ओजोन का स्तर बढ़ा। मानसून में बारिश के कारण पीएम अपेक्षाकृत कम रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी 22 दिन निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज हुआ। कहा कि धरातल के पास अधिक मात्रा में मौजूद ओजोन हानिकारक वायु प्रदूषक है।

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहारों के दौरान योगनगरी ऋषिकेश से कोलकाता के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

रुड़की, एजेंसी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। योगनगरी ऋषिकेश से कोलकाता के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे निर्धारित किए गए हैं। त्योहारों के दौरान रेलवे योगनगरी ऋषिकेश से कोलकाता के बीच विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। अमृतसर से कोलकाता और बरौनी के बीच भी दो विशेष ट्रेन चलेंगी। मुरादाबाद मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को ठहराव दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04311 - 12 कोलकाता - योगनगरी ऋषिकेश - कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 16 अक्तूबर से 22 नवंबर तक दोनों ओर से 6 - 6 फेरे किया जाएगा। योगनगरी ऋषिकेश से प्रत्येक शुक्रवार रात 10:20 पर रवाना

होकर ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, आलमनगर, उतरेटिया, रायबरेली, मां बेहला देवी प्रतापगढ़, वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भाबुआ रोड, सासाराम, देहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, नेताजी सुभाषचंद्र बोस गोमोह, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान, बांडेल, नेहाटी होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता से प्रत्येक रविवार दोपहर 1:55 पर रवाना होकर इन्हीं स्टेशनों से होकर ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश पहुंचेगी। सीनियर डीसीएम ने बताया कि गाड़ी संख्या 04623 - 24 अमृतसर - कोलकाता - अमृतसर एक्सप्रेस का संचालन 7 अक्तूबर से 28 नवंबर तक दोनों ओर से 8 - 8 फेरे किया जाएगा। ट्रेन प्रत्येक बुधवार को रात 8:10 पर अमृतसर से रवाना होकर दूसरे दिन 3 बजे कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता से प्रत्येक शनिवार सुबह 4:45 पर रवाना होकर ट्रेन अगले दिन रात 9:05 पर अमृतसर पहुंचेगी। जबकि गाड़ी संख्या 04667 - 68 अमृतसर - बरौनी - अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस 4 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक दोनों ओर से 9 - 9 फेरे संचालित की जाएगी। अमृतसर से प्रत्येक रविवार रात 8:10 पर ट्रेन का संचालन होगा। दूसरे दिन रात 2:10 पर ट्रेन बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। बरौनी जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार सुबह 5:05 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:50 पर ट्रेन अमृतसर पहुंचेगी। मुरादाबाद मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को ठहराव दिया गया है।

कुंभ की यादें, सनातन की अस्मिता लौटाएगा हरिद्वार अर्धकुंभ, भव्य-दिव्य के साथ दिखेगा बेहतर प्रबंधन

हरिद्वार, एजेंसी। हरिद्वार में होने वाला अर्धकुंभ इस बार सिर्फ आस्था का बड़ा आयोजन नहीं, बल्कि बेहतर व्यवस्थाओं की कसौटी भी बनने जा रहा है। पिछले कुंभ और स्नान पर्वों से मिले अनुभव के आधार पर भीड़, सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की तैयारी है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य रूप में आयोजित करने की सराहना की जा रही है। इसे नासिक, प्रयाग और उज्जैन के आयोजनों से बेहतर प्रबंधन वाला बताया जा रहा है। इस पर मेरा भी समर्थन है क्योंकि, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को जोड़ना है। इसका लक्ष्य सनातन धर्म की खोई अस्मिता को वापस लाना भी है। कुंभ के साथ स्नान पर्व और कांवड़ जैसी व्यवस्था के आयोजनों के अनुभव के कारण हरिद्वार को प्रबंधन में अग्रणी माना जा रहा है। यहां भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले आयोजनों से मिली सीख को इस बार लागू किया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है। वास्तव में हरिद्वार में कुंभ आयोजनों का एक लंबा इतिहास है। यह इतिहास प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने में सहायक रहा है। अर्धकुंभ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं देखा जा रहा है। यह सनातन मूल्यों के पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। इस प्रयास से धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की उम्मीद है। हरिद्वार को कुंभ आयोजनों के लिए एक अनुभवी स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां भीड़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की व्यवस्थाएं अन्य कुंभ स्थलों से बेहतर मानी जाती हैं। सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और स्वच्छता के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को एक सुगम और सुरक्षित अनुभव प्रदान किया जाएगा।

नदियों में खनिज निकासी फिलहाल सीमित, मानसून के बाद खनन राजस्व का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

देहरादून, एजेंसी। मानसून के दौरान नदियों में खनिज निकासी सीमित रहने के बाद अब विभाग की नजर बरसात के बाद की गतिविधियों पर है। पिछले वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य से कहीं अधिक राजस्व मिलने के बाद खनन विभाग नए रिकॉर्ड की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। मानसून के चलते प्रदेश की नदियों में खनिज निकासी फिलहाल सीमित है। बरसात के बाद अब खनन गतिविधियां दोबारा शुरू कर राजस्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड ने खनन से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक 1217 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया था। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 950 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, इसके मुकाबले 1217 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। कोषागार में 1130 करोड़ रुपये, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में 80 करोड़ रुपये और राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) के तहत 7 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1,041 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। खनन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में खनन राजस्व में पिछले 4.5 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में जहां खनन विभाग से करीब 110 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ

था, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा 1217 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सरकार ने खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नीतिगत और तकनीकी स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं। खनिज नीति और नियमावली में किए गए सरलीकरण के साथ वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। खनन प्रक्रिया की निगरानी के लिए माइनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया। इसके तहत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में 45 ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं। इनमें वाहनों की निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरा और आरएफआईडी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों से उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एमटीटीएसएस और और ई-खन्ना सिक्योरिटी पेपर परियोजनाओं को स्कॉच अवार्ड (गोल्ड) से सम्मानित किया गया। खान मंत्रालय की माइनर मिनरल रिफॉर्म श्रेणी में उत्तराखंड को 'सी' श्रेणी के राज्यों में दूसरा स्थान मिला।

उत्तरकाशी के आठ बच्चों में कॉक्ससैकी वायरस की पुष्टि, जल स्रोतों की निगरानी तेज

स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंताः

उत्तर काशी, एजेंसी। नैनीताल जिले के ज्योलीकोट में जिस तरह से दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने और मौत की घटना सामने आई थी, ऐसे में उत्तरकाशी के भंगेली गांव में बच्चों के बीमार होने की घटना डराने वाली है। उत्तरकाशी के भंगेली गांव में बीमार हुए 15 बच्चों में से आठ में कॉक्ससैकी वायरस की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञ वायरस से होने वाली बीमारी को हाथ, पैर और मुंह यानी एचएफएमडी बीमारी का नाम दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के अन्य बच्चों की भी जांच कर रही है। नैनीताल जिले के ज्योलीकोट में जिस तरह से दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने और मौत की घटना सामने आई थी, ऐसे में उत्तरकाशी के भंगेली गांव में बच्चों के बीमार होने की घटना डराने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर तो मुहर लगाई है कि बच्चे दूषित पानी से ही एचएफएमडी बीमारी की चपेट में आए हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वायरस पेयजल स्रोत से आने वाले पानी में था या अन्य स्रोत में। हालांकि जल संस्थान ने पेयजल के दूषित नहीं होने की दावा किया है। इसमें कितनी सच्चाई है यह जांच के बाद ही पता चल सकेगी। हालांकि जल संस्थान ने जल स्रोतों की निगरानी तेज कर दी है। भटवाड़ी समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. वेद मोइक के मुताबिक बच्चों के हाथ, पैर और मुंह पर दाने के अलावा तेज बुखार, गले में दर्द और भूख न लगने की शिकायत सामने आ रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जांच की तो इसके लक्षण एचएफएमडी बीमारी से मिलते-जुलते मिले। इस तरह के लक्षण वाले 15 बच्चों की जांच हुई तो आठ बच्चों में बीमारी की पुष्टि हुई। यह बीमारी आमतौर पर सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है। उत्तरकाशी जिले में वर्तमान में एक भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं

है। गांव में जब एक साथ कई बच्चे बीमार हुए तो स्वास्थ्य विभाग को उनके उपचार के लिए फिजिशियन को लगाना पड़ा। चिकित्सकों ने दूसरे जिलों के बाल रोग विशेषज्ञों से सलाह लेकर बच्चों को उपचार दिया। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बच्चों के उपचार के लिए बाल रोग विशेषज्ञ इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वह बच्चों की मानसिक और शारीरिक जरूरत को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसके अलावा दवाओं की खुराक भी तय करने में उनका योगदान है। इसमें शरीर के विकास का भी ध्यान रखना पड़ता है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के एचओडी डॉ. अशोक कुमार बताते हैं कॉक्ससैकी वायरस मुख्य रूप से दूषित सतहों में पनपता है। हाथ, पैर और मुंह के माध्यम से यह शरीर में संक्रमण पैदा करता है। यह एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत तेजी से फैलता है। ये एंटरोवायरस परिवार का हिस्सा है जो इंसानी पाचन तंत्र (आंतों) में जीवित रहता है और संख्या बढ़ाता है। कई बार यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रवाद को गति देने वाली भाषा है हिंदी

वाराणसी , एजेंसी। बीएचयू में पत्रकारिता विभाग की ओर से आयोजित हिंदी सप्ताह का समापन हुआ। संयुक्त कुलसचिव संजय कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी है। विभागाध्यक्ष प्रो. ज्ञानप्रकाश मिश्र ने कहा कि हिंदी को बिना किसी झिझक बोला जाता है। यह राष्ट्रवाद को गति देने वाली भाषा है। हिंदी लोकमंगल की भाषा है इसलिए इसे देवनागरी कहा गया है। डॉ. बाला लखेंद्र ने हिंदी को प्रतिस्पर्धा में आगे बताया। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. शोभना नार्लीकर ने किया।

शोध प्रवेश के लिए अब 25 तक कर सकेंगे आवेदन

गोरखपुर , एजेंसी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी।सीटों की स्थिति में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों की ओर से तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी। इसे देखते हुए कुलपति प्रो. कृष्ण पाल सिंह ने अभ्यर्थी हित में अंतिम तिथि बढ़ाने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में शोध प्रवेश के लिए इस सत्र में कुल 868 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें नियमित पूर्णकालिक, स्ववित्तपोषित पूर्णकालिक और पार्ट टाइम मोड की सीटें शामिल हैं। सीटों का विषयवार विवरण प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध है।

बरेका सुपरवाइजर क्लब समिति के सचिव बने मुकेश, सुरेंद्र कोषाध्यक्ष

वाराणसी , एजेंसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में सुपरवाइजर क्लब समिति के गठन के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी मुख्यालय राजकुमार गुप्ता की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें टीएएस में कार्यरत एसएसई (विद्युत) मुकेश कुमार डेहरिया सचिव और एसएसई (डिजाइन) सुरेंद्र प्रसाद सिंह कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सचिव पद के लिए मुकेश कुमार डेहरिया को 191 मत मिले। राजकुमार को 44 और सचिंद्र कुमार मिश्र को 20 मत प्राप्त हुए। वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 185 और चिन्मयानंद को 70 मत मिले। समिति के सदस्य पद पर जेई (प्लांट एंड टूल ऑफिस) अभय कुमार सिंह, एसएसई (स्मॉल टूल) जेएन गौरव और सीएमएससी एंड टी लैब के सत्येंद्र प्रसाद सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्लब की गतिविधियों को प्रभावी और सक्रिय बनाने के साथ ही सदस्यों के हित में सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य करने की बात कही।

ललिता घाट से गंगाजल लेकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे सेवा यात्री

वाराणसी , एजेंसी। ललिता घाट से 51 सेवा यात्री (बाइकर्स) गंगा जल भरकर डमरू दल की गूंज और शंखनाद के बीच बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। गंगाजल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष अनुष्ठान होंगे।क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नवरतन राठी ने बताया कि 17 सितंबर को कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक एवं सांसद वीडी शर्मा काशी में और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी वडनगर में सेवा यात्रियों के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष से निकलने के बाद सेवा यात्रियों का वाराणसी की सीमा तक लगभग दस स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया जाएगा। यात्रा को लेकर इन स्थानों पर तैयारियां की जा रही हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा का एक माह का 'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। काशी से वडनगर तक निकलने वाली बाइक यात्रा इसी अभियान का प्रमुख हिस्सा है। गंगा जल से भरे कलश, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, डमरुओं की गूंज और शंखनाद के बीच शुरू होने वाली यह यात्रा काशी की धार्मिक आस्था को सेवा और संकल्प के संदेश से जोड़ेगी।

नुक्कड़ नाटक में दिया पोषण का संदेश

लखनऊ, एजेंसी। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ग्रामीण पोषण जागरूकता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने चक्करपुरवा, प्रबंध नगर और मुबारकपुर गांव में ग्रामीणों को संतुलित आहार का महत्व समझाया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिये बताया गया कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए महंगे नहीं, बल्कि स्थानीय खाद्य पदार्थ लाभकारी होते हैं। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं (स्तनपान कराने वाली माताएं) के पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। निर्देशन गृह विज्ञान विभाग की डीन तत्हीर फात्मा ने किया। समन्वय में डॉ. कीर्तिमा सचान, डॉ. कल्पना देवी व डॉ. अंजलि सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बिजली बिल व मीटर जांच करने गई टीम से अभद्रता, हमले का आरोप

गोरखपुर , एजेंसी। पीपीगंज थानाक्षेत्र में बिजली बिल की वसूली और मीटर की जांच करने पहुंची बिजली निगम की टीम के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। संविदा लाइनमैन रंजय कुमार ने तीन लोगों के खिलाफ पीपीगंज पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजली उपकेंद्र पीपीगंज के रायपुर फीडर क्षेत्र में अवर अभियंता पप्पू कुमार के नेतृत्व में टीम सोमवार दोपहर करीब दो बजे घरों और प्रतिष्ठानों के मीटर की जांच और बकाया बिल जमा कराने पहुंची थी। आरोप है कि एक मेडिकल स्टोर से जुड़े कुछ लोगों ने मीटर खराब होने समेत अन्य बातों को लेकर कर्मचारियों से विवाद शुरू कर दिया और उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। इस दौरान विभागीय कागजात भी फाड़ दिए गए।

चुनावों से पहले हर वर्ग को खुश करने की कोशिश

किसानों को मिलेगा सस्ता लोन, अग्निवीरों को आरक्षण

लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने, किसानों को सस्ती दर पर ऋण और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर भी निर्णय लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी दी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ मंजूर : कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। इससे बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन सुगम होने और पर्यटन को गति मिलने की उम्मीद है।

परिषदीय विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल : बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।

किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर छह लाख तक ऋण : मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) और कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में

20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों विभागों में भूतपूर्व सैनिकों की भांति अग्निवीर के रूप में की गई 4 वर्ष की सेवा अवधि घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो। बता दें कि इससे पहले पुलिस विभाग में पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 20 फीसद आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। अब परिवहन विभाग में भी सिपाही के पद पर पूर्व अग्निवीर भर्ती हो सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा जल्द इस बाबत शासनादेश जारी किया जाएगा।

कारागारों की सुरक्षा होगी मजबूत : कारागारों में पूर्व अग्निवीरों की जेल वार्डर के पद पर भर्ती से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। जिन कारागारों में सामान्य अपराधियों के साथ आतंकवादी, कुख्यात अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता है, वहां पूर्व अग्निवीरों का प्रशिक्षण, अनुशासन-कौशल एवं अनुभव का उपयोग लाभकारी होगा। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए नये रोजगार सृजित होंगे।

पीआरडी जवानों और आश्रितों को कैशलेस इलाज : प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय हुआ। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को उपचार के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी।

खिलौना उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन : कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति से प्रदेश में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी।

ये फैसले भी महत्वपूर्ण

- उत्तर प्रदेश के अभियांत्रिकी विभागों में कार्य के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, जनपद मथुरा में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 केएलपीडी एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन पर अनुमोदन।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील स्थित ग्राम पूरे लाल खान में लगभग 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी।
- 10 वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव पास।
- प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन को मंजूरी।
- प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत।
- प्रदेश की उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला।

पोर्टल बंद होने से हजारों छात्रों का दाखिला अटका

कानपुर , एजेंसी। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) से संबद्ध महाविद्यालयों के हजारों छात्रों के दाखिले अटक गए हैं। यह समस्या समर्थ पोर्टल पर डब्ल्युआरएन की प्रक्रिया बंद होने से आई है। छात्रों ने पोर्टल खुलवाने की मांग शुरू कर दी है। कॉलेज प्रबंधक विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। विवि प्रशासन ने 31 अगस्त के बाद से पोर्टल नहीं खोला है, जबकि हर साल अक्तूबर से नवंबर तक यह प्रक्रिया चलती थी। इसी भ्रम में कई कॉलेजों ने छात्रों का दाखिला ले लिया, लेकिन अब पोर्टल न खुलने से दिक्कत हो रही है।

सीएसजेएमयू और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल पर छात्रों को अपना पंजीकरण कराना होता है। इस बार भी प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल से चल रही है। इसके बाद ही छात्र डिग्री कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। कई निजी महाविद्यालय छात्रों का दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन लापरवाही में डब्ल्युआरएन नहीं जनरेट करवाते हैं। हर साल विवि कॉलेजों के कहने पर दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाता रहा है।

इस बार कुलाधिपति ने सभी कुलपतियों के साथ बैठक कर इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए निर्देशित किया था। राज्यपाल का कहना था कि कॉलेजों में दाखिले की कोई एक तिथि दी जाए। बार बार तिथियों को विस्तारित न किया जाए। कुलाधिपति के निर्देश के बाद विवि ने भी दाखिले की प्रक्रिया बंद कर दी। इस कारण से हजारों छात्र अभी भी दाखिले के इंतजार में हैं। उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा कि डिग्री कॉलेजों में हजारों की संख्या में छात्र दाखिलों की कतार में हैं।

1600 कैडेटों को पीछे छोड़ हिमानी ने साधा गोल्ड

लखनऊ, एजेंसी। निशाना एक था... लेकिन उसे साधने के लिए हिमानी को कई पड़ाव पार करने पड़े। निशातगंज की रहने वाली 16 वर्षीय हिमानी ने यूपी के करीब 1600 एनसीसी कैडेटों के बीच अलग-अलग चरणों में अपनी जगह बनाते हुए दिल्ली के थल सैनिक कैंप-2026 तक का सफर तय किया। राष्ट्रीय कैंप में पहुंचकर उन्होंने स्नैप शूटिंग प्रतियोगिता के जूनियर विंग वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। आर्यकन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा हिमानी के साथ लखनऊ से चार अन्य कैडेट भी कैंप में पहुंचे थे लेकिन गोल्ड हिमानी के नाम रहा।

खास बात यह है कि हिमानी ने दो साल पहले जब एनसीसी जॉइन की थी, तब उनका मन इसमें नहीं था। धीरे-धीरे उन्हें एनसीसी का अनुशासन पसंद आने लगा और प्रशिक्षण ने उनकी रुचि को लक्ष्य में बदल दिया। थल सैनिक कैंप के दौरान उन्होंने फायरिंग राइफल से हथियार प्रशिक्षण लिया। इसके साथ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, हेल्थ व

हाइजीन और ड्रिल का गहन अभ्यास किया। कठिन प्रशिक्षण के बाद स्नैप शूटिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया।

हिमानी के पिता चंद्रपाल एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और मां पुष्पा देवी गृहिणी हैं। हिमानी ने अपनी उपलब्धि का श्रेय प्रधानाचार्य डॉ. ममता किरण राव, केयर टेकर ऑफिसर शिवानी पाण्डेय, 20 यूपी गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और लखनऊ ग्रुप एनसीसी के स्टाफ को दिया।

कर्नल सोफिया से मिली सेना में जाने की प्रेरणा : वर्ष 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय मीडिया का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी से हिमानी प्रभावित हुईं। उन्होंने बताया कि सेना में इतनी जांबाज महिला अफसर हैं, यह उन्होंने पहले नहीं सोचा था। इसके बाद उनके मन में भी सेना में जाने की इच्छा जगी। हिमानी अब सेना में शामिल होकर देश सेवा करना चाहती हैं।

पदक लेकर लौटीं तो विद्यालय में हुआ जश्न : सरकारी सहायता प्राप्त आर्यकन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में स्वर्ण पदक लेकर लौटने पर हिमानी का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. ममता किरण राव ने कहा कि हिमानी ने कठिन प्रशिक्षण में खुद को साबित कर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया है।

प्रदेश में वैवाहिक हिंसा में आई कमी, गांवों में अभी शहरों से दस फीसदी ज्यादा मामले; आंकड़ों में खुलासा

लखनऊ, एजेंसी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6: 2023-24) की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ होने वाली वैवाहिक हिंसा के मामलों में कमी आई है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में हालात अब भी चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान 3.7 फीसदी महिलाओं ने शारीरिक हिंसा झेली।

आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 18 से 49 साल की महिलाओं के साथ जीवनसाथी द्वारा की जाने वाली शारीरिक या यौन हिंसा का ग्राफ घटकर 28.5 प्रतिशत पर आ गया है। पिछले सर्वे (एनएफएचएस-5: 2019-21) में यह आंकड़ा 34.9 प्रतिशत था। शहरों में जहां 20.7 प्रतिशत महिलाएं हिंसा का शिकार हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 30.7 प्रतिशत है। साफ है कि गांवों में महिलाओं को अब भी ज्यादा प्रताड़ना

झेल रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 3.7 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान भी शारीरिक प्रताड़ना का सामना किया। पिछले सर्वे (हस्न॥स-5) के मुकाबले इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। गांवों (3.9 प्रतिशत) में यह दर शहरों (3.1 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा है। कम उम्र में यौन हिंसा की बात करें, तो 18 साल की उम्र से पहले यौन हिंसा झेलने का आंकड़ा मामूली रूप से घटकर 0.5 प्रतिशत (पहले 0.7 प्रतिशत) पहुंच गया है।

आर्थिक आजादी से बदलाव

हिंसा में आई इस कमी को महिलाओं की बढ़ती आर्थिक आजादी और जागरूकता से जोड़कर देखा जा रहा है। अब यूपी में 83.5 प्रतिशत महिलाओं का बैंक खाता है। इस मामले में ग्रामीण महिलाएं (84.3 प्रतिशत) शहरी महिलाओं (81 प्रतिशत) से आगे हैं। मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं की संख्या भी 46.5 प्रतिशत से बढ़कर 56.4 प्रतिशत हो गई है। नकद आय हासिल करने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी 15.5 प्रतिशत से सुधरकर 21.1 प्रतिशत हो गया है।

शिक्षा के चलते आई कमी

- शिक्षा के प्रचार प्रसार, आत्मनिर्भरता और जागरूकता के चलते शहरों में घरेलू हिंसा में ज्यादा कमी आई है। गांवों में शिक्षा व जागरूकता का ग्राफ अब भी कम है। इसलिए गांवों में घरेलू हिंसा के मामले कम नहीं हो रहे। हालांकि, गांवों में सरकारी योजनाओं, नशा उन्मूलन और रोजगार से घरेलू हिंसा कम हुई है।

प्रो. मानिनी श्रीवास्तव,
मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

तकनीकी आत्मनिर्भरता से बनेगा मजबूत भारत

लखनऊ, एजेंसी। तकनीक की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर ही भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, नवाचार और सतत विकास को प्राथमिकता देनी होगी। इसी संकल्प के साथ मंगलवार को रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में 59वां अभियंता दिवस मनाया गया। भारत र प्रतिशत सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स (इंडिया) के लखनऊ चैप्टर का शुभारंभ भी हुआ।

मुख्य अतिथि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष संदीप कुमार ने युवा अभियंताओं से नई तकनीक अपनाने और सतत विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। आईएमईआई के लखनऊ चैप्टर से मरीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तकनीकी गतिविधियों, ज्ञान के आदान-प्रदान और पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा। संस्था के अध्यक्ष इं. वीपी सिंह ने कहा कि इंजीनियर तकनीकी विकास के साथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देते हैं। मानद सचिव इं. एनके निषाद ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टैंकर तक पहुंचीं लपटें, कर्मचारियों ने सूझबूझ से टाला बड़ा हादसा

आगरा, एजेंसी। आगरा के प्रतापपुरा चौराहा (सदर) स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पंप पर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग पास ही खड़े पेट्रोल से भरे टैंकर तक पहुंच गई। उधर, आग की लपटों को देखकर ग्राहकों में अफरातफरी मच गई। हालांकि पंप कर्मियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया और महज 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया।

प्रतापपुरा चौराहे पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है। मंगलवार शाम तकरीबन 4:30 बजे टैंकर खाली होने के लिए आया था। कर्मचारी पाइप लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे। तभी टैंकर के पास दीवार पर लगे बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग टैंकर के नीचे तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे, लेकिन पंप कर्मचारियों ने साहस दिखाया।

अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़े और आग बुझाने लगे। कुछ ग्राहक भी उनके साथ जुट गए। इस दौरान पंप कर्मचारियों ने 15 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर आग को पूरी तरह से बुझा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइलों से वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पंप पर शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ था। पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते आग पर काबू पा लिया। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल को नहीं दी गई। फिर भी जांच के लिए पुलिसकर्मी पंप पर पहुंचे थे।

पोल्ट्री कॉन्क्लेव में 50 करोड़ के एमओयू हुए

- विशिष्ट अतिथि अपर निदेशक पशुपालन डॉ. अनिल कुमार गहलौत ने मंडल में पोल्ट्री उद्योग के विकास से रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया

अलीगढ़ , एजेंसी। पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिसमें पोल्ट्री फॉर्मों को डिजिटल करने पर जोर दिया गया। यहां पर 50 करोड़ के एमओयू किए गए।

संयोजक एवं सीवीओ डॉ. दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि विभाग और उद्यमियों के बीच 50 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए एमओयू हुए हैं। एमओयू करने

वालों में प्रतीक वार्ष्णेय, रॉबिन चौधरी, संजय तिवारी और अनुपम माहेश्वरी प्रमुख रहे। उद्यम में लगाई जाने वाली कुल पूंजी का 30 प्रतिशत पशुपालक द्वारा लगाया जाएगा और 70 प्रतिशत बैंक से लोन लिया जाएगा। ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक प्रबंधन, जैव-सुरक्षा, रोग नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, मार्केटिंग, निवेश एवं रोजगार सृजन पर जोर दिया। पोल्ट्री फॉर्म को डिजिटिलाइज्ड करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। शुभारंभ करते हुए मंडलायुक्त ओपी आर्य ने कहा कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जा सकता है।

विशिष्ट अतिथि अपर निदेशक पशुपालन डॉ. अनिल कुमार गहलौत ने मंडल में पोल्ट्री उद्योग के विकास से रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने उद्यमियों एवं किसानों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। अपर निदेशक डॉ. हौसला प्रसाद ने विभागीय प्रयास और भविष्य की संभावनाएं बताईं। कार्यक्रम में अपर निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. बृजेश त्रिपाठी, डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह, डॉ. पीके सिंह, पॉल्ट्री फॉर्म संचालक एवं किसान उपस्थित रहे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विवि के डॉ. प्रो. अमिताभ भट्टाचार्य, प्रमुख विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव और विचार साझा किए। कहा कि पोल्ट्री उद्योग केवल अंडा और मांस उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक कृषि-आधारित उद्योग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

देवछठः ब्रज के राजा का धूमधाम से मना प्रकटोत्सव

दर्शन करने को उमड़ा श्रद्धालुओं कीड

बलदेव। ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज का प्रकटोत्सव बलदेव नगरी में उल्लास के साथ गुरुवार को मनाया गया। आराध्य के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे मंदिर के पट खोले गए। श्री दाऊजी महाराज को विशेष पंचामृत अभिषेक, श्रृंगार और हीरा-जवाहरात के दर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। मंदिर में समाज गायन, भजन, नफीरी वादन एवं नंदोत्सव का आयोजन हुआ, जबकि 108 वेदपाठी व विद्वानों ने श्री बलभद्र पाठ और हवन-यज्ञ किया। श्रीदाऊजी महाराज का जन्मोत्सव बलदेव छठ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब सुबह से ही उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव पर विशेष दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री दाऊजी का विशेष पंचामृत स्नान व अभिषेक श्रृंगार हीरा जवाहरात के विशेष दर्शनों में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नफीरी की धुन पर महिलाएं मंदिर परिसर में भजनों पर थिरकते रहीं। समाज गायन में सेवायत श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव के पदों का गायन किया। जन्मोत्सव की खुशी में श्रद्धालुओं की भीड़-भाड़ सुबह से शाम तक उमड़ती रहीं। नंदोत्सव में नारियल फल प्रसाद लुटाए गए। सभी श्रद्धालु चारों ओर उमड़े श्रद्धालुओं ने दृश्य को देख कर आनंदित हो गये। मंदिर में विशेष रूप से 108 वेद पाठी व विद्वानों ने श्री बलभद्र पाठ का आयोजन किया। विशेष हवन यज्ञ किया गया। जिससे श्रद्धालु धन्य हो गये। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर में नफीरी वादन की धुन पर महिला व पुरुष युवतियां भजनों पर नाचते गाते हुए नजर आए। बोल श्री दाऊजी महाराज की जय जयकार बोल रेवती मैया की जय जयकार हुई। इस दौरान लगातार भीड़भाड़ उमड़ती रहीं।

नारियल लूटने की होड़ में गौपो का समूह, दधिकांधा की अनूठी है परम्परा – श्री दाऊजी महाराज के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में समाज गायन के बाद दोपहर एक बजे दधिकांधा का आयोजन किया गया। दही, हल्दी, केसर, मक्खन आदि से मिश्रित लाला की छीछी स्वरूप प्रसादी सेवायतो व भक्तों पर फेंकी गई। मंदिर की छत से नारियल, मेवा फल उपहार आदि लुटाये गए। जिसे लूटने के लिए गोपो का समूह लूटने की होड़ में लगा रहा। इस मल्ल युद्ध का निर्णायक साक्षात श्री दाऊजी महाराज को माना जाता है। इसका हिस्सा बने गौपों का समूह नारियल उपहार आदि लूट कर दाऊजी महाराज की परिक्रमा करते हुए नन्द घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आदि पदों का गायन करके अपने घर चल दिए।

क्षीर सागर में हुआ सेहरों का विसर्जन – विभिन्न देहात क्षेत्र से दूल्हे का सेहरा विसर्जित करने की परंपरा बलदेव छठ के अवसर पर निभाई जाती है। दूल्हे का सेहरा माता-पिता अपने पुत्र की शादी के ठीक एक वर्ष बाद बलदेव स्थित क्षीरसागर कुंड में विसर्जित करते हैं। हजारों लोगों ने सेहरा विसर्जित कर पूजा अर्चना की। बलदेव छठ को मोहर छठ के नाम से भी जाना जाता है।

यूपीआई पर एमडीआर का विरोध, 0.4 प्रतिशत वसूली से छोटे व्यापारियों में दहशत

कारोबारी बोले का धंधा चौपट होगा, व्यापारी संगठन फेम ने जताया सख्त विरोध

मथुरा। यूपीआई से 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (फेम) मथुरा ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। फेम के मथुरा महानगर अध्यक्ष रासबिहारी अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला व्यापार विरोधी है और इससे डिजिटल इंडिया मिशन को गहरा धक्का लगेगा। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला किसी भी तरह से व्यापारी हित में नहीं है। फेडरेशन का कहना है कि 2 से 5 प्रतिशत मार्जिन वाले किराना, दवा, जूता, कपड़ा व्यापारी को रोज 1 लाख पर 400 रुपये महीने के 12,000 रूपये का घाटा। देश में 65 प्रशित व्यापार पर असर इसका असर पडेगा। वॉल्यूम में भले 5 प्रतिशत लेन देन दिखें, पर वैल्यू में वही 65 प्रतिशत कारोबार हैं। हर बड़ा बिल इसकी चपेट में। 2100 का बिल 2000,100 में तोड़ा जाएगा। बिल स्प्लिटिंग और कैश लेन देन बढ़ेगा। रासबिहारी अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी न ग्राहक से ले सकते, न मना कर सकते हैं। ग्राहक से वसूलने पर रोक लगाई है। व्यापारी दो पाटों में फंसा गया है। बड़ा कॉरपोरेट बैंक से रेट घटवा लेगा, मथुरा जैसे शहरों का छोटा दुकानदार पूरा 0.4 प्रतिशत भरने को मजबूर रहेगा। उन्होंने कहाकि विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। संगठन ने आरोप लगाया कि यह फैसला अमेरिकी कंपनी वीजा, मास्टर कार्ड के दबाव में लिया गया है, इससे पैसा विदेशी निवेश वाले बैंकों में जाएगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने मांग की है कि यूपीआई को पूरी तरह फ्री रखा जाए, अगर एमडीआर जरूरी है तो सरकार खुद सब्सिडी दे और एमडीआर को आयकर में खर्च माना जाए। फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने सरकार से व्यापारियों एवं ग्राहकों के लिए इस अनुचित नियम को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए अपना विरोध जताया है।

सास की गला काटकर हत्या में बहू को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

मथुरा। थाना गोविंद नगर के चर्चित सावित्री देवी सोनी हत्याकांड में 12 साल बाद न्याय की घड़ी आई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार-आई, एचजेएस की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बहू को अपनी ही सास की निर्मम हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस में सरकारी अधिवक्ता रहे शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता डॉ. अशोक कुमार वर्मा पुत्र एन.एल. वर्मा निवासी डिफेंस कॉलोनी, भामतीपुरा रोड, धौलपुर राजस्थान ने सात दिसम्बर 2014 को थाना गोविंद नगर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी सास श्रीमती सावित्री देवी सोनी पत्नी स्व. बाबू लाल वर्मा, निवासी गली पातीराम, मंडी रामदास, गोविंद नगर, मथुरा, आर्य समाज इंटर कॉलेज की सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी सुमन वर्मा पत्नी डॉ. अशोक कुमार वर्मा के साथ धौलपुर में रहती थीं और कभी-कभी अपने पैतृक घर मथुरा आती-जाती थीं। पांच दिसंबर 2014 को वह धौलपुर से अपने मथुरा वाले घर आईं। छह दिसंबर को उनकी पोती अध्या वर्मा (पत्नी पंकज सोनी, निवासी कोटा) को शादी समारोह में मथुरा आना था। 07 दिसंबर 2014 को सुबह 07.30 बजे जब अध्या घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दादी सावित्री देवी कुर्सी पर खून से लथपथ घायल अवस्था में बैठी हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पर कमरे में तख्त पर बर्तन रखे थे और सामने स्टूल लगा था, जिससे स्पष्ट था कि मृतका किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति के साथ बैठकर बात कर रही थीं और उसी दौरान किसी बात पर विवाद होने पर धारदार हथियार से गले और शरीर पर कई वार कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे ने घर में रखे प्रॉपर्टी के दस्तावेज वाले बक्से को भी खंगाला था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें दूसरी बहू सीता वर्मा का नाम प्रकाश में आया।

कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस – बचाव पक्ष ने दलील दी कि सीता वर्मा एक महिला है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पिछले कई वर्षों से अपने पति से अलग रह रही है। उसके साथ नरम रवैया अपनाया जाए। वहीं डीजपीसी शिवराम सिंह तरकर ने तर्क दिया कि यह एक बुजुर्ग, अकेली महिला की गला काटकर की गई जघन्य हत्या है। यह मानव जीवन के विरुद्ध गंभीरतम अपराध है, जिसमें कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

कोर्ट की अहम टिप्पणी और सजा – दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मृतका एक बुजुर्ग महिला थीं। अभियोजन ने चिकित्सीय साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह साबित किया है कि उन्हें गर्दन पर एक घातक चोट सहित कई धारदार हथियार की चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। चोटों की संख्या और प्रकृति अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। न्याय के हित में आजीवन कारावास की सजा ही उचित है।

अग्रिम कर समाप्त करने और टीडीएस सरलीकरण की मांग, प्रधान मुख्य आयुक्त अपर्णा करन को दिए सुझाव

आयकर आउटरीच कार्यक्रम में फेम ने सौंपा ज्ञापन

मथुरा। होटल ब्रजवासी लैंड्स इन में आयोजित करदाता आउटरीच कार्यक्रम के अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (फेम) ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (उत्तर प्रदेश पश्चिम एवं उत्तराखंड क्षेत्र) अपर्णा करन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। फेम के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय कुमार अग्रवाल ने ज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने की पहल का स्वागत करते हुए कर प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, न्यायसंगत और सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव रखे। फेम ने कहा कि पहले बिक्रीकर का राजस्व राज्य सरकारों को मिलता था, लेकिन 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से केन्द्र सरकार को मासिक और त्रैमासिक रूप में बड़ी राशि ळैज् राजस्व के रूप में मिल रही है। पिछले 10-15 वर्षों में कई अप्रत्यक्ष कर और उपकर भी लागू हुए हैं। इसलिए अब अग्रिम आयकर को समाप्त करना एक व्यवहारिक और न्यायसंगत कदम होगा। काल्पनिक आय पर अग्रिम कर में कोई गलती होने पर आयकर दाता को धारा 234 बी तथा 234 सी के तहत 12ः वार्षिक ब्याज देना पड़ता है, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है क्योंकि आय हुई नहीं और कर का दायित्व बन गया। संगठन ने आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अग्रिम कर समाप्त कर राहत देने की मांग की। फेम पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि प्रधान मुख्य आयुक्त इन व्यावहारिक समस्याओं पर संज्ञान लेकर केन्द्र सरकार तक व्यापारियों की आवाज पहुंचाएंगी। इस अवसर पर फेम के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन व्यापार घाटे और आयात-निर्यात के असंतुलन से रुपये के अवमूल्यन पर चिंता जरूरी है। आयकर विभाग, सीए, अधिवक्ता और उद्योगपति केवल कंप्लाइंस तक सीमित न रहें, बल्कि निर्यात बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार को नीतिगत सुझाव भेजें। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। टीडीएस की जटिल धाराओं के स्थान पर सरल व समतल दरें लागू की जाएं तथा तकनीकी भूलों पर दंड लगाने के बजाय स्वतः सुधार का अवसर दिया जाए।छोटे आईटी फ्रीलांसर्स, विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों के विदेशी बैंक खातों की अनजाने में हुई चूक पर दंडात्मक कार्रवाई के बजाय स्वैच्छिक सुधार का अवसर मिलना चाहिए।

पीएम मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा ने मनाया सेवा पर्व

76 यूनिट रक्तदान के साथ मरीजों को बांटे फल

मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मथुरा महानगर की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा एवं मानवता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। मसानी चौराहा स्थित बृजवासी चौरिटेबल ब्लड बैंक में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए रक्तदान किया। शिविर में कुल 76 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।रक्तदान शिविर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में सहायक हो सकता है। उन्होंने युवाओं से समाजहित एवं मानव सेवा से जुड़े कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया।भाजपा मथुरा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश मिलता है। उन्होंने युवाओं से ऐसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।शिविर के संयोजक एवं भाजपा जिला महामंत्री यतेंद्र फौजदार की देखरेख में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। सेवा संकल्प अभियान के संयोजक राम किशन पाठक एवं सह संयोजक दीपक गोला ने भी आयोजन में सहभागिता की।रक्तदान शिविर के पश्चात मंत्री संदीप सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना तथा उन्हें फल वितरित किए। उन्होंने मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं सीएमएस नीरज अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा के मीडिया प्रभारी श्याम शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा भावना से जोड़ते हुए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रक्तदान एवं फल वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने रक्तदाताओं और आयोजन में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विनीत शर्मा, ज्ञानेंद्र राणा, विजय शर्मा,सुधांशु खंडेलवाल, अमित गोयल, गोविंद शर्मा, धीरेंद्र सिंह, अशोक यादव, निखिल गर्ग, यश गौतम, मनप्रीत सिंह, अरविंद ठाकुर, देवेंद्र कुमार, सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रक्तदान करने वालों में हिमांशु वर्मा, हनु भार्गव, शुभम भारद्वाज, नंद किशोर, अजय शर्मा सहित अनेक रक्तदाता शामिल रहे। शिविर के समापन पर सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

फिजिशियन फोरम के अध्यक्ष बने डा. अनिल चौहान

- **सचिव डा. राघव वरिष्ठ फिजिशियन डा. भरत गुप्ता को प्रेसिडेंट चुना गया**

मथुरा। मथुरा शहर के एक स्थानीय होटल में फिजिशियन चिकित्सकों के संगठन फिजिशियन फोरम का चुनाव सम्पन्न हुआ। चुनाव में वरिष्ठ फिजिशियन डा. अनिल कुमार चौहान की अध्यक्ष एवं डा राघव कुमार को सचिव चुना गया। चुनाव अधिकारी डा पीसी अग्रवाल एवं डा. एसबी अग्रवाल के नेतृत्व में वर्ष 2026-2028 के चुनाव को लेकर आयोजित चुनावी बैठक में फोरम की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डा. चिरदीप अग्रवाल को उपाध्यक्ष एवं डा. सिद्धार्थ कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं वर्ष 2028 के लिए वरिष्ठ फिजिशियन डा. भरत गुप्ता को प्रेसिडेंट इलेक्ट चुना गया। चुनाव अधिकारी डा. पीसी अग्रवाल एवं डा. एसबी अग्रवाल ने बताया कि फिजिशियन फोरम का चुनाव पूरी पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी चिकित्सकों और फोरम को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। बैठक में मौजूद चिकित्सकों ने नई टीम को बधाई दी और बुके देकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. अनिल कुमार चौहान ने कहा कि फोरम ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी भी चिकित्सक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिकित्सकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष डा. संजय सूद, डा. हार्दिक जैन, डा प्रदीप पाराशर डा अजित सिकरवार, डा विपिन कुमार, डा. ओपी अग्रवाल, डा भारती गर्ग, डा. नितिन चौहान, डा अमित गुप्ता आदि चिकित्सक मौजूद रहे।

भूतेश्वर स्थित प्राचीन दाऊजी मंदिर में जन्मोत्सव रही धूम

मथुरा। बलदेव छठ के पावन पर्व पर भूतेश्वर बलभद्र कुंड स्थित प्राचीन दाऊजी महाराज मंदिर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः आठ बजे विधि विधान मंत्रोच्चारण के मध्य भगवान बलदेव जी एवं माता रेवती जी का पंचामृत अभिषेक मंदिर के मुख्य महंत मोहन गुरु द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्वान आचार्य मालाराम शास्त्री, अनुज, अखिलेश शास्त्री एवं वेदांत ने पूजन के बाद 251 किलो दूध, दही, घी, शहद एवं गंगाजल से स्नान कराया गया। अभिषेक के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन कर पुण्य कमाया। सायं दाऊजी महाराज का बेंगलुरु, कोलकाता आदि से मंगाये गये देसी विदेशी फूलों से पूरे मंदिर प्रांगण को भव्य सजाया गया साथ ही ठाकुर दाऊजी महाराज की समक्ष विशाल छप्पन अर्पण किए गए। भक्तलोग दर्शन कर लाभान्वित हुए। रात्रि में सुविख्यात कलाकारों द्वारा ठाकुर जी के समक्ष भजन प्रस्तुत किए गए। देर रात तक श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम के समापन पर दाऊजी महाराज की महा आरती की गई, प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस भव्य आयोजन में विशेष रूप से शरद नागर, सत्य प्रकाश, गोविंद प्रसाद, मनोज सर्राफ, विपिन , माणिक शर्मा, कृष्ण कुमार कान्हा, पिंटू अग्रवाल, अशोक, विष्णु , अतुल का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम की सफलता के लिए संयोजक मोहनलाल भारद्वाज ने सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

राधाष्टमीः तीन साल में 10 से 35 लाख पहुंच गया श्रद्धालुओं के आगमन आंकडा

भीड को सम्हालने के लिए की गई हैं भारी भरकम व्यवस्थाएं

मथुरा। राधाष्टमी पर इस बार करीब 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभालने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भारी भरकम व्यवस्थाएं की गई हैं। तैयारियों को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठक हुई हैं। अधिकारी मेला और मंदिर क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। हर व्यवस्था पर बारीकी से नजर रखी जा रही हैं, तैयारियों की पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है। बरसाना में 325 स्थानों से सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होगी, इसके लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में केंद्रीयकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है। श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए मंदिर में भीड का दबाव न बने इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। निकास के लिए जयपुर मंदिर की ओर एकल दिशा मार्ग रहेगा। इस बार श्रीजी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए श्रीजी गेट और पीली कोठी से दो मार्ग निर्धारित किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। आगरा जोन से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में आठ अपर पुलिस अधीक्षक, 36 क्षेत्राधिकारी और करीब तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तीन स्थानों से ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 स्थानों पर एंबुलेंस और 10 स्थानों पर फायर टीमों की तैनाती की गई है। स्थानीय श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है इनके लिए आधार कार्ड के आधार पर पास जारी किए जाएंगे और उन्हें निर्धारित समय पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। थर्ड जेंडर श्रद्धालुओं को भी लाइन के माध्यम से दर्शन कराया जाएगा। बरसाना थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में 88 बैरियर और 50 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वीआईपी वाहनों के लिए यादव मोहल्ला चौराहा और पीडब्ल्यूडी में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। यातायात व्यवस्था को देखते हुए इस बार भंडारे भी कस्बे के बाहर लगाए जाएंगे।

आज रात से वाहनों का प्रवेश बंद – गुरुवार रात आठ बजे से कस्बे में छोटे-बड़े सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे से बाइक और ई-रिक्शा भी कस्बे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे से कस्बे में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा।

बेरोजगार दिवस कार्यक्रम से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता को हिरासत में लिया

-बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन से पहले पुलिस ने की कार्रवाई, कई कार्यकर्ताओं को कोतवाली ले जाया गया

मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देशभर में मनाए जा रहे बेरोजगार दिवस के तहत गुरुवार सुबह होली गेट पर प्रस्तावित युवा कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पहुंचा दिया। युवा कांग्रेस मथुरा परिवार के अनुसार, सुबह 9 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें मौके से हिरासत में ले लिया, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन नहीं हो सका। घटना के बाद युवा कांग्रेस ने अपने सभी कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जल्द से जल्द कोतवाली थाना पहुंचने की अपील की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दे पर उनकी आवाज आगे भी लगातार उठती रहेगी।

द्वारकेश संस्कृत विद्यालय के छात्रों मिलीं पाठ्य पुस्तक

मथुरा। संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए पुष्टिमार्ग संप्रदाय के तृतीय पीठाधीश्वर (कांकरोली नरेश) श्री श्री 108 डॉ. वागीश कुमार जी महाराज द्वारा पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी (एडवोकेट) ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर में संचालित द्वारकेश संस्कृत विद्यालय के छात्रों को आज मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉ. वागीश कुमार जी महाराज द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सहदेव कृष्ण चतुर्वेदी ने सभी बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित करवाई और महाराज श्री का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रति महाराज श्री की रुचि और इसे बढ़ावा देने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पुस्तक वितरण के दौरान महाराज श्री ने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सभी को आगे आना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर मंदिर के सभी प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वृन्दावनः बड़े दाऊ जी मंदिर में धूमधाम से मना बलदेव छठ उत्सव

▶▶ पंचामृत अभिषेक और छप्पन भोग के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

वृन्दावन की अनाज मंडी स्थित प्राचीन बड़े दाऊ जी मंदिर में बलदेव छठ का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री बलराम स्वरूप श्री दाऊ जी महाराज का विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। अभिषेक के उपरांत ठाकुर जी का मनोहारी श्रृंगार कर भव्य झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर के सेवायत दीपक गोस्वामी ने बताया कि प्रातःकाल धार्मिक अनुष्ठानों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विशेष अवसर पर दाऊ जी महाराज के श्रीचरणों में विविध मिष्ठान्न, फल, मेवा और व्यंजनों से सुसज्जित छप्पन भोग अर्पित किया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इसके अलावा सायंकाल में आयोजित भव्य भजन संध्या में हजारों भक्त देर रात तक भक्ति रस में सराबोर होकर झूमते रहे। बलदेव छठ के इस पावन मौके पर स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दाऊ जी महाराज के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए थे। दिनभर चले इन धार्मिक आयोजनों ने ब्रज की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को जीवंत कर दिया।

राया विद्युत उपकेंद्र पर मनी भगवान विश्वकर्मा की जयंती

राया। कस्बा राया में विद्युत उपखंड कार्यालय पर गुरुवार को वास्तुकार और निर्माण कला के जनक भगवान विश्वकर्मा की जयंती भक्ति भाव के साथ मनायी गयी। इस अबसर पर कार्यालय परिसर पर पूजा अर्चना के साथ अखण्ड रामायण पाठ हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अबसर पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार गौड़ अबर अभियंता सतेंद्र यादव कृष्णवीर सिंह विष्णु शर्मा पंकज शर्मा रामकुमार हेमंत कुमार सत्यप्रकाश पिंटू कुमार जगवीर ओमवीर सिंह गोपाल शर्मा गोपाल लाला अनिल रावत रनवीर सिंह भेदजीत सिंह सुभाष संतोष कुमार जितेंद्र राहुल आदि विधुत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

चौमुहां में ब्रज उदय प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन

▶▶ महिलाओं को मिला आजीविका का नया सहारा’

चौमुहां। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वावलंबन से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विकासखंड चौमुहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में श्ब्रज उदय प्रेरणा कैंटीनश् का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि प्रशिक्षु आईएएस एवं प्रभारी बीडीओ सलोनी गौतम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नरदेव चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं संगठित होकर रोजगार पा रही हैं। जगह-जगह प्रेरणा कैंटीन का सफल संचालन इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार में महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण हुआ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रशिक्षु आईएएस सलोनी गौतम ने कैंटीन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इस कैंटीन के खुलने से दोहरा लाभ होगा। एक तरफ जहां ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों और स्थानीय कर्मचारियों को बहुत ही कम और किफायती दामों पर शुद्ध, स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो सकेगा।प्रभारी बीडीओ ने आगे की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल इन प्रेरणा कैंटीनों का संचालन ब्लॉक स्तर पर प्रमुख सरकारी परिसरों में किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार की योजना इसका विस्तार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक करने की है, जिसके तहत इन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर भी संचालित किया जाएगा। इससे ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं तक पहुंच सकेगा।इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप चौधरी,एडीओ आइएसबी राकेश कर्दम, एडीओ पंचायत नवेश कुमार सुमन,मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल सिसोदिया, बिहारी लाल उर्फ पूरन सिंह सिसौदिया,पंचायत सचिव योगेश शर्मा, रविंद्र वशिष्ठ, नेत्रपाल सिंह,राजेश कुमार,वीरेश शर्मा सहित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजर, स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक, स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारी महिलाएं और भारी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

किशाऊ परियोजना मोदी सरकार की उपलब्धि, क्या मुख्यमंत्री का व्यवहार 'क्रेडिट पिपासु' : अनुराग सिंह ठाकुर

किशाऊ परियोजना पर छह दशक से कायम गतिरोध मोदी सरकार ने किया समाप्त- अनुराग सिंह ठाकुर, परियोजना का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र उठाएगा, मुख्यमंत्री बताएं कि कांग्रेस सरकारें 50-60 वर्षों में समाधान क्यों नहीं निकाल पाईं : अनुराग ठाकुर

मोदी सरकार के प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त- अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला, पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर पिछले छह दशकों से चले आ रहे गतिरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की अनेक सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किशाऊ बांध परियोजना की समस्या का समाधान नहीं हो सका मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संवाद और सहमति के माध्यम से इस लंबे समय से लंबित विषय को समाधान तक पहुंचाया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ÷आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की पहल पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर किशाऊ परियोजना को लेकर वर्षों से लंबित मतभेदों का समाधान किया गया। मैं सर्वसम्मति से लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रश्नमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का आभार प्रकट करता हूँ। 15 सितंबर 2026 को छह राज्यों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे परियोजना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतने वर्षों में केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की अनेक सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया मगर मोदी सरकार ने इस समस्या का समाधान करने का काम किया है÷

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा ÷किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है और इसके लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय भार का वहन केंद्र सरकार करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत भार सहभागी राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना के संबंध में हिमाचल प्रदेश के हिस्से की विद्युत लागत को लेकर भी अन्य सहभागी राज्यों द्वारा वित्तीय भार साझा करने की व्यवस्था बनी है, जिससे हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा। किशाऊ परियोजना केवल एक बांध अथवा बिजली परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जल सुरक्षा, सिंचाई, पेयजल और पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। केंद्र सरकार के अनुसार परियोजना से 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और लगभग 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन का लक्ष्य है श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ÷ यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस ऐतिहासिक समझौते से छह राज्यों के हित जुड़े हैं और जिसका समाधान केंद्र सरकार के नेतृत्व में हुआ है, उसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा ÷क्रेडिट पिपासु÷ बनकर व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब परियोजना पर छह दशकों से समाधान नहीं निकल पाया और केंद्र सरकार ने सभी संबंधित राज्यों को साथ लेकर सहमति बनाई, तब इसका श्रेय लेने की होड़ उचित नहीं है। किशाऊ परियोजना पर हुआ समझौता सहकारी संघवाद और संवाद के माध्यम से समाधान का उदाहरण है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्षों से लंबित विषय को आगे बढ़ाया है। ऐसे में राजनीतिक श्रेय की बजाय हिमाचल प्रदेश सहित सभी सहभागी राज्यों और आने वाली पीढ़ियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर संकीर्ण राजनीति करने के बजाय सभी पक्षों के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा ÷प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस दृढ़ता और संवाद की भावना के साथ किशाऊ परियोजना का समाधान सुनिश्चित किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित जल, ऊर्जा और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

एच.पी.वी. वैक्सीन एवं माहवारी स्वच्छता विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित

सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन के सौजन्य से आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला सोलन में एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमा वायरस) वैक्सीन एवं माहवारी स्वच्छता विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज़िला टीकाकरण अधिकारी डॉ. गगन ने की।

डॉ. गगन ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य किशोरियों एवं उनके अभिभावकों को एच.पी.वी. संक्रमण, एच.पी.वी. वैक्सीन के लाभ तथा किशोरियों के स्वास्थ्य एवं माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था।

उन्होंने छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को एच.पी.वी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एच.पी.वी. एक सामान्य वायरस है, जिसके कुछ प्रकार आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर सहित कुछ अन्य कैंसर का कारण बन सकते हैं। एच.पी.वी. संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है।

उन्होंने कहा कि 14 से 15 वर्ष की आयु की बालिकाओं को एच.पी.वी. वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि एच.पी.वी. टीकाकरण से संबंधित भ्रांतियों और अफवाहों पर विश्वास न करें तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वैक्सीन का उद्देश्य किशोरियों को भविष्य में एच.पी.वी. संक्रमण से होने वाली गंभीर बीमारियों, विशेषकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव प्रदान करना है। टीकाकरण से संबंधित किसी भी शंका या संभावित दुष्प्रभाव के बारे में अभिभावक स्वास्थ्यकर्मियों अथवा चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रियंका ने कहा कि माहवारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसके प्रति किसी प्रकार की झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं को माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, स्वच्छ एवं सुरक्षित सैनिटरी पैड अथवा उपयुक्त मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री का प्रयोग करने तथा उसे समय-समय पर बदलने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि सामान्यतः सैनिटरी पैड को बहुत लंबे समय तक न रखें और आवश्यकता के अनुसार लगभग 4 से 6 घंटे में बदलें, जबकि अधिक रक्तस्राव होने पर इससे पहले भी बदलना चाहिए। इस्तेमाल किए गए पैड को उचित तरीके से लपेटकर निर्धारित स्थान पर ही फेंकना चाहिए तथा पैड बदलने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।

डॉ. प्रियंका ने छात्राओं को माहवारी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेने की सलाह दी। उन्होंने हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने छात्राओं को माहवारी से संबंधित किसी भी असामान्य समस्या, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, असहनीय दर्द, चक्कर, कमजोरी या अनियमित माहवारी की स्थिति में चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और किशोरियों को सही एवं वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाना उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

धान खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण शुरु

शिमला। हिमाचल प्रदेश में खरीफ सीजन 2026-27 में किसानों से धान खरीदने के लिए ऑनलाईन पोर्टल को पंजीकरण के लिए 15 सितम्बर, 2026 से खोल दिया गया है। किसान अपने धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एचपी एपीपी पर पंजीकरण करके अपनी सुविधानुसार टोकन बुक कर सकते हैं। निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुमुद सिंह ने आज यहां बताया कि प्रदेश में धान की खरीद 3 अक्तूबर, 2026 से शुरू होगी तथा 15 दिसम्बर, 2026 तक किसानों से खरीदा जाएगा, जिसके लिए 11 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। धान की खरीद चार सीमान्त जिलों कांगड़ा, सोलन, ऊना एवं सिरमौर में की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसानों को एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। इसमें किसानों का व्यक्तिगत एवं जमीन सम्बन्धी डाटा फार्मर रजिस्ट्री से ऑनलाईन लिया जाएगा तथा पटवारी से जमीन के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उसे बैंक सम्बंधी सम्पूर्ण जानकारी पूर्व की भाति स्वयं भरनी होगी। जो किसान एग्रीस्टैक में पंजीकृत नहीं है, उसे पूर्व की भांति एचपी एपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए स्वयं सम्पूर्ण जानकारी भरनी होगी तथा पूर्व की भांति ही पटवारी द्वारा जमीन का ऑनलाइन सत्यापन तथा कृषि अधिकारी द्वारा उपज की एंट्री ऑनलाईन करनी होगी। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये अधिक है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि अपनी धान की फसल को उक्त चार जिलों में स्थापित 11 खरीद केन्द्रों में जाकर बेचें तथा भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे उक्त समर्थन मूल्य की जानकारी किसानों तक पहुंचाए तथा उन्हें उनकी फसल सरकार को बेचने के लिए प्रेरित करें।

डॉ. शांडिल 17 व 18 सितम्बर को सोलन ज़िला के प्रवास पर

सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 17 व 18 सितम्बर, 2026 को सोलन ज़िला के प्रवास पर आ रहे हैं। डॉ. शांडिल 17 सितम्बर, 2026 को दोपहर 12.30 बजे माँ भगवती मेला ओच्छघाट में मुख्यातिथि होंगे। स्वास्थ्य मंत्री 18 सितम्बर, 2026 को प्रातः 11.00 बजे खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय कण्डाघाट में 'अपना परिवार सुखी परिवार' में नए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। डॉ. शांडिल तदोपरांत सांय 05.00 बजे अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले में मुख्यातिथि होंगे।

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाना सुनिश्चित करें : उपायुक्त हेमराज बैरवा

विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा

धर्मशाला, उपायुक्त कार्यालय में आज जिला कांगड़ा में संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की। बैठक में जिला में चल रही योजनाओं, लंबित कार्यों, वित्तीय प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। इनमें आरजीएसए के अंतर्गत सामुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के निर्माण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत घरों के निर्माण की स्थिति, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित लंबित जांच मामलों की स्थिति शामिल रही।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए व्यवस्थित रूट प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने पंचायत स्तर पर प्लास्टिक को एकत्रित करने के साथ-साथ डोर-टू-डोर कलेक्शन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि प्लास्टिक कचरे का उचित संग्रहण एवं प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों की कार्यशीलता तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तथा अन्य स्वच्छता गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रमाण पत्र तैयार करने तथा अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत घरों का उपयुक्त स्थान पर होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवगठित एवं विभाजित ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों के निर्माण और भूमि संबंधी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

उन्होंने कहा कि पंचायत घर ऐसी जगह पर होने चाहिए, जहां ग्रामीणों को आसानी से पहुंच उपलब्ध हो और वे घर-द्वार के समीप सरकारी सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ उठा सकें। बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों के निर्माण, भूमि चयन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, टोकन मनी तथा अनुदान स्वीकृति से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। जिला में 81 नवगठित ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों से संबंधित कार्यों की स्थिति भी अधिकारियों से प्राप्त की गई।

बैठक में विकसित भारतङ्करोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी रैम जी) के तहत रोजगार दिवस सृजन, लंबित कार्यों, समयबद्ध भुगतान, जियो-टैगिंग तथा जॉब कार्ड ई-केवाईसी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 तक जिला कांगड़ा में 2,16,087 व्यक्ति-दिवस सृजित किए गए।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास निर्माण, प्राकृतिक आपदा से संबंधित आवासों, विशेष परियोजनाओं तथा पुराने लंबित आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपयुक्त ने बताया कि 15 सितंबर 2026 तक ग्राम पंचायतों के स्तर पर कुल 241.30 करोड़ रुपये व्यय दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), बैंक ऋण संबंध, स्टार्टअप, रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि तथा 'लखपति दीदी' से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई 2.0) की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2026-27 में संबंधित पांच ब्लॉकों के लिए कुल 433.19 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा व्यय की प्रगति 86 प्रतिशत दर्ज की गई है।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अधिकारियों को विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार, जिला विकास अधिकारी (ग्रामीण विकास) अभिनीत कात्यायन, जिला पंचायत अधिकारी सचिन ठाकुर,

हिमाचल उत्सव के कलाकारों के ऑडिशन 20 सितंबर को

सोलन। डायनामिक इंडिया युवा मंडल द्वारा आयोजित और गोयल मोटर्स सोलन द्वारा प्रायोजित हिमाचल का सबसे बड़ा गैर-सरकारी मेला 22वां हिमाचल उत्सव 4 से 11 अक्टूबर तक सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित होगा। आठ दिनों तक चलने वाले हिमाचल उत्सव में लोक संस्कृति, ग्रामीण उत्पादों, ग्रामीण खेलों सहित पहाड़ी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आठ सांस्कृतिक संध्याओं में नृत्य, गायन और अन्य परफॉर्मिंग आर्ट की प्रस्तुतियां होंगी। इन सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के इच्छुक हिमाचल के गायकों, नर्तकों और अन्य कलाकारों के लिए ऑडिशन 20 सितंबर को होटल पैरागॉन पैलेस, सोलन में सुबह 11 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक कलाकार ऑडिशन में अवश्य भाग लें। ऑडिशन के लिए कोई फीस नहीं है। डायनामिक इंडिया युवा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पंकज सूद, संस्थापक उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा एडवोकेट और संस्थापक महासचिव कीर्ति कौशल ने बताया कि पिछले 21 वर्षों में हिमाचल उत्सव का मंच स्थानीय कलाकारों को उभरने का एक सशक्त मंच साबित हुआ है। इस वर्ष भी ऑडिशन के माध्यम से प्रदेश के उभरते कलाकारों का चयन कर उन्हें उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल उत्सव की आठ सांस्कृतिक संध्याओं में 500 से अधिक स्थानीय कलाकार और स्कूली बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। , विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग से प्रतियोगी कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक संस्थान इसके लिए युवा मंडल से संपर्क कर सकते हैं।

डॉक्टर बनना मंजिल नहीं, समाज की सेवा करना असली लक्ष्य : विजय शर्मा

मेडिकल कॉलेज कवर्धा में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ, डिप्टी सीएम ने किया छात्रों का स्वागत

रायपुर, एजेंसी। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने बड़ा लक्ष्य रखा और डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन डॉक्टर बनना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। हमारा उद्देश्य केवल डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि डॉक्टर बनकर समाज के लिए अच्छा कार्य करना होना चाहिए। शासकीय मेडिकल कॉलेज कवर्धा में प्रथम शैक्षणिक सत्र और प्रथम बैच की पढ़ाई का शुभारंभ हुआ।

इस ऐतिहासिक अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पाण्डेय ने नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का एप्रॉन, स्टेथोस्कोप, पेन और गुलाब का फुल देकर स्वागत किया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ अपने नए शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज के इतिहास के इस पहले दिन विद्यार्थियों ने अतिथियों के साथ अपने संघर्ष, तैयारी और सपनों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जिस परिवार और समाज ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उसके प्रति सेवा का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य की तैयारी निरंतर जारी रखें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान अनावश्यक तनाव नहीं होना चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति का परिणाम नहीं होती, बल्कि परिवार और सभी के संयुक्त प्रयासों से प्राप्त होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे डॉक्टर बनने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। सांसद संतोष पाण्डेय ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से कवर्धा में मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि विद्यार्थियों ने कठिन मेहनत के बाद यहां तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि शुभारंभ है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है, तो उसके मन में स्वस्थ होने की उम्मीद होती है। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा भाव और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से किया संवाद, जानी तैयारी और सफलता की कहानी–प्रथम बैच के विद्यार्थियों के शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी तैयारी, पढ़ाई की दिनचर्या, कोचिंग के अनुभव और प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी ली। विद्यार्थियों ने भी खुलकर अपनी तैयारी और सफलता की कहानी साझा की। किसी ने ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से तैयारी की, तो किसी ने लाइब्रेरी में स्व-अध्ययन को आधार बनाया।

पिता ने कभी निराश नहीं होने दिया–संवाद के दौरान राजनांदगांव निवासी अतिथि देवांगन दूसरे प्रयास में सफल हुईं। उन्होंने बताया कि पिता ने कभी निराश नहीं होने दिया, बल्कि गलतियों को पहचानकर सुधार करने और लगातार प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं भूपेंद्र सिंह ने ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी की, जबकि कवर्धा के धरमपुरा निवासी आकाश धुर्वे ने लाइब्रेरी में स्व-अध्ययन कर सफलता हासिल की। भिलाई निवासी हर्षिता तीसरे प्रयास में सफल हुईं। भिलाई निवासी अंशिता सिंह के पिता ने बताया कि बेटी की तैयारी में उन्होंने मार्गदर्शन के साथ मॉक टेस्ट में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि भिलाई का पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल भी तैयारी में सहायक रहा।

उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से यह भी जाना कि वे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किताबों तथा डिजिटल स्क्रीन का कितना उपयोग करते थे। विद्यार्थियों ने बताया कि वे करीब 8 घंटे पुस्तकों से और 3 से 4 घंटे डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाई करते थे। एक विद्यार्थी ने किताब और स्क्रीन के उपयोग का अनुपात 50-50 प्रतिशत बताया। ऑनलाइन कक्षाओं के कारण कुछ विद्यार्थियों को रोज 7 से 8 घंटे तक स्क्रीन पर पढ़ाई करनी पड़ती थी। संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रवेश परीक्षा के अनुभव भी पूछे। विद्यार्थियों ने परीक्षा के स्तर, तैयारी के दौरान आई चुनौतियों और सफलता तक पहुंचने के अपने अनुभव साझा किए।

आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, 165 अधिकारी-कर्मचारियों का ट्रांसफर

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने एक साथ 165 अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव करते हुए तबादला आदेश जारी किया है। नई सूची में जिला आबकारी अधिकारियों से लेकर आबकारी उप निरीक्षक, कांस्टेबल, क्लर्क, ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक के नाम शामिल हैं।

12 जिला आबकारी अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी–जारी तबादला सूची के मुताबिक प्रदेश के 12 जिला आबकारी अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 31 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों और 57 आबकारी उप निरीक्षकों को भी नई जगह पदस्थ किया गया है।विभागीय स्तर पर किए गए इस व्यापक फेरबदल में मैदानी अमले के साथ-साथ कार्यालयीन कर्मचारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कांस्टेबल से क्लर्क और ड्राइवर तक तबादले–आदेश के अनुसार 39 हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल के कार्यस्थल में बदलाव किया गया है। वहीं 12 क्लर्क तथा 14 ड्राइवर और चपरासियों को भी नई पदस्थापना दी गई है।

इस तरह विभाग की ओर से जारी आदेश में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 165 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।

नई पदस्थापना पर संभालना होगा कार्यभार–तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशानुसार अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभाग में हुए इस व्यापक फेरबदल के बाद अब नई जगहों पर प्रशासनिक और मैदानी जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा।

रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ले-आउट के बाहर बने 40 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

रायपुर, एजेंसी। नगर पालिक निगम रायपुर ने जोन-6 क्षेत्र अंतर्गत रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में ले-आउट के बाहर किए गए लगभग 40 अवैध निर्माणों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश तथा जोन-6 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा एवं नगर निगम अधिकारियों के साथ पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। नगर निगम के अनुसार संबंधित बिल्डरों ने ले-आउट के बाहर बिना अनुमति निर्माण कराया था। नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद अभियान चलाकर अवैध निर्माण बुलडोजर से हटाए गए। कार्रवाई के बाद संबंधित बिल्डरों ने निगम को आश्वस्त किया कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा।

जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव ने बताया कि रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में मुनरपे, रहमत, ओग, धनु सोनकर, मनोज चकधारी, रवि त्रिपाठी, आशु त्रिपाठी, अनवर, चेतन देवांगन, सुभाष विश्वकर्मा, सुखराम चकधारी, अजय साहू, जय साहू, अजय माखिजा, बसंत सतवाने, तिस्थ साहू एवं गोपाल देवांगन सहित अन्य संबंधित बिल्डरों द्वारा ले-आउट के बाहर अवैध निर्माण कराए जाने की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से पूर्व में जलभराव, सड़क, बिजली, पेयजल और नाली की समस्याओं को लेकर लगातार जनशिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी।

बाबू बने थे टैक्स इंस्पेक्टर, अब लौटेंगे मूल पद पर

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के राज्य कर विभाग में 2021 और 2022 की सीमित भर्ती परीक्षा के जरिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों को अब उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। विभाग ने जांच में सामने आई गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों के बाद संबंधित चयन प्रक्रिया और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों को निरस्त करने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को विभाग में लिपिक पद पर रहते हुए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाया गया था। अब चयन निरस्त होने के बाद वे अपने पुराने पद और पदस्थापना पर लौटेंगे।

जांच में सामने आई कई गंभीर खामियां–जांच रिपोर्ट के मुताबिक चयन प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा परीक्षा का समेकित परिणाम और अंक सूची तैयार नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति का मूल रिकॉर्ड नहीं मिलने और उत्तरपुस्तिकाओं पर अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने के लिए आवश्यक कोडिंग व्यवस्था नहीं होने का भी उल्लेख किया गया है। जांच में चयनित अभ्यर्थियों की कई उत्तरपुस्तिकाओं में एक जैसे जवाब मिलने की बात सामने आई। कुछ उत्तर मॉडल आंसर से भी काफी हद तक मेल खाते पाए गए। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ाए जाने की बात भी जांच में दर्ज होने की रिपोर्ट है।

42 कर्मचारियों को मूल पद पर लौटाया गया–विभागीय आदेश के बाद वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर की गई नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। रिपोर्टों के अनुसार, प्रभावित 42 कर्मचारी अब उसी मूल लिपिक पद पर वापस जाएंगे, जहां से वे निरीक्षक के पद पर पहुंचे थे।

2021-22 की परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवाल–मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच समिति गठित की थी। समिति ने परीक्षा आयोजित करने से लेकर उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया तक से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्ट में परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर कई गंभीर सवाल दर्ज किए गए हैं।

समीर विश्नोई के कार्यकाल का भी जिक्र–मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया तत्कालीन राज्य कर आयुक्त समीर विश्नोई के कार्यकाल में हुई थी। हालांकि, किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच या न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष अलग से महत्वपूर्ण होंगे। उपलब्ध रिपोर्टों में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं के संदर्भ में उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से कच्चे घर की चिंता हुई दूर

पक्के आशियाने ने लौटाई दुलेश्वरी बाई की खुशियां

रायपुर, एजेंसी। सेवा, संकल्प और जनकल्याण की भावना के साथ गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवाकाल में गरीबों को बेहतर जीवन, सम्मान और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का संकल्प विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम रानीतराई निवासी दुलेश्वरी बाई के परिवार के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत की है।

दुलेश्वरी बाई ने बताया कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बरसात का मौसम उनके लिए विशेष चिंता लेकर आता था। बारिश के दौरान घर में पानी आने से बच्चों की पुस्तकें, कपड़े और अन्य जरूरी सामान भीग जाते थे। कच्चे मकान में कीड़े-मकोड़ों की समस्या भी बनी रहती थी। हर मौसम में परिवार को घर की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में परिवार के लिए एक पक्का और सुरक्षित घर किसी सपने से कम नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उन्हें 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता मिली, जिससे उनका पक्का मकान तैयार हो सका। पक्का मकान बनने के बाद दुलेश्वरी बाई के परिवार की दिनचर्या और जीवन की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। अब बारिश के दौरान घर में पानी आने की चिंता नहीं रहती और परिवार को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से काफी राहत मिली है। बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिला है। दुलेश्वरी बाई ने बताया कि पहले जहां बारिश शुरू होते ही घर के सामान और बच्चों की किताबों को बचाने की चिंता रहती थी, वहीं अब पूरा परिवार निश्चिंत होकर अपने पक्के घर में रह रहा है। उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवारों को सुरक्षा, स्थायित्व, सम्मान और बेहतर भविष्य का भरोसा भी प्रदान कर रहा है।

राजधानी रायपुर में राज्यस्तरीय श्रमिक महासम्मेलन 17 को

रायपुर, एजेंसी। भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर 17 सितंबर को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगे। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर में दोपहर 12 बजे से आयोजित होने वाला यह महासम्मेलन प्रदेश के श्रमवीरों के सम्मान का महत्वपूर्ण अवसर होगा। निर्माण से लेकर उद्योग, कृषि, सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिश्रम से प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले श्रमिक इस आयोजन के केंद्र में रहेंगे। भगवान विश्वकर्मा जयंती श्रम, कौशल, निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर आयोजित श्रमिक महासम्मेलन के माध्यम से श्रम के सम्मान और श्रमिकों के महत्व का संदेश प्रदेशभर में पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इनके साथ मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, अन्य मंत्रीगण सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

श्रमिक सुरक्षा और उत्कृष्ट कार्य को मिलेगा सम्मान

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार-2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पुरस्कार के तहत चयनित श्रमिक अथवा संस्था को 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किया हो। विशेष रूप से ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रभावी उपाय किए गए हों और जिनके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो।

नवा रायपुर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का भव्य शुभारंभ

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आज बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। लगभग 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने दीप प्रज्वलित कर किया।

शुभारंभ समारोह के विशेष अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने 'छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष पुस्तिका-2026' के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया। यह प्रकाशन छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया, उपलब्धियों, नवाचारों और चुनावी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करता है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार तथा आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने सम्मेलन में देशभर से आए राज्य निर्वाचन आयुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचन विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों और स्थानीय निकाय निर्वाचन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा प्रशासन और निर्वाचन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों से जुड़े समसामयिक विषयों, डिजिटल पहलों, तकनीकी नवाचारों तथा निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह एवं आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन के प्रथम दिन डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, पारदर्शिता तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रियाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर परिचर्चा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्थायी समिति के संयोजक सुधांशु पांडे ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मरीन ड्राइव पर सजेगा 'आशीर्वाद का दीया', शहर में बदलेगी ट्रैफिक की चाल

रायपुर, एजेंसी। सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को मरीन ड्राइव में आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने यातायात डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आज शाम करीब 7 बजे से यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा।

यातायात पुलिस के अनुसार, तेलीबांधा थाना तिराहा, कटोरा तालाब चौक, अनुपम नगर चौक, शास्त्री चौक और इनकम टैक्स कॉलोनी टर्निंग से मरीन ड्राइव की ओर आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह चौक से खजाना चौक, भगत सिंह चौक से शंकर नगर अंडरब्रिज, भगत सिंह चौक से तेलीबांधा चौक तथा आनंद नगर चौक से भारत माता चौक एवं कटोरा तालाब चौक तक दोनों ओर वाहनों का आवागमन और पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों के लिए गॉस मेमोरियल ग्राउंड, मल्टी लेवल पार्किंग अंबेडकर चौक, ऑक्सीजोन के किनारे का मार्ग, शांति नगर विमतारा रोड, सूर्य नमस्कार केनाल रोड और बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की गई है।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से सड़क किनारे या प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन पार्क नहीं करने की अपील की है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अनावश्यक रूप से प्रभावित मार्गों का उपयोग न करने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का भारत दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर: पीएचएफ

नई दिल्ली । पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) के प्रमुख मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि अगले महीने होने वाली हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का भारत दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होनी है। इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया के साथ ही पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना है। पाकिस्तान के नहीं आने की स्थिति में ओमान या बांग्लादेश को मौका दिया जा सकता है। दोनों टीमों को फिलहाल रिजर्व टीम के रूप में रखा गया है। पाकिस्तान के दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र 'डॉन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वानी ने कहा, 'पाकिस्तान टीम का दौरा सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। सरकार हमसे जो भी करने को कहेगी, हम वही करेंगे। '

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अगले महीने टूर्नामेंट के लिए भारत आएगा। मल्टी-नेशनल टूर्नामेंट में कोई दिक्कत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो सकती।

उन्होंने केंद्र सरकार की नीति का जिक्र करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान मल्टीनेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं।

ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना मेरे लिए बड़ा पल, जिंदगी में इतना बड़ा स्टेडियम कभी नहीं देखा था: टिलेमैन्स

नई दिल्ली । मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के नए मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स का कहना है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना फुटबॉल के सबसे खास अनुभवों में से एक है। उन्होंने याद किया कि जब वह एस्टन विला के लिए खेलते थे और पहली बार विरोधी खिलाड़ी के रूप में इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में उतरे थे, तो वहां का माहौल देखकर काफी प्रभावित हुए थे। जुलाई में, मिडफील्डर ने जून 2031 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पिछले सीजन में उन्होंने एस्टन विला के लिए सात असिस्ट किए और अपने क्लब को यूईएफए यूरोपा लीग जीतने में मदद की, जिसमें उन्होंने एससी फ्रीबर्ग के खिलाफ फाइनल में पहला गोल किया। उन्होंने जियोहॉटस्टार को बताया, 'मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बड़ा क्लब है। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली बार विरोधी टीम के तौर पर खेलना मेरे लिए एक बड़ा पल था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्टेडियम कभी नहीं देखा था। माहौल, भीड़, इसके बारे में सब कुछ कमाल का था। यह ऐसी जगह है जहां हर फुटबॉलर खेलने का सपना देखता है। '

बेल्जियम के स्टार मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी के रूप में ओल्ड ट्रैफर्ड के माहौल का अनुभव करने के लिए उत्साहित हैं। यूनाइटेड 2026-27 प्रीमियर लीग सीजन में मिश्रित शुरुआत के बाद लय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। टीम ने लीग के अपने पहले चार मैचों में चार अंक जुटाए हैं। यूनाइटेड को हल सिटी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद टीम ने इप्सविच टाउन को 5-2 से हराया। वहीं, एवर्टन के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि मैनचेस्टर डर्बी में उसे मैनचेस्टर सिटी से 0-1 की हार मिली।

संक्षिप्त समाचार

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 59 रन से हराया

हरारे। ऑस्ट्रेलिया ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मंगलवार को खेले गए पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 59 रन से हराया। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। सीरीज के शेष मुकाबले 18 और 20 सितंबर को खेले जाने हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 294 रन बनाए। इस टीम को 10 के स्कोर पर ट्रेविस हेड (4) के रूप में पहला झटका लग गया था, जिसके बाद कप्तान मिचेल मार्श ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए

50 रन की साझेदारी की। मार्श 28 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद जोश इंगलिस मैदान पर उतरे, लेकिन टीम के खाते में 4 रन से ज्यादा नहीं जोड़ सके। हालांकि, कूपर (51 रन) अर्धशतक लगाने में सफल रहे।टीम को 107 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया था। यहां से मैट रेनेशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ पांचवें विकेट के लिए 72 रन जुटाए, जबकि ओलिवर पीक के साथ छठे विकेट के लिए 75 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाईकैरी 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रेनेशॉ ने 94 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 109 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक रहा। ओलिवर ने टीम के खाते में 30 रन का योगदान दिया।

यूईएफए ने 2028 और 2029 चैंपियंस लीग फाइनल के वेन्यू किए तय

- म्यूनिख और कैंप नोउ को मिली मेजबानी

न्योन । यूईएफए ने 2028 और 2029 चैंपियंस लीग फाइनल के आयोजन स्थलों की पुष्टि कर दी है । म्यूनिख फुटबॉल एरिना और बार्सिलोना का कैंप नोउ प्रतिष्ठित यूरोपीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी करेंगे । 2028 का खिताबी मैच म्यूनिख फुटबॉल एरिना में खेला जाएगा, जबकि 2029 संस्करण बार्सिलोना के कैंप नोउ में होगा । म्यूनिख के स्टेडियम को प्रमुख चैंपियंस लीग आयोजनों की मेजबानी करने का काफी अनुभव है । इसने साल 2012 में और फिर 2025 में फाइनल का आयोजन किया ।

आईसीसी टी-20 रैंकिंग: पाकिस्तानी को पछाड़ दूसरे स्थान पर पहुंचे अभिषेक

- बुमराह और वरुण को भी फायदा
- अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने रैंकिंग में सुधार किया

दुबई, एजेंसी। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत के शानदार प्रदर्शन का असर खिलाड़ियों की ताजा आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी दिखाई दिया है। तीन मैचों की सीरीज में भारत ने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना ली है। इन दोनों मैचों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद कई खिलाड़ियों ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है।

टी20 विश्व कप के मौजूदा चैंपियन भारत के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी स्थिति मजबूत की है। बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा को सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जबकि गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने रैंकिंग में सुधार किया है।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शानदार 82 रन की पारी खेली थी। इस पारी का फायदा उन्हें ताजा टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में मिला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक स्थान की छलांग लगाई और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब उनसे आगे सिर्फ भारत के ईशान किशन हैं। ईशान और अभिषेक के बीच रेटिंग अंकों का अंतर भी ज्यादा नहीं है। दोनों के बीच 51 रेटिंग अंकों का अंतर है। ऐसे में सीरीज के बाकी मुकाबलों में प्रदर्शन अभिषेक के लिए रैंकिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

वरुण चक्रवर्ती पांचवें नंबर पर

गेंदबाजों की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति मजबूत हुई है। वरुण चक्रवर्ती ने दो स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष पांच में जगह बना ली है। वरुण अब पांचवें स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में उनके प्रदर्शन ने इस सुधार में भूमिका निभाई है। जसप्रीत बुमराह ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय तेज गेंदबाज सात स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

अर्शदीप और अक्षर भी ऊपर चढ़े

भारत के एक और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वह 11 स्थान ऊपर चढ़कर 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी अपनी स्थिति में सुधार किया है। वह छह स्थान ऊपर चढ़कर 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के शुरुआती दो मैचों के बाद भारत के चार गेंदबाजों को टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है।

अजमतुल्लाह ओमरजई को भी फायदा

अफगानिस्तान की ओर से ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई ने रैंकिंग में ध्यान खींचा है। 26 वर्षीय उमरजई ने सीरीज के पहले मुकाबले में नाबाद अर्धशतक लगाया था। उनकी इस पारी के बाद ताजा टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडरों की रैंकिंग में उन्हें फायदा हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज में भारत शुरुआती दो मुकाबले जीत चुका है। इस प्रदर्शन का फायदा जहां भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग में मिला है, वहीं अफगानिस्तान के उमरजई ने भी अपने प्रदर्शन से सुधार किया है।ताजा आईसीसी रैंकिंग में वनडे में भी कई बदलाव हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी इसमें फायदा हुआ है।

पूर्व बार्सिलोना स्टार फिलिप कूटिन्हो दिसंबर तक सैंटोस एफसी से जुड़े

सैंटोस । ब्राजीलियाई क्लब सैंटोस एफसी ने लिवरपूल और बार्सिलोना के पूर्व प्लेमेकर फिलिप कूटिन्हो को 'फ्री ट्रांसफर' पर साइन किया है । क्लब ने मंगलवार को यह घोषणा की । 34 वर्षीय खिलाड़ी का यह कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर तक के लिए है । सैंटोस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अपनी बेहतरीन तकनीकी गुणवत्ता और दृष्टिकोण के साथ-साथ यूरोप और ब्राजीलियाई राष्ट्रीय टीम के साथ शानदार करियर वाला यह मिडफील्डर 2026 के अंत तक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ टीम में शामिल हो रहे हैं ।' फरवरी में मानसिक थकान का हवाला देते हुए 'वास्को दा गामा' से अलग होने के बाद कूटिन्हो किसी क्लब के साथ नहीं थे । कूटिन्हो के मुताबिक, उन्हें क्लब में लाने में उनके पुराने दोस्त नेमार ने अहम भूमिका निभाई है । दोनों ब्राजील के लिए यूथ और सीनियर दोनों स्तरों पर एक साथ खेल चुके हैं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2018 भी शामिल है । कूटिन्हो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'नेमार ने निश्चित रूप से मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । वह बचपन से ही मेरे दोस्त रहे हैं । जब मैंने वास्को दा गामा छोड़ा, तो फुटबॉल की दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही मुझे मैसेज किया था । उन्होंने कहा कि साथ खेलना अच्छा रहेगा, लेकिन उस समय मैं ऐसा नहीं कर सकता था, उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी ।

दूसरा टी20

कैटी मैक का तूफान

भारतीय टीम को 30 रन से मात देकर ऑस्ट्रेलिया-ए की सीरीज में अजेय बढ़त

न्यू चंडीगढ़। ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अनाधिकारिक टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को 30 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया-ए ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था। अब अंतिम मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। कैटी मैक और रेचल ट्रेनामन की जोड़ी ने मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 9 ओवरों में 75 रन की साझेदारी हुई।रेचल 25 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 37 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद कैटी ने चार्ली नॉट के साथ दूसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़े। चार्ली 20 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 26 रन बनाकर आउट हुईं। यहां से अनिका लीरॉयड ने कैटी के साथ तीसरे विकेट के लिए 65 रन जुटाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

कैटी 60 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में 11 चौके शामिल रहे, जबकि अनिका ने 16 गेंदों में 24 रन की नाबाद पारी खेली। भारत की तरफ से दोनों विकेट निकी प्रसाद के हाथ लगे।

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। टीम को 9 के स्कोर पर दिनेश वृंदा (1) के रूप में शुरुआती झटका लगा, जिसके बाद शिप्रा गिरी ने सुजाता के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 रन की साझेदारी की, लेकिन 29 के स्कोर तक सुजाता (8) के साथ शिप्रा (13) भी पवेलिन लौट गईं।

विमेंस टी20 रैंकिंग: 800 रेटिंग के साथ श्री चरणी ने

टी20 फॉर्मेट में इतिहास रचा

- दीप्ति चार पायदान ऊपर चढ़ीं

नई दिल्ली। श्री चरणी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह मंगलवार को जारी आईसीसी टी20 रैंकिंग में 800-रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गईं। यह उपलब्धि एशिया कप 2026 के फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली है। चरणी ने श्रीलंका के विरुद्ध खिताबी मुकाबले में सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट हासिल करते हुए पूरे टूर्नामेंट में कुल 12 विकेट चटकाए थे। अब चरणी की रेटिंग 804 है, जिससे शीर्ष पर उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। श्री चरणी यह आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज और कुल मिलाकर तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। महिला टी20 में गेंदबाजों के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शट के नाम है, जिन्होंने शीर्ष पर रहते हुए 806 रेटिंग हासिल की थी। श्री चरणी ने एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने का पूनम यादव का रिकॉर्ड तोड़ा था। वह टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 800 रेटिंग हासिल करने वाली तीसरी गेंदबाज हैं; उनसे पहले पूर्व नंबर 1 सोफी एक्लेस्टोन 802 रेटिंग तक पहुंच चुकी थीं।

एक तरफ, चरणी शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, तो दूसरी ओर स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उनकी जगह के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी हैं। दीप्ति ने एशिया कप फाइनल में 19 रन देकर 3 विकेट लिए और 14 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं। वह चार पायदान ऊपर चढ़कर 729 रेटिंग के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। हालांकि, हमवतन खिलाड़ी चरणी से काफी पीछे हैं।

फाइनल में मैच जिताऊ 68 रन की पारी खेलने के बाद शेफाली वर्मा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही, शेफाली टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑल-राउंडर्स की सूची में भी पांच स्थान ऊपर चढ़कर 15वें नंबर पर पहुंच गईं।

एशियन गेम्स : भारत की तैयारी पूरी, इस बार और भी मजबूत तैयारी

नई दिल्ली । एशियन गेम्स 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है । 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में भारत के 503 खिलाड़ी मेडल के लिए जोर लगाते हुए नजर आएंगे । भारत इस बार कुल 35 खेलों में हिस्सा लेने वाला है । हालांकि, कुछ खेल ऐसे हैं, जिनमें देश को मेडल जीतने की पूरी संभावना है । आइए ऐसे ही पांच खेलों के बारे में आपको बताते हैं । एथलेटिक्स: एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। इस खेल में भारत ने एशियन गेम्स के 19 संस्करण में अब तक कुल 85 गोल्ड, 102 सिल्वर और 96 ब्रॉन्ज समेत कुल 283 मेडल जीते हैं।

नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी के बावजूद, इस खेल में भारत को मुरली श्रीशंकर, गुलवीर सिंह, अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह, पारुल चौधरी, राजेश रमेश और रोहित यादव से मेडल की उम्मीद होगी। निशानेबाजी: एथलेटिक्स के बाद एशियन गेम्स के इतिहास में भारत को सबसे ज्यादा कामयाबी इसी खेल में मिली है। भारतीय खिलाड़ी हर बार की तरह इस बार भी निशानेबाजी में देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल दिलाने का प्रयास करेंगे। निशानेबाजी में भारत ने अब तक कुल 80 मेडल जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 30 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पिछले एशियन गेम्स में निशानेबाजी में भारत ने कुल 22 मेडल जीते थे। इस खेल में मनु भाकर को भारत की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था। मनु के अलावा, ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आशी चौकसे, सुरुचि से भी मेडल की आस होगी।

रेसलिंग: भारत को रेसलिंग से भी एशियन गेम्स 2026 में कई मेडल की उम्मीद होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रेसलिंग के खेल को शामिल नहीं किया था, ऐसे में भारतीय पहलवान एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन करने को बेकरार होंगे। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने इस खेल में अब तक कुल 65 मेडल जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे हैं। अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, दीपक पूनिया, मनीषा, सुजीत कलकल इस खेल में देश के लिए मेडल लाने की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे।

बॉक्सिंग: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने एशियन गेम्स 2026 के लिए नई उम्मीद जगा दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स गई भारतीय मुक्केबाजी टीम का हर सदस्य मेडल लेकर आया था। महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं, जदुमणि सिंह, सचिन सिवाच, अंकुश और नरेंद्र बेरवाल मेडल लाने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं।

क्रिकेट: एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। भारतीय मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम के मजबूत स्क्वॉड और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए इस खेल में मेडल पक्का माना जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं, पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी। पिछले एशियन गेम्स में भारत की पुरुष और महिला टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था।

स्नेक प्लांट, पीस लीली से लेकर तुलसी तक, ये 5 पौधे घर में लाएंगे पॉजिटिव एनर्जी और धन-समृद्धि

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में लगाए गए कुछ पौधे धन-समृद्धि बढ़ाने का काम भी करते हैं। मनी प्लांट, पीस लीली और तुलसी सहित कुछ पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी लाने के काम करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो घर की सुंदरता बढ़ाने के शांति और सुकून लाने का काम करते हैं।घर में पौधे लगाना सिर्फ घर को खूबसूरती का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये हमारे घर की एनर्जी के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इसमें से कुछ पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का काम करते हैं। ऐसे में पौधे लगाने से पहले ये जान ले कि ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा या नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित करेगा।

सुख-शांति और समृद्धि लाने वाले पौधे

वास्तु गुरु मान्या के अनुसार, पौधे लगाना घर को सुंदर बनाना नहीं होता बल्कि घर की ऊर्जा को संतुलित करना होता है। घर में लगाए गए सही पौधे सुख-शांति और समृद्धि लाने का एक बेहतरी जरिया बन सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 पौधों के बारे में जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं।

तुलसी का पौधा

इसे घर का संजीवनी कवच भी कहा जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाना वास्तु में बेहद ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। तुलसी का पौधा को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में घर में इसे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी के पौध के पास हमेशा साफ-सफाई रखें और इसकी बेल या सुख रहे पत्तों को समय पर साफ करते रहें।

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट को घर में लगाना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। इसे घर का एयर प्यूरीफायर भी कहा जाता है। स्नेक प्लांट घर में मौजूद टॉक्सिक एनर्जी को सोखने में माहिर माना जाता है। वास्तु गुरु मान्या बताती हैं कि इसकी नुकीली पत्तियों ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। घर की दक्षिण दिशा में इसे रखने से घर का माहौल शांत बना रहता है।

मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को धन और सुख-समृद्धि प्रदान करने वाला पौधा माना जाता है। अगर आपके घर में भी मनी प्लांट लगा है तो इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट की बेल हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़नी चाहिए। अगर इसके पत्ते जमीन को छूते हैं, तो माना जाता है कि आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती है। दक्षिण-पूर्व दिशा दिशा में इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

पीस लिली

पीस लिली को मानसिक शांति और सुकून देने वाला पौधा माना जाता है। ये पौधा घर के कलेश और दिमागी तनाव को दूर करने में मददगार साबित होता है। यह पौधा घर में छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे हमेशा कांच या सिरेमिक के सुंदर बर्तन में रखें और इसपर धूल मिट्टी जमाने न होने दें।

लकी बैम्बू प्लांट

घर में बैम्बू प्लांट लगाना शुभ और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना जाता है। दक्षिण-पूर्व दिशा में इसे रखने से आर्थिक लाभ होता है। वास्तु गुरु मान्या के मुताबिक, इसका पानी हर हफ्ते बदलना जरूरी होता है, ताकि रुकी हुई एनर्जी बिजनेस या करियर पर

क्या कहते आपके सितारे

मेष

मेष- आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। आपकी समस्याएं बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। आपको अपने कामों को लेकर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा, तभी आपके काम आसानी से पूरे होंगे। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको किसी की बातों में आने से बचना होगा।

वृषभ

वृषभ- आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको किसी की कोई बात बुरी लगने से आप जीवनसाथी से बेवजह उलझ सकते हैं। आपके सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो उसके भी पूरे होने की संभावना है।

मिथुन

मिथुन- आज का दिन आपके लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, जो आपको खुशी देगी। बिजनेस में भी आपकी कोई रुकी हुए डील फाइनल हो सकती है, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपके आसपास में आपका किसी बात को लेकर बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें।

कर्क

कर्क- आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आपका किसी नये घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। आपकी अपनी संपत्ति में इजाफा होने से आपको खुशी होगी। आपको किसी नई स्कीम का पता चल सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें, नहीं तो इससे कोई नुकसान होने की संभावना है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर आपको खुशी होगी।

सिंह

सिंह- आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा, तभी आपके काफी काम पूरे होंगे। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आ सकती हैं, जिस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आप लेनदेन से संबंधित मामलों में पूरा ध्यान दें और यदि आपने किसी अजनबी पर भरोसा किया, तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है।

कन्या

कन्या- आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसके लिए आप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आपकी कोई नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। जीवनसाथी को करियर में तरक्की करते देख आपको खुशी होगी।

तुला

तुला- आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपने कामों को लेकर भागदौड़ में लगे रहेंगे, तभी आपके काफी काम पूरे होंगे। परिवार के सदस्यों से आपकी खूब पटेगी, जिससे आपको यदि कोई समस्या भी आएगी, तो उसे भी आप आसानी से दूर कर सकेंगे। आप किसी अजनबी की बातों पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आपको किसी दूर रह रहे मित्र की याद सता सकती है, जिससे आप मिलने जा सकते हैं।

वृश्चिक

वृश्चिक- आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है। आपकी किसी बात को लेकर परिवार में सदस्यों से बेवजह बहसबाजी होने की संभावना है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था, तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आपको अपनी पारिवारिक मामलों पर पूरा ध्यान देना होगा।

धनु

धनु- आज का दिन आपके लिए लेनदेन से संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपकी आपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशियां रहेगा।

मकर

मकर- आज का दिन आपके लिए दीर्घकालिक योजना को गति दिलाने वाला रहेगा। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके बॉस कामों से बहुत खुश रहेंगे, जो आपके प्रमोशन की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, उसके भी पूरा होने की संभावना है।

कुंभ

कुंभ- आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार को संयम रखने के लिए रहेगा। आप किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले। लेनदेन से संबंधित मामलों में आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिसमें आप पुराने गिले शिकवे न उखाड़ें। संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपको किसी काम को लेकर कोई लोन आदि अप्लाई करना पड़ सकता है।

मीन

मीन- आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपनी शान शौकत पर पूरा ध्यान देंगे, जिसमें खर्चा भी खूब करेंगे। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पारिवारिक मामलों को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। आपको यदि कोई रोग लंबे समय से सता रहा था, तो उसमें भी आपके कष्ट बढ़ सकते है। आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी काम को लेकर आप अकस्मात यात्रा पर जा सकते हैं।

सुख-सुविधाओं से भरा जीवन, फिर भी मन अशांत क्यों, बुद्ध से समझें जीवन का सत्य

यदि कंचन, कामिनी और कीर्ति से ही सुख मिल जाता, तो गौतम बुद्ध या महावीर के पास इनमें क्या नहीं थे। गौतम को कपिलवस्तु का राज्य, यशोधरा जैसी रूपवती, गुणवती पत्नी, राहुल जैसा फूल सा सुन्दर पुत्र एवं महाराज शुद्धोदन की अर्जित अपार कीर्ति, फिर भी यशोधरा को सोया हुआ छोड़कर रात में महल से निकल गए और हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, 'जब तक दुःख का कारण और निदान नहीं पा लूंगा, कपिलवस्तु में प्रवेश नहीं करूंगा।'संसार जिसे प्राप्त करके प्रसन्न होता है, ज्ञानी उसी के पार जाने का मार्ग खोजता है। कंचन शरीर को सुख दे सकता है, कामिनी मन को आकर्षित कर सकती है और कीर्ति संसार में नाम दे सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी मृत्यु, मोह, भय और अंतहीन असंतोष से मुक्ति नहीं दे सकता।

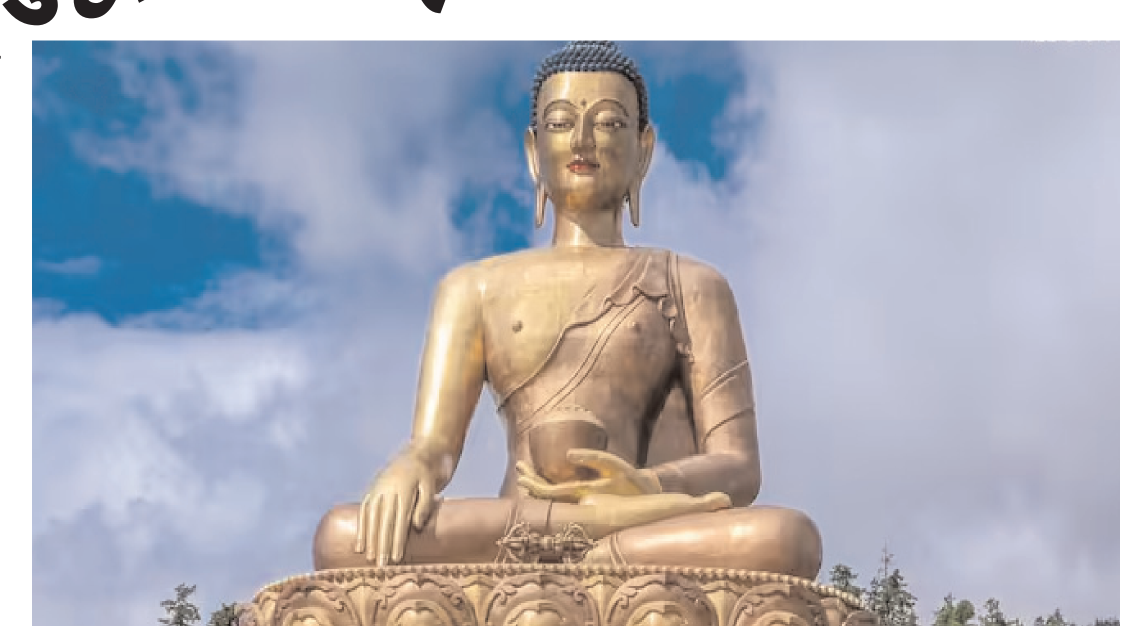

यदि कंचन, कामिनी और कीर्ति में ही जीवन का सच्चा सुख छिपा होता, तो फिर गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे राजकुमारों ने इन सबका त्याग क्यों किया होता। गौतम बुद्ध के पास कपिलवस्तु का राजपाट था, यशोधरा जैसी रूपवती और गुणवती पत्नी थीं, राहुल जैसा फूल-सा सुंदर पुत्र था और पिता महाराज शुद्धोदन की अर्जित हुई अपार प्रतिष्ठा भी थी। जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न लगातार उठता रहा, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है। एक रात वे यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर महल से निकल पड़े। उन्होंने अपने भीतर संकल्प लिया कि जब तक जीवन के दुःख का कारण और उसके निवारण का मार्ग नहीं खोज लेंगे, तब तक कपिलवस्तु वापस नहीं लौटेंगे।

धन आदि जीवन को सुख-सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन मन को स्थायी शांति नहीं दे सकते, वास्तविक सुख बाहर की वस्तुओं में न होकर भीतर के संतोष, और आत्मबोध में छिपा है। कंचन अर्थात धन-वैभव, कामिनी अर्थात सांसारिक प्रेम और आकर्षण तथा कीर्ति अर्थात यश-प्रतिष्ठा, ये तीनों मनुष्य को संसार में सुखी होने का भ्रम दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को वह शांति नहीं दे सकते।

सुख प्राप्ति का सम्भवतः एक दूसरा भी उपाय है, कि हम सुख और दुःख में संतुलित रहना सीखें। सुख प्राप्त करने के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। यह संसार एवं जीवन द्वंदात्मक है, सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति, जय-पराजय, लाभ-हानि, जन्म-मृत्यु, संयोग-वियोग आदि, यानि सृष्टि ही द्वंदात्मक है।

संक्षिप्त समाचार

गाजियाबाद राज्य कर विभाग में एडमिन आईडी का दुरुपयोग, कर्मचारियों की

एसीआर खराब

गाजियाबाद, एजेंसी। राज्य कर विभाग में मास्टर एडमिन (उपायुक्त प्रशासन) द्वारा मानव संपदा पोर्टल की आइडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कई अधिकारियों और कर्मचारियों के पासवर्ड रीसेट करने का मामला सामने आया है। आईडी का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रविष्टियों (एसीआर) को प्रतिकूल और संदिग्ध रूप से खराब कर दिया गया। इस मामले में तीन प्रधान सहायकों की पदोन्नति रूक गई है। इस मामले में मुख्यालय की ओर से उपायुक्त प्रशासन को हटाने के आदेश दिए गए हैं।

दिशा सालियान मामले में मेरे खिलाफ बदनामी अभियान एक राजनीतिक एजेंडा': आदित्य ठाकरे

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि वह दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान को नहीं जानते थे और न ही दिशा से कभी उनकी मुलाकात हुई थी. सीबीआई के दिशा सालियान की मौत के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि पीड़ित के पिता की शिकायत में आदित्य ठाकरे का नाम है. इस मामले में आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा है कि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले. दिशा सालियान केस के फिर से सुर्खियों में आने के बाद आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने पहले भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में इस केस का राजनीतिकरण करके उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है. एक ट्वीट में, आदित्य ठाकरे ने कहा, 'अफवाहों के भंवर को खत्म करने के लिए मैं एक बार फिर सिर्फ सच बता रहा हूं. मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही मैं उन्हें जानता हूं. आदित्य ने कहा कि पिछले छह सालों से कुछ लोग राजनीतिक मकसद से निजी दुश्मनी और उनके चरित्र को खराब करने के इरादे से जानबूझकर उनका नाम इस बुरी घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि इसका कोई सबूत या कनेक्शन नहीं है. आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह लगातार, झूठा कैंपेन, जिसमें कोई सच्चाई नहीं हैं, बुरी बात है. उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर कितनी भी जोरदार, झूठी बहस या मीडिया ट्रायल सच्चाई को नहीं बदल सकते. उन्होंने कहा कि आधिकारिक एजेंसियों को बिना किसी भेदभाव के जांच करने दिया जाए.

कर्नाटक में संदिग्ध नक्सली उप्पार वेंकटेश गिरफ्तार

तुमकुरु, एजेंसी। कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार रात तुमकुरु जिले में एक संदिग्ध नक्सली उप्पर वेंकटेश को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि वह नक्सली गतिविधियों में शामिल था और गांववालों को डराता-धमकाता था. तुमकुरु के पावगड़ा तालुक के कनकलाबेंडे गांव का रहने वाला वेंकटेश, पावगड़ा के कनकलाबेंडे इलाके में कदमालकुंटे पहाड़ी के पास एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान रात करीब 11 बजे पकड़ा गया. अधिकारियों ने बताया कि वह अर्धनग्न हालत में मिला. पुलिस ने बताया कि वह इस दौरान शराब पी रहा था और चिकन खा रहा था. पुलिस के मुताबिक, वेंकटेश पिछले कुछ महीनों से कनकलाबेंडे गांव के लोगों को परेशान कर रहा था और डरा रहा था. जब पुलिस पहले गांव गई थी तो वह एक पहाड़ी पर देसी बम फोड़कर भाग फरार हो गया था. 29 अगस्त को, उसने कथित तौर पर करियान्ना नाम के एक किसान के पंप सेट पर देसी बम लगाकर उसे मारने की कोशिश की थी.

पंजाब के सरकारी स्कूलों की अब सोशल मीडिया पर भी होगी पहचान, उपलब्धियों और गतिविधियों को करना होगा शेयर

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के सरकारी स्कूलों की गतिविधियां और उपलब्धियां अब इंटरनेट मीडिया के जरिये भी लोगों तक पहुंचेंगी। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को कम से कम एक इंटरनेट मीडिया मंच पर आधिकारिक और सक्रिय खाता बनाने के निर्देश दिए हैं।

स्कूलों को 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक या इंस्टाग्राम में से किसी एक मंच पर आधिकारिक खाता बनाकर उसे सक्रिय रखना होगा। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में होने वाली सकारात्मक गतिविधियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपलब्धियों तथा नवाचारी शिक्षण कार्यों को व्यापक स्तर पर सामने लाना है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिन सरकारी स्कूलों के पहले से आधिकारिक इंटरनेट मीडिया खाते हैं, उन्हें निर्धारित वेब प्रपत्र के माध्यम से इन खातों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। वहीं, जिन स्कूलों के पास अभी

तक कोई आधिकारिक इंटरनेट मीडिया खाता नहीं है, उन्हें 'एक्स', फेसबुक या इंस्टाग्राम में से किसी एक मंच पर खाता बनाना होगा। खाते की जानकारी एमस्टार पोर्टल के माध्यम से दर्ज करनी होगी। स्कूल की सकारात्मक गतिविधियों की देनी होगी जानकारी विभाग ने स्कूल प्रमुखों को इंटरनेट मीडिया खातों पर स्कूल की सकारात्मक पहलों और महत्वपूर्ण गतिविधियों की नियमित जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं।

इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियां, शिक्षकों की उपलब्धियां, कक्षा में अपनाई जा रही नवाचारी शिक्षण गतिविधियां, स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की ओर से किए जा रहे कार्य तथा स्कूल में आयोजित होने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल से अभिभावकों और आम लोगों को सरकारी स्कूलों में हो रहे कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपलब्धियों को भी सार्वजनिक मंच मिल सकेगा।

इंटरनेट मीडिया खाते बनाने के साथ शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के रिकार्ड को एमस्टार एप पर अद्यतन करने के भी निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रमुखों को प्रत्येक विद्यार्थी का पूरा आवासीय पता जांचकर अपडेट करने को कहा गया है। इसके अलावा जहां उपलब्ध हों, वहां विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावकों दोनों के मोबाइल नंबरों का सत्यापन कर उन्हें रिकार्ड में दर्ज करना होगा। विभाग ने यह प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश जारी किए थे।

कैंटर के शीशे बंद कर सो रहा था ड्राइवर, दम घुटने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। कासना कोतवाली क्षेत्र में कैंटर के केबिन में सोए चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने दम घुटने से चालक की मौत होने का दावा किया है। कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण कैंटर के शीशे और दरवाजे बंद कर सोने के दौरान दम घुटना माना जा रहा है। मृतक की पहचान पवन शर्मा (37) निवासी ऐचोरा, थाना अनूपशहर, बुलंदशहर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सुबह डायल-112 पर सूचना मिली कि ग्राम लडपुरा में खड़े कैंटर में एक व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो कैंटर के दरवाजे अंदर से लॉक थे। किसी तरह लॉक खोल कर उसे बाहर निकाला गया, उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। जांच में पता चला कि पवन अलीगढ़ से गाजीपुर मंडी में आलू की सप्लाई के लिए रवाना हुआ था।

गोरखपुर-प्रयागराज में चुनावी रणनीति को धार देंगे तावड़े, पूर्वांचल की हारी हुई सीटों की होगी समीक्षा

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र में राजनीतिक सेनाएं मोर्चा संभालने लगी हैं। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रभावी नैरेटिव गढ़कर चुनावी अस्त्र को धार देने में जुटी है।

वहीं भाजपा एक साथ तीन मोर्चों (अभियान, संगठनात्मक समीक्षा एवं छह क्षेत्रों में संघ के साथ समन्वय बैठकों) के सहारे चुनावी रथ हांक रही है। वहीं, पार्टी पर सहयोगी दलों को अपने पाले में रखने का दबाव है। दो बार लखनऊ और एक बार कानपुर में मैराथन मंथन करने के बाद अब प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े 17 और 18 सितंबर को गोरक्ष क्षेत्र में डेरा डालेंगे, वहीं 21 से 23 सितंबर तक प्रयागराज मथेंगे। भाजपा की रणनीति के मुताबिक राष्ट्रीय

संगठन महामंत्री बीएल संतोष और विनोद तावड़े एक माह की कसरत में सभी प्रशासनिक मंडलों एवं पार्टी की दृष्टि से गठित क्लस्टरों की समीक्षा कर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे देंगे। इन बैठकों में बूथों का राजनीतिक प्रबंधन भी परखा जाएगा। बूथों पर जुटाए गए राजनीतिक समीकरणों एवं प्रभावी जातियों की समीक्षा होगी। गोरखपुर एवं प्रयागराज क्षेत्र में होने वाली बैठकों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर वर्ष 2022 एवं 2024 के चुनाव में भाजपा कई सीटों पर हारी या संघर्ष करती नजर आई। यहां का राजनीतिक गणित पहले सपा और बसपा के साथ रहा है, लेकिन 2014 से यह भाजपा के पाले में झुकता नजर आया। पिछले विधान सभा में भाजपा को झटका लगा। पार्टी नहीं संभली तो 2024 लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। गोरक्ष एवं प्रयाग के आसपास की सीटों पर कुर्मी, निषाद, राजभर, मौर्य, केवट, मल्लाह, प्रजापति समेत आधा दर्जन ओबीसी जातियों की बड़ी संख्या है। कई सीटों पर सवर्णों में आपसी द्वंद भाजपा के लिए चिंता का सबब बन रहा है। भले ही तावड़े बिहार का चुनावी तानाबाना समझकर प्रभाव छोड़ने में सफल रहे, लेकिन यूपी की राजनीतिक चाल कई मायनों में बिहार से अलग है। अगर वह बड़ी संख्या में टिकट बदलने के संकल्प के साथ यूपी आए हैं तो पहले यहां का वातावरण समझना होगा।

कोटा में बुजुर्ग बाघिन महक की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सक्रियता पर होगा अध्ययन

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में कोटा जिले के अभेड़ा बायोलाजिकल पार्क की बुजुर्ग बाघिन 'महक' की 23 वर्ष लंबी उम्र के बावजूद उसकी सक्रियता और स्वास्थ्य के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानकारी हासिल करने को लेकर अध्ययन किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (डब्लयूआइआइ) के विज्ञानी और राज्य सरकार के वन विशेषज्ञ इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन में इस बाघिन की जेनेटिक संरचना, डीएनए, शरीर में चलने वाली प्रक्रियाओं वैक्सीनेशन, खान-पान और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा।

साथ ही यह जानने का भी प्रयास होगा कि क्या महक के शरीर में कोई विशेष जीन मौजूद है, जिसके कारण से बढ़ती उम्र के बावजूद महक बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों से बची हुई है। आमतौर पर बाघ-बाघिना की उम्र 18 साल के आसपास होती है। जंगल में शिकार, दूसरे जानवरों से संघर्ष सहित कई कारणों से इनकी उम्र कम भी हो सकती है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, महक का जन्म 28 अगस्त 2004 को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क में हुआ था। उसे वहां से वर्ष 2012 में अभेड़ा बायोलाजिकल पार्क लाया गया था।

ईरान में हिजाब नियमों पर थम रही सख्ती?: बिना सिर ढके निकल रहीं महिलाएं, कट्टरपंथी चाह रहे कार्रवाई

दुबई, एजेंसी। ईरान की राजधानी तेहरान में महिलाएं बिना सिर ढके खुले कैफे में बैठ रही हैं और छोटे टॉप पहन रही हैं। पार्कों में पुरुष शॉर्ट्स और महिलाएं लेगिंग पहनकर साथ में व्यायाम कर रही हैं। सड़क किनारे होने वाले संगीत कार्यक्रमों में महिलाएं नाचती दिखाई दे रही हैं और खुले बालों के साथ नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए तेहरान के इन दृश्यों से पता चलता है कि इस्लामी गणराज्य में सामाजिक पाबंदियों को लागू करने में हाल के वर्षों में काफी ढील आई है। 16 सितंबर 2022 को 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन हैं। अमीनी को कथित तौर पर सही तरीके से सिर पर स्कार्फ नहीं पहनने के आरोप में नैतिकता पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया था। इस कार्रवाई में 500 से अधिक लोग मारे गए और हजारों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, शांति बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने महिलाओं के हिजाब और शालीन कपड़ों से जुड़े नियमों को लागू करने में पीछे हटना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस ढील को फिर से खत्म किया जा सकता है। ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान में कट्टरपंथी नेता महिलाओं के पहनावे पर फिर सख्ती की मांग कर रहे हैं। लेकिन शीर्ष नेता ऐसे समय में जनता की नाराजगी भड़काने से बचने की चेतावनी दे रहे हैं, जब युद्ध, अमेरिका के हमलों, प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी के कारण पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के ससुर और राजनेता गुलाम अली हद्दाद आदेल ने पिछले सप्ताह हिजाब को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी में कहा, 'युद्ध की परिस्थितियों के कारण हम उस मोर्चे में उस तरह प्रवेश नहीं कर सकते, जिस तरह हमें करना चाहिए।' तेहरान में रहने वाली कार्यकर्ता और पूर्व राजनीतिक कैदी पूरन नाजेमी ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद हिजाब को लेकर मतभेद और गंभीर हो गए हैं। उन्होंने फोन पर कहा, 'वे प्रदर्शनों से डरते हैं।' राजधानी के एक समृद्ध उत्तरी इलाके में रहने वाली 20 साल के शुरुआती दशक की एक विश्वविद्यालय छात्रा ने बताया कि वह सिर पर स्कार्फ नहीं पहनती, लेकिन ऐसे कपड़े पहनती है जो उसके हाथ और पैर का अधिकांश हिस्सा ढकते हैं। उसने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं।'

रूस पर शिकंजा कसने वाला बिल अमेरिकी संसद से पास

भारत-चीन पर 100 तक टैरिफ का खतरा

मास्को, एजेंसी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को रूस और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने वाले एक बड़े विधेयक को मंजूरी दे दी। 262 सांसदों ने इसके पक्ष में और 159 ने विरोध में मतदान किया। 61 पन्नों वाले इस विधेयक को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। यह विधेयक पिछले महीने अमेरिकी सीनेट में भी 86-11 वोटों से पारित हो चुका है। इसका नाम लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 रखा गया है। यह नाम जुलाई में अप्रत्याशित रूप से दिवंगत हुए सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में रखा गया है, जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के प्रमुख समर्थकों में रहे थे। विधेयक का सबसे अहम निशाना रूस का ऊर्जा क्षेत्र है। इसका मकसद रूस से तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर आर्थिक दबाव बनाकर उसकी ऊर्जा से होने वाली कमाई घटाना है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले तीसरे देशों के सामान पर शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है। इनमें चीन और भारत जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों का घोषित उद्देश्य रूस की उन आय के स्रोतों को कम करना है, जिनसे यूक्रेन के खिलाफ 2022 से जारी युद्ध को फंड किया जा रहा है। राष्ट्रपति को रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदने वाले तीसरे देशों पर 100 फीसदी तक शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है.सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार, यह प्रावधान 2025 के विधेयक में प्रस्तावित 500 फीसदी शुल्क के मुकाबले अधिक सीमित है। रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15 फीसदी से कम आयात करने वाले और रूसी ऊर्जा पर निर्भरता घटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले देशों के लिए छूट का प्रावधान है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार, चीन अगर रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो उसके सामान पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर 100 फीसदी तक शुल्क लगाया जा सकता है। ट्रंप के अनुरोध पर विधेयक में ईरान के हथियार और ऊर्जा क्षेत्रों की फंडिंग कम करने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाने के अधिकार को भी बढ़ाया गया है। भारत पर अभी 100 फीसदी शुल्क नहीं लगाया गया है। विधेयक राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अनुसार ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

ट्रंप की युद्ध नीति पर संसद में संग्रामः ईरान पर सांसदों का शिकंजा, इस्राइल को बम देने पर रोक

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की इस्राइल को 2.8 अरब डॉलर के भारी हथियार बेचने की योजना पर सवाल उठ गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में शीर्ष डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। न्यूयॉर्क से सांसद मीक्स ने बुधवार को कहा कि उन्हें गंभीर और अभी तक दूर नहीं हुई चिंताएं हैं कि इन शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल गाजा और लेबनान के घनी आबादी वाले इलाकों में कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'ट्रंप प्रशासन ने पर्याप्त भरोसा नहीं दिलाया है कि नेतन्याहू सरकार इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी कानून के मुताबिक और आम नागरिकों की उचित सुरक्षा के साथ करेगी।

किराए के लिए खाली है
1- 3600 वर्ग फुट कमर्शियल 4 हॉल सेमी फर्निश्ड सेक्टर 10 टी सी सी काम्प्लेक्स फरीदाबाद में।
2- 1620 वर्ग फुट ऑफिस सेमी फर्निश्ड मेन रोड सेक्टर 10 टी सी सी काम्प्लेक्स फरीदाबाद में।
3- टू बैड रूम सेट ग्राउंड फ्लोर वेल फर्निश्ड सेक्टर 7 डी ब्लॉक फरीदाबाद में।
4- वन रूम सेट वेल फर्निश्ड सेकंड फ्लोर सेक्टर 7 डी ब्लॉक फरीदाबाद में।
इच्छुक व्यक्ति फोन नंबर 9999446252, 9811157562 पर संपर्क करें।

- सूचना -
फरीदाबाद जिला में भेदीनजर समाचार में अपने समाचार, विज्ञापन देने और अखबार की कापी प्राप्त करने के लिये सम्पर्क करें-
1-
मोबाइल नम्बर- 9811477204
2-
मोबाइल - 9810229192
3-
मोबाइल- 9811159238

छोटा विज्ञापन बड़ा फायदा
आज ही स्पेस बुक कराएं-काल करें
0120-4152063,
9811157562

नई एवं तरोताजा खबरों के लिए भेदी नजर पढ़िए, समय के साथ चलिए
सुनहरा मौका वार्षिक ग्राहक बनिए और
वीआईपी एल्फा सूटकेस कीमत रु, 900 प्राप्त करिए
भेदी नजर समाचार पत्र के ग्राहक बनें
मात्र 700 रूपये दीजिए और वार्षिक ग्राहक बनने के अलावा तुरंत पाइए
और अन्य आकर्षक उपहार के लिए
बम्पर ड्रा
पहला इनाम

एक हीरो बाईक
दूसरा इनाम

एक सोनी एलसीडी 32 इंच व अन्य आकर्षक ईनाम
तीसरा इनाम

बीस मोबाईल फोन
- कोई भी व्यक्ति एजेंट 500 से अधिक मेंबर बना लेगा तो उसे अलग से उपहार दिया जाएगा।
- ये स्कीम एक जनवरी 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक चलेगी।
- 31 दिसम्बर 2026 को 1000 सदस्य बनाने पर बम्पर ड्रा निकाला जाएगा जिसमें उपरोक्त इनाम हरियाणा के किसी भी मंत्री द्वारा दिए जाएंगे।
- ड्रा बम्पर ड्रा में भेदी नजर के वार्षिक मेम्बर ही भाग ले सकते हैं।
- भेदी नजर प्रत्येक माह की पहली तारिख को कूपन छापेगा।

आर.एन.आई. नं.
DEL/HIN/2004/13528
प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी एवं संपादक उमा शर्मा द्वारा
उमा पब्लिकेशनस्
1001/1002 दसवां तल नौरंग हाऊस, 21 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -1 से प्रकाशित
एवं नीलू प्रिंटिंग प्रेस ई-33 सेक्टर -7 नोएडा से मुद्रित
संपादक
उमा शर्मा
प्रधान संपादक
गिरीश चन्द्र शर्मा
फोन नं. -
011-66304689
0120-4189808
0129-2290152
0129-2267 07 8
0129-2977562
फैक्स नं. -
011-66304690
0129-2297 640
मो. : 9811157 562,

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र फरीदाबाद होगा ।
पीआईबी एक्ट अनुसार सभी विवादित समाचारों की ज़िम्मेदारी समाचार लेखक की होगी भेदीनज़र संस्थान ,संपादक और प्रधान संपादक क़ानूनन ज़िम्मेदार नहीं होगा